सूर्योदय 5:58 सूर्यास्त 6:42

आज का तापमान

शिमला	15.6 न्यू	21.8 अधि
धर्मशाला	13.8 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,570
निफ्टी	23,914

सोना 1,51,000 चांदी 2,28,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 3 सितंबर 2026 | 18 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 129, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा

ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान के लीडर थे; गोविंद देव गिरि बने महासचिव

एजेंसी, अयोध्या। पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ होंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार को इसका ऐलान किया। मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया और एयरफोर्स में 39 साल काम किया।

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को नया महासचिव बनाया गया है। बैठक में ट्रस्टी बनाए गए महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष का चार्ज दिया गया। नए सीईओ और कोषाध्यक्ष महासचिव गोविंद देव गिरि को ही रिपोर्ट करेंगे। ट्रस्ट में दिल्ली के महेश भागचंदका समेत 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। इनमें अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और आरएसएस समर्थक शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं। निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी होंगी। यह बदलाव मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामला सामने आने के 3 महीने के बाद हुआ। इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं। इसके बाद 2 जुलाई को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया था। वह 58 दिनों तक पद पर रहे।

5538 लोगों के आवेदन आए थे, सर्वसम्मति से जीतेंद्र मिश्रा को चुना गया : कृष्ण मोहन

अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया राम मंदिर सीईओ के लिए 5,538 लोगों ने अप्लाई किया था। 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में 16 लोगों के इंटरव्यू हुए। इनमें एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा, मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह और श्रुति भारद्वाज के नाम सिलेक्ट किए गए। जितेंद्र मिश्रा का नाम सर्वसम्मति से फाइनल किया गया।

मंदिर ट्रस्ट के पास 1876 करोड़ कैश

6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मंदिर को कितना चढ़ावा मिला, उसे कहां खर्च किया गया, इसका ब्योरा रखा गया। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में खाते हैं। इनमें 1876 करोड़ रुपए जमा हैं। मंदिर निर्माण के समय समर्पण निधि 3264 करोड़ रुपए मिली थी। मंदिर के चढ़ावे में 582 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर और 391 करोड़ रुपए मैनेजमेंट पर खर्च किए गए।

न्यूज शॉर्ट्स

कर्नाटक के सीएम बोले सीता का चरित्र राम से बड़ा

एजेंसी, बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि रामायण में सीता का चरित्र भगवान राम से कहीं बड़ा है। वे बेंगलुरु में उबंटू कंसोर्टियम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित 'टुगेदर वी ग्रो इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डे' के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। शिवकुमार ने महिला उद्यमियों से राज्य के विकास में नेतृत्व की भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं निर्माण करती हैं। उन्हें संसद तक नेतृत्व संभालना चाहिए। सरकार पूरा साथ देगी। शिवकुमार ने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं का नेतृत्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन बैन, पांच रुपए में जमा होगा फोन

एजेंसी, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा। इसके लिए हर फोन पर 5 रुपए चार्ज देना होगा। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत वीआईपी, बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों की फोटो या वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मंत्री रमेश ने यह जानकारी दी। यह फैसला 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं द्वारा फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही थीं।

आंध्र प्रदेश में एंटी-मलेरिया दवा से बच्ची की मौत, 52 लोग अस्पताल में भर्ती

एजेंसी, पोलावरम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले के गोल्लागुप्पा गांव में एंटी-मलेरिया दवा खाने के बाद एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की पहचान मदिवी जमुना के रूप में हुई है। वहीं, 52 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया की रोकथाम के लिए गांव में मेडिकल कैंन लगाया था। इसके बाद 71 लोगों को क्लोरोक्वीन की टेबलेट बांटी गई थीं। दवा लेने के बाद कुछ बच्चों और ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने जैसी दिक्कतें होने लगीं थी। शुरुआत में कुछ मरीजों को लक्ष्मीपुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कुछ को तेलंगाना के भद्राचलम एरिया अस्पताल ले जाया गया। जिला प्रशासन ने गांव में मेडिकल कैंप लगाया है और डॉक्टरों की टीम तैनात की है। काकीनाडा से 9 सदस्यीय टीम भी गांव पहुंची है, जबकि विजयवाड़ा, राजामहेंद्रवरम और काकीनाडा से तीन और टीमें भेजी गई हैं।

नेपाली पीएम संसद में बोले- भारत को धन्यवाद

कहा- सही समय पर पड़ोसी देशों ने मदद पहुंचाई; 7 दिन में 1127 की मौत

एजेंसी, काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ राहत व बचाव कार्यों में मदद के लिए संसद में भारत और चीन को धन्यवाद दिया। बुधवार को संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों ने समय पर राहत सामग्री, तकनीकी टीमें और आपात मदद भेजी।

भारत ने राहत सामग्री की पांचवीं खेप भेजी है। भारतीय टीमें सुरंगों में सर्च ऑपरेशन और शवों की पहचान में मदद कर रही हैं। वहीं, चीन ने ग्यिरोंग बॉर्डर तक जाने वाला हाईवे खोल दिया है, जिससे राहत दल प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं। बाढ़ में अब तक 1127 लोगों की मौत हो चुकी है और 4800 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के कर्मचारी भी गायब हैं। आशंका है कि कुछ लोग अब भी सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में बताया कि बाढ़ के बाद अब तक 95 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। शाह ने कहा कि बाढ़ 26 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे आई थी।

जानकारी मिलते ही सरकार ने राहत-बचाव अभियान शुरू किया। 9:15 बजे आपात बैठक बुलाई गई और 10:30 बजे तक हेलिकॉप्टर व बचाव दल तैनाती के लिए तैयार थे। नेपाल में बाढ़ और लगातार बारिश के बाद सुन कोशी, बूढ़ी गंडकी और महाकाली नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने मध्य, पश्चिमी और पूर्वी नेपाल के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है, और तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है।

4 दिन मलबे में दबा रहा 5 साल का बच्चा, जिंदा बचाया

नेपाल में बाढ़ के मलबे में चार दिन तक दबे रहने के बाद एक 5 साल के बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। बचाव के बाद बच्चा इतना थका हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। एक वीडियो में नेपाल सेना का जवान बच्चे को खिचड़ी और पानी पिलाता नजर आया। जवान ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह जल्द अपने परिवार से मिलेगा और फिर स्कूल जा सकेगा।

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र को राहत नहीं, पुराने आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमी लेयर के मामले में केंद्र सरकार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर अपने पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों को 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर मामले में उच्चतम न्यायालय से 11 मार्च के फैसले को पिछली तारीख से लागू न करने और इसे लागू करने के लिए दो साल का समय देने की मांग की है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले का असर सरकारी नौकरियों, सर्विस और कैंसर आवंटन, सीनियरिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला और 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर पड़ सकता है।

करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 505 नए बेड जुड़ेंगे : मुख्यमंत्री नायब सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर, आधुनिक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सचिवालय में स्टेट फाइनेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फेज-II विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थी। फेज-II के तहत अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं और क्षमता में बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इससे करनाल सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हर वर्ष 120 एमबीबीएस विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है तथा 64 पीजी सीटें हैं।

अस्पताल में करीब 600 बेड की क्षमता है। फेज-II के तहत अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए 404.95 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट एवं बर्न वार्ड, आईसीयू, आईसीसीयू, जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और मनोरोग विभाग से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा हेलिपैड तथा अन्य जरूरी सहयोगी एवं सहायक सुविधाओं का भी प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित विस्तार के तहत अस्पताल में करीब 505 नए बेड जोड़े जाएंगे। इससे अस्पताल की कुल बेड क्षमता लगभग 600 से बढ़कर 1100 बेड हो जाएगी।

मप्र में बस-बल्कर की भिड़ंत, तीन की मौत

एजेंसी, रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर बुधवार शाम तेज रफ्तार बल्कर ने यात्रियों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल हो गए, जिनमें आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, हादसा गुढ़ थाना क्षेत्र में बदवार बस स्टैंड के पास बुधवार शाम करीब 5 बजे हुआ। रीवा से सीधी जा रही बघोर ट्रैवल्स की बस को बल्कर ने पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद बल्कर पलट गया, जबकि बस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

2 दिन बाद अमेरिका का ईरान पर फिर मिसाइल हमला; 12 की मौत, 68 घायल

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका ने 2 दिन बाद फिर ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात सिरिक, खुजस्तान, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की। ईरान के अनुसार इन हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 68 लोग घायल हुए हैं।

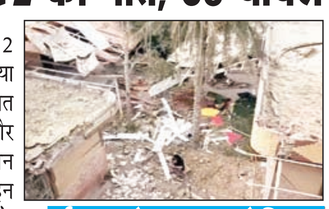

ईरान का दावा है कि सिरिक में एक शादी समारोह के दौरान मिसाइल गिरने से 5 लोगों की जान गई, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं, खुजस्तान प्रांत में हुए हमले में 7 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हुए। अमेरिका का कहना है कि उसने केवल ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक करने का दावा किया है। इससे पहले 30 अगस्त को अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित लारक द्वीप पर दो ईरानी रॉकेट लॉन्चरों पर हवाई हमला किया था।

ईरान बोला - अमेरिका की बुनियाद हिला देंगे

ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी हमलों के बाद कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान की नई रणनीति अमेरिका की 'बुनियाद हिला देगी'। रेजाई ने एक्स पर लिखा कि ईरान सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीति और आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए भी नई रणनीति अपनाएगा।

सीएम रेखा ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं त्वरित व समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से सीधे संवाद किया।

उन्होंने एक-एक कर नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को मामलों की गंभीरता के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दरवाजा जनता के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। नागरिक अपनी समस्या लेकर सीधे सरकार तक पहुंचें, उनकी बात संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए और उन्हें समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यही वर्तमान की दिल्ली सरकार की कार्यसंस्कृति है। जनसुनवाई के दौरान शिक्षा, लंबित पुरस्कार राशि, जलभराव, सीवर, बिजली सुरक्षा, सफाई, अवैध निर्माण एवं कनेक्शन सहित विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गईं। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच, आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने तथा लंबे समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने पर जोर दिया। जनसुनवाई में कुछ नागरिकों ने यह भी बताया कि वे पूर्व में संबंधित विभागों के समक्ष शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन लंबे समय के बावजूद समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाए और जहां भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल नागरिकों की शिकायत सुनना नहीं, बल्कि शिकायत को समाधान तक पहुंचाना है।

सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा मौत मामले की सीबीआई करेगी जांच

एजेंसी, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। यह फैसला दिशा के पिता की उस याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी। इसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। दिशा मामले की शुरुआती जांच करीब तीन महीने में बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में सामने आए विभिन्न दावों के बाद 2023 में जांच दोबारा शुरू की गई और एसआईटी गठित की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया है।

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग व बलिदान को मुख्यमंत्री धामी ने किया नमन

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मसूरी गोलीकांड में बलिदान हुए राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान उत्तराखंड की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा।

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान से उत्तराखंड राज्य गठन का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मसूरी में शहीद स्थल झूलाघर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मसूरी की धरती उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की साक्षी रही है। वर्ष 1994 में हजारों आंदोलनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उनके मन में आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का सपना था। धामी ने कहा कि नई पीढ़ी को राज्य निर्माण के संघर्ष और आंदोलनकारियों के बलिदान से परिचित कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही और माताओं-बहनों ने अपने संघर्ष एवं सहभागिता से आंदोलन को मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव के आधार हैं। राज्य सरकार ने उनके सम्मान और कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके दायरे में चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार 98 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है।

◆ मसूरी गोलीकांड के शहीदों का बलिदान सदैव रहेगा अमर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन छह हजार से बढ़ाकर सात हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है। पूर्णतः शय्याग्रस्त दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा तथा उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

उप्र आउटसोर्स सेवा निगम का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ किया, अब आउटसोर्स कर्मियों का शोषण नहीं होगा। संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण के लिए यूपीसीओएस का शुभारंभ और उसके पोर्टल व वेबसाइट की लांचिंग के अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को डेमो चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार में सैफई सिंडिकट खून चूसने का काम करता था। अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा। कोई शोषण नहीं कर सकेगा। योगी ने कहा कि हमारा मानना है कि उप्र की विकास यात्रा पिछले साढ़े नौ वर्षों में जो तय की है, वह उन्हीं कार्मिकों के प्रयासों से संभव हो सका है। इसमें शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप सम्मान भी प्राप्त हो। उप्र आउट सोर्स सेवा निगम उसी गरिमा को स्थापित करने का सरकार का प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। पहले यह व्यवस्था तीन खेमों में बटा होता था। कार्मिक, एजेंसी और सरकार होती थी। अक्सर कर्मचारी को अलग-अलग दरवाजों पर जाना पड़ता था, जब कोई समस्या आती थी तो उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहता था। सरकार और कर्मचारी का केवल वेतन और ड्यूटी का रिश्ताहो नहीं हो सकता। विश्वास का रिश्ता होता है। कर्मचारी को महसूस होना चाहिए कि उसके बेहतर कार्य का रिकार्ड रखा जा रहा है। उसकी समस्या सुनने का एक तंत्र है। वह अकेला नहीं है।

◆ बोले- आउटसोर्स कर्मियों का वेतन, पीएफ और बीमा रहेगा सुरक्षित

उसका वेतन समय से मिले, भविष्य निधि और बीमा सुरक्षित रहे। आउटसोर्स कर्मी को उसकी मेहनत के अनुरूप वेतन मिले। उसके श्रम का सम्मान हो। पहले यही नहीं होता था।

विधानसभा हिमाचल में रोपवे सरकार की प्राथमिकता, एफसीए मंजूरी में तेजी से रोपवे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

अनछुए पर्यटन क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ना सरकार का लक्ष्य : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान रोपवे निर्माण का मुद्दा गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं की स्थिति, इनकी लागत, निजी निवेश और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सवाल किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में रोपवे सरकार की प्राथमिकता में हैं, लेकिन इनकी लागत बहुत अधिक होने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पीपीपी और ईएपी मोड पर रोपवे बनाने के लिए तैयार है और निजी निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शिमला में रोपवे लगाने की योजना पर भी काम करने की कोशिश की गई थी। टेंडर के आकलन में इसकी लागत करीब 2,700 करोड़ रुपए आई। अधिक लागत के कारण इस परियोजना पर फैसला नहीं हो सका व इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में पीपीपी और ईएपी मोड पर जाने की बात रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे की ट्राली खाली चलने की स्थिति में भी तीन-चार यात्रियों के खर्च का भार सरकार को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है, जिसमें रोपवे के पीपीपी मोड की अवधि 30 से 35 साल तक सीमित की जा सके। उन्होंने रोपवे निर्माण में निजी निवेशकों से हिमाचल में आने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार उनका स्वागत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब 1,200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है और निजी निवेशकों को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि रोपवे के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए, जहां अभी पहुंच सीमित है। पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पर्यटन के लिहाज से खूबसूरत प्रदेश है और रोपवे के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जा सकती है।

निजी निवेशकों से रोपवे परियोजनाएं आगे बढ़ाने को सरकार तैयार

चुराह के विधायक हंसराज ने चंबा में प्रस्तावित तीन रोपवे परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या इन तीनों परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं के प्रस्तावों में कई पहलुओं को देखना पड़ता है। कई मामलों में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू करने की बात होती है। उन्होंने कहा कि रोपवे सरकार की प्राथमिकता में हैं, लेकिन केवल अध्ययन के लिए पैसा खर्च करना सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी निवेशक आते हैं तो सरकार उनका स्वागत करेगी और उन्हें जमीन उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है, जहां वे होटल बना सकें। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमानी चामुंडा रोपवे की स्थिति को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार क्योरी से बिलिंग को जोड़ने वाली योजना पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उषा कंपनी ने शिमला और हिमानी चामुंडा दोनों परियोजनाएं ली थीं, लेकिन चार साल तक मामला चलता रहा और कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निजी निवेशक अपना पैसा लगाकर रोपवे बनाए, सरकार ऐसे निवेशकों का खुले मन से स्वागत करेगी।

शिमला

भारतेन्दु शिखर

हर वर्ग के कल्याण पर सुक्खू सरकार का जोर, योजनाओं से मिलेगी राहत

गरीब परिवारों से विद्यार्थियों तक, सरकार की योजनाओं से मिलेगा व्यापक लाभ

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं और उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

दो लाख अतिनिर्धन परिवारों को राहत : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 अक्तूबर से मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के करीब दो लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें

करीब 90 हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

विद्यार्थियों के लिए सस्ती शिक्षा ऋण सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है। योजना के तहत विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने योजना की पारिवारिक आय सीमा चार लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है, जिससे अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य धन की कमी के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई न रुके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है।

बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव के.के. पंत, राजपूत कल्याण बोर्ड के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य, प्रशासनिक सचिव तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया।

कसौली में जायका की सिंचाई योजनाओं की होगी जांच

जायका योजनाओं में खामी मिली तो होगी जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कसौली विधानसभा क्षेत्र में जायका परियोजना के तहत चल रही छह सिंचाई योजनाओं को लेकर सवाल उठा। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने इन योजनाओं में कार्यों की गुणवत्ता, समानांतर योजनाओं के संचालन और धन के संभावित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि योजनाओं के कार्यों में किसी प्रकार की कमी या अनियमितता सामने आती है तो जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

विधायक ने उठाई योजनाओं की गुणवत्ता पर चिंता : विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि कसौली क्षेत्र में जायका परियोजना के तहत सिंचाई से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इनका अपेक्षित लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर समानांतर योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जाने की

आशंका है। उन्होंने दो पंचायतों में सिंचाई विभाग की योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

विधायक ने कहा कि परियोजना की मूल भावना किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि योजना के लिए स्वीकृत धन का सही उपयोग हो और निर्धारित मानकों के अनुसार काम पूरा किया जाए।

छह सिंचाई योजनाओं पर खर्च होंगे करीब पांच करोड़

कृषि मंत्री के अनुसार कसौली क्षेत्र में जायका परियोजना के तहत छह सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं पर करीब 4.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नई कूहलें नहीं हैं, बल्कि पहले से अस्तित्व में रही कूहलों को ही परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, विधायक की ओर से कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब इन योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की स्थिति पर निगरानी बढ़ने की उम्मीद है।

शिक्षकों की तैनाती में देरी पर हाई कोर्ट सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल आफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती व तैनाती प्रक्रिया नियमों के अनुसार जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। अदालत ने कहा कि पात्र शिक्षकों और प्रिंसिपलों, जिनकी तैनाती अभी लंबित है, उन्हें जल्द संबंधित स्कूलों में नियुक्त किया जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चयन प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 की अधिसूचना और सरकार के निर्णयों के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने सरकार से स्वीकृत पदों, रिक्तियों, उपलब्ध अभ्यर्थियों और लंबित तैनाती की जानकारी वाली स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। पूर्व अंतरिम आदेश जारी रखते हुए सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पठानकोट में 700 बच्चों ने बारिश में लगाई दौड़

अशोक, भारतेन्दु संवाददाता , पठानकोट। पंजाब के पठानकोट में श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व की शताब्दी को समर्पित पांच किलोमीटर की रन फॉर इक्वेलिटी मैराथन का आयोजन किया गया। पंजाब सरकार, खेल विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस दौड़ को कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

तेज बारिश के कारण एक घंटे देरी से शुरू हुई दौड़ : पठानकोट में बुधवार सुबह तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया था। मैराथन सुबह सात बजे शुरू होनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे करीब एक घंटे की देरी से शुरू किया गया। हल्की बारिश के बीच भी विद्यार्थियों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने पूरे जोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया।

700 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा : जिला खेल अधिकारी के अनुसार पांच किलोमीटर की इस मैराथन में पठानकोट के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं से जुड़े करीब 700 बच्चों

गुरु रविदास प्रकाश पर्व पर 700 विद्यार्थियों ने लगाई पांच किलोमीटर दौड़

ने भाग लिया। बारिश और खराब मौसम के बावजूद विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन में शामिल सभी विद्यार्थियों को प्रशासन की ओर से खेल किट और पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया गया।

गुरु रविदास की विचारधारा को घर-घर पहुंचाने पर जोर : मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने शहरवासियों और पंजाब के लोगों को श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की विचारधारा और संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

सेमिनार और वृत्तचित्र से दिया जा रहा संदेश : मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में गुरु रविदास जी के दर्शन और वाणी पर आधारित सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके जीवन और विचारों पर आधारित वृत्तचित्र फिल्म प्रदेश के गांवों में दिखाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को गुरु रविदास जी के संदेश से जोड़ा जा रहा है।

चार विशाल नगर कीर्तन यात्राएं निकलेंगी : उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जम्मू, बठिंडा, जालंधर और गुरु रविदास जी के जन्मस्थान काशी से चार विशाल नगर कीर्तन यात्राएं शुरू होंगी। ये यात्राएं देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए श्री खुरालगढ़ साहिब पहुंचेंगी।

सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट करते पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार।

पंचायत घरों के निर्माण को लेकर सरकार ने तय किए नए नियम

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत घरों के निर्माण और उन्हें आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने को लेकर सरकार ने व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। अब पंचायत घर के निर्माण के लिए कम से कम 10 बिस्वा भूमि विभाग के नाम होना अनिवार्य होगा। सरकार पंचायत घर के निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपये तक का बजट उपलब्ध कराती है। नई पंचायतों को प्रारंभिक स्तर पर 50 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा विधायक अपनी निधि से पंचायत घरों के लिए फर्नीचर खरीदने को भी 50 हजार रुपये तक दे सकते हैं।

विधानसभा में उठा पंचायत घरों का मामला : ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में विधायक बलबीर वर्मा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के चौपाल, कियोग और कुपवी विकासखंडों में 20 पंचायत घरों के निर्माण और उन्नयन के लिए कुल 364.66 लाख रुपये स्वीकृत किए

गए हैं। इनमें से सात पंचायत घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पर्याप्त जमीन पर जोर : मंत्री ने विधायकों से पंचायत घरों के लिए अधिक से अधिक भूमि विभाग के नाम करवाने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायत घरों के लिए एक बीघा से अधिक जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पर्याप्त भूमि होने से भविष्य में पंचायत स्तर पर अतिरिक्त भवनों, सुविधाओं और विभिन्न विकास योजनाओं का विस्तार आसानी से किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि पंचायत घर केवल बैठकों और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं होने चाहिए। इनमें ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी।

नई पंचायतों को भी मिलेगी सहायता : नई गठित पंचायतों के लिए सरकार ने 50 हजार रुपये की राशि मंजूर करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पंचायत घरों में आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था के लिए विधायक अपनी निधि से 50 हजार रुपये तक की सहायता दे सकते हैं।

चिड़गांव में दबोचा गया सात साल से फरार अपराधी, पुलिस अभियान को मिली सफलता

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने पुराने और लंबित आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सात साल से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 55 वर्षीय धर्म दास पुत्र स्वर्गीय फूला सिंह निवासी चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे एक सितंबर को चिड़गांव से गिरफ्तार किया।

2019 में दर्ज हुआ था मामला : धर्म दास के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में 19 जून 2019 को प्राथमिकी संख्या 48/2019 दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज था। ये धाराएं लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग या हमला करने से संबंधित हैं।

अदालत ने घोषित अपराधी किया था : मामले में लगातार फरार रहने के कारण आरोपी को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद एसीजेएम रामपुर की अदालत ने 22 जनवरी 2026 को

धर्म दास को घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।

पीओ टीम ने लगातार की तलाश : आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रामपुर उपमंडल की घोषित अपराधी टीम लगातार संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थी। पुलिस को उसके चिड़गांव में मौजूद होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुराने मामलों में कार्रवाई जारी : पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबित मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को कानून के दायरे में लाना और अदालत की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।

सेब खरीद में कंपनियों की होड़, बागवानों के लिए बढ़े दाम

कंपनियों में बढ़ी खरीद प्रतिस्पर्धा, मंडियों में 150 रुपए तक पहुंचा सेब का भाव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सेब सीजन के बीच खरीददार कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सीधा लाभ बागवानों को मिलता नजर आ रहा है। कंपनियों ने एक ही दिन में सेब के खरीद रेट में करीब पांच रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी कर दी है। अडानी ने 108 रुपये, देवभूमि ने 113 रुपये और नीचे चेस्ट ने 110 रुपये प्रति किलो का रेट जारी किया है। दो अन्य छोटी कंपनियों ने भी करीब 112 रुपये प्रति किलो खरीद रेट घोषित किया है।

खरीद को लेकर बढ़ी प्रतिस्पर्धा : सेब उत्पादक क्षेत्रों में इस समय कंपनियों और निजी खरीदारों के बीच खरीद को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इसका असर सेब के बाजार भाव पर साफ दिखाई दे रहा है। कंपनियों की ओर से रेट बढ़ाए जाने से बागवानों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में दाम और मजबूत हो सकते हैं। खरीदारों के बीच बढ़ती होड़ के कारण उत्पादकों को अपनी

फसल के लिए बेहतर भाव मिलने की संभावना बनी है।

मंडियों में भी 150 रुपये तक पहुंचा भाव : कंपनियों के खरीद रेट बढ़ने के साथ मंडियों में भी सेब के दाम में तेजी दर्ज की जा रही है। अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को मंडियों में 150 रुपये प्रति किलो तक का भाव मिल रहा है। कारोबारियों के अनुसार जन्माष्टमी के कारण बाजार में सेब की मांग बढ़ी है। त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण सेब की मांग मजबूत बनी हुई है।

कम उत्पादन से कीमतों को सहारा : इस वर्ष प्रदेश में सेब का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कम रहने का अनुमान है। कम उत्पादन के कारण बाजार में उपलब्ध सेब की मात्रा सीमित है। दूसरी ओर मांग में खास कमी नहीं आई है। ऐसे में कम आपूर्ति और मजबूत मांग के कारण सेब के दाम को सहारा मिल रहा है। बागवानों को उम्मीद है कि यही स्थिति आगे भी बनी रही तो उन्हें सीजन में बेहतर आमदनी हो सकती है।

बागवानों की उम्मीद बढ़ी : बागवानों के लिए कंपनियों द्वारा रेट बढ़ाना राहत की खबर है। पहले से कम उत्पादन के बीच यदि खरीददारों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी रहती है तो इसका फायदा सीधे उत्पादकों को मिल सकता है। खासकर अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की मांग मजबूत रहने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि आने वाले दिनों में सेब के दाम किस स्तर तक पहुंचेंगे, यह मंडियों में आवक, फल की गुणवत्ता, बाजार की मांग और कंपनियों की खरीद पर निर्भर करेगा। फिलहाल कंपनियों की ओर से खरीद रेट बढ़ाए जाने और मंडियों में 150 रुपये तक भाव मिलने से बागवानों में सीजन को लेकर सकारात्मक उम्मीद बनी हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में बाजार की दिशा पर नजर रखना जरूरी होगा। गुणवत्ता वाले सेब की मांग मजबूत रहने पर बागवानों को ऊंचे दाम मिल सकते हैं। वहीं मंडियों में आवक बढ़ने या मांग कमजोर पड़ने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव संभव है। फिलहाल बढ़े खरीद रेट ने उत्पादकों को राहत दी है।

चौदहवीं विधान सभा के 12वें सत्र (मॉनसून सत्र) के 9वें दिन की कार्यवाही का संचालन करने विधान सभा सचिवालय पहुँचने पर सलामी लेते विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां।

बीपीएल प्रमाणपत्र मामले में हाई कोर्ट ने प्राथमिकी की खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कथित फर्जी बीपीएल प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि जब सक्षम ग्राम पंचायत को संबंधित परिवार की स्थिति की पूरी जानकारी थी और उसी ने प्रमाणपत्र जारी किया था तो इसे धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्यार सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के झंडूता थाने में दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी कार्यवाही निरस्त कर दी। मामला जून 2023 में सामने आया था, जब याचिकाकर्ता की बेटी का स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के पद पर बीपीएल कोटे से चयन हुआ।

लोकतंत्र विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां ने विद्यार्थियों को संसदीय व्यवस्था की दी विस्तृत जानकारी

विधानसभा दौरे में विद्यार्थियों ने जाना लोकतंत्र का महत्व

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी जिला चंबा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्पाटू जिला सोलन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटीकंडी, सेंट बीड्स कॉलेज संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलदया जिला शिमला के करीब 210 छात्र-छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय का दौरा किया। विद्यार्थियों ने काउंसिल चैंबर के बाहर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को भारतीय संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी दी।

विद्यार्थियों को दी संसदीय प्रणाली की जानकारी : कुलदीप सिंह पठानियां ने छात्र-छात्राओं को

विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सशक्त लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुने गए प्रतिनिधि देश तथा प्रदेश के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर माना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सांसद मिलकर लोकसभा का गठन करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह केंद्र में सरकार बनाता है। बहुमत वाले दल के नेता का चुनाव होने के बाद वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका समझाई : विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को राज्यसभा की संरचना और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है।

पठानियां ने बताया कि बड़े राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के कारण यहां विधान परिषद नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया।

भोरंज के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग के उत्साहजनक परिणाम

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भोरंज के सरकारी स्कूलों में पिछले एक वर्ष से जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन कोचिंग के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। बुधवार को मिनी सचिवालय में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ आयोजित बैठक में एसडीएम शशि पाल शर्मा ने कोचिंग व्यवस्था की समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि भोरंज क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया है। उन्होंने इन परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए विद्यालयों में कोचिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संकाय सदस्यों से कहा कि कोचिंग कक्षाएं नियमित रूप से जारी रखते हुए उनकी गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जाए, ताकि विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

बिक्रम ठाकुर ने सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाकर नियमित भर्तियों की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। विधानसभा में रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पांच वर्षों में पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में नियमित भर्तियों के बजाय आउटसोर्स और कम मानदेय वाली नौकरियों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक : बिक्रम ठाकुर ने श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल में बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 3.01 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। सरकार को सरकारी भर्तियों के

साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए।

उद्योगों के कमजोर माहौल पर सवाल : उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 95 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़ी हैं और फार्मा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद औद्योगिक गतिविधियों में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 115 औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में नए रोजगार अवसर पैदा करना चुनौतीपूर्ण है।

नियमित भर्तियों के बजाय आउटसोर्स व्यवस्था : बिक्रम ठाकुर ने कहा कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 725 लोगों की भर्ती हुई है, जबकि राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से केवल 97 लोगों की भर्ती हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में पद आउटसोर्स माध्यम से भरे जा रहे हैं। उनके अनुसार युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार की जरूरत है, न कि कम मानदेय वाली अस्थायी नौकरियों की।

414 टीजीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग : भाजपा विधायक ने टीजीटी कला के 414 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को 75 दिनों से अधिक समय बीतने पर भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्तियां देने की मांग की।

न्यूज ब्रीफ

राज्य पुरस्कार की सूची से हमीरपुर कॉलेज के प्राचार्य का नाम गायब, एसीआर को लेकर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। वर्ष 2026 के राज्य पुरस्कारों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा चयनित प्राचार्यों व प्रोफेसरों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित शिक्षकों को 2 सितंबर को शिमला सचिवालय में उपलब्धियों पर प्रस्तुति और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हालांकि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर के प्राचार्य डॉ. सतीश सोनी का नाम सूची में शामिल नहीं है। प्राचार्य ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि उनकी एसीआर प्राप्त नहीं हुई है, जबकि कॉलेज के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 की एसीआर 21 अक्तूबर 2024 को संबंधित कार्यालय को भेजी गई थी, जिसका उल्लेख डिस्पैच रजिस्टर में क्रमांक 1105 पर दर्ज है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के 134 कॉलेजों की समग्र रैंकिंग में हमीरपुर कॉलेज प्रथम रहा है। कॉलेज के पांच सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों का नाम पुरस्कार सूची में शामिल है। प्राचार्य ने मामले की अभिलेख आधारित जांच की मांग की है।

बामटा में गूंज रही गुग्गा गाथा, 25 वर्षों से परंपरा निभा रही गायन मंडली

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में इन दिनों गुग्गा मंडलियां घर-घर जाकर गुग्गा गाथा का गायन कर रही हैं। इसी कड़ी में नोग की सरवन एंड पार्टी भी बामटा क्षेत्र में गुग्गा गाथा का गायन कर रही है। मंडली के 6-7 सदस्य नंगे पैर घर-घर पहुंचकर गुग्गा गाथा सुनाकर इस पारंपरिक लोक संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। मंडली के मुखिया सरवन कुमार ने बताया कि उनकी मंडली पिछले करीब 25 वर्षों से इस परंपरा को निभा रही है। उन्होंने बताया कि मंडली के सदस्य हर वर्ष रक्षाबंधन से लेकर गुग्गा नवमी तक लगातार नौ दिनों तक नंगे पैर आसपास की पांच-छह पंचायतों में जाकर लोगों को गुग्गा गाथा सुनाते हैं। इस दौरान ग्रामीण भी मंडली का स्वागत करते हैं और श्रद्धा के साथ गुग्गा देवता की गाथा सुनते हैं। सरवन कुमार ने कहा कि गुग्गा गायन केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी परंपरा नहीं, बल्कि हिमाचल की लोक संस्कृति और लोकगीतों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंडली का उद्देश्य वर्षों पुरानी इस परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और इसे जीवित रखना है।

परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच अब स्वचालित परीक्षण केंद्र से

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। क्षेत्रीय मोटर वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) सुंदरनगर के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत सभी परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच अब स्वचालित परीक्षण केंद्र के माध्यम से होगी। परिवहन विभाग के निर्देशों के तहत 1 सितंबर से फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए मैनुअल फिटनेस जांच व्यवस्था बंद कर दी गई है। आरएलए सुंदरनगर अमर नेगी ने बताया कि परिवहन विभाग ने मैसर्स विक्रम एचपी सेंटर, कांगू (डैहर), तहसील सुंदरनगर को स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित एवं संचालित करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया है। केंद्र संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर आरएलए के तहत पंजीकृत बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी कैब सहित सभी परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच अब केवल स्वचालित परीक्षण केंद्र कांगू में होगी। इस व्यवस्था से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने वाहन मालिकों से फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले वाहन की जांच करवाने और निर्धारित शुल्क समय पर जमा करने की अपील की है।

राज्यपाल ने हमीरपुर में पूर्व सैनिकों से की भेंट

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मंगलवार सायं हमीरपुर में पूर्व सैनिकों से भेंट की। उन्होंने उनके कल्याण व हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने राज्यपाल को पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। पूर्व सैनिकों ने प्रस्तावित शहीदी स्मारक के लंबित निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी दी। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों एवं समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने शहीदी स्मारक के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। राज्यपाल ने शहीदी स्मारक के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी सांसदों एवं विधायकों से भी इस निर्माण कार्य में सहयोग एवं योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह स्मारक हमारे वीर शहीदों के अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति एक सच्ची एवं गरिमापूर्ण श्रद्धांजलि होगा।

एक हजार ई-बसें व 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी सुक्खू सरकार

सीएम सुक्खू बोले- तीन हजार बसों पर 7 हजार करोड़ खर्च करना उचित नहीं, 12 साल तक कंपनी संभालेगी रखरखाव और मरम्मत

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से एक हजार इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने जा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में तीन हजार बसें खरीदने पर करीब सात हजार करोड़ रुपए खर्च करना उचित नहीं होगा। सरकार जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से बसों का बेड़ा बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में केवल बस की कीमत ही नहीं, उसके रखरखाव और मरम्मत का खर्च भी शामिल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की 12 वर्ष तक देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। उन्होंने बताया कि पहले इलेक्ट्रिक बस की लागत करीब 70 रुपए प्रति किलोमीटर तक पड़ रही थी, जो अब सभी खर्चों को जोड़ने के बाद करीब 36 रुपए प्रति किलोमीटर रह गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को विधानसभा में सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की बसों की कमी और बंद पड़े बस रूटों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कही। विधायक चंद्रशेखर ने यह मामला विधानसभा में नियम-62 के तहत उठाया था। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश के लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह है, लेकिन सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्रों में बसों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था का मौके पर आकलन कराने के लिए निगम के उच्च अधिकारियों की टीम भेजने की मांग की।

सरकाघाट-धर्मपुर में 16 रूट बंद होने का दावा

चंद्रशेखर ने कहा कि सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र में 16 बस रूट पूरी तरह बंद हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सरकाघाट डिपो को दो हिस्सों में बांटकर धर्मपुर डिपो बनाया गया था। उस समय सरकाघाट डिपो में करीब 280 बसें थीं, जबकि धर्मपुर डिपो को 48 बसें दी गई थीं। उनका आरोप था कि धर्मपुर डिपो को कुछ पुरानी और लगभग अपनी उपयोगी अवधि पूरी कर चुकी बसें भी दी गई। विधायक ने कहा कि वर्ष 2025 की आपदा के बाद क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था और प्रभावित हुई। कई बसें काफी पुरानी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि तीन बसें 15 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। उनका कहना था कि इस स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होती है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि एचआरटीसी व्यावसायिक संस्था नहीं है, यह जनसेवा से जुड़ा निगम है। उन्होंने सरकाघाट और धर्मपुर में बसों तथा रूटों की स्थिति की जानकारी विधानसभा में दी। सरकार के अनुसार सरकाघाट क्षेत्र के लिए 77 बसों का बेड़ा स्वीकृत है, जिसमें से 58 बसें उपलब्ध हैं। इनमें नौ बसें नौ वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं। इसके अलावा 10 जेएनएनयूआरएम बसें भी चल रही हैं। उपलब्ध बसों से 74 रूटों पर सेवाएं दी जा रही हैं, जबकि 17 रूट बंद हैं। धर्मपुर में 56 स्वीकृत रूटों में से 46 पर बस सेवा चल रही है। यहां 47 बसों के माध्यम से 57 रूट संचालित किए जा रहे हैं, जबकि नौ रूट बंद हैं। सरकार ने यह भी माना कि एचआरटीसी में स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों की कमी है। सरकार की ओर से कहा गया कि उच्च स्तर के अधिकारी जल्द संबंधित क्षेत्र का दौरा कर वहां की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेंगे। मंत्री ने बताया कि एचआरटीसी के लिए 250 डीजल बसों और 100 छोटी बसों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। धर्मपुर में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलाई जा सकी हैं। चार्जिंग की सुविधा विकसित करने के लिए बिजली विभाग को 63 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं।

जयराम ने इलेक्ट्रिक बस नीति पर उठाए सवाल

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की इलेक्ट्रिक बस नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बसें भेजी गई थीं, लेकिन वे रास्ते में खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कई मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन चुनौतीपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों की तुलना में करीब तीन गुना महंगी पड़ती हैं। ऐसे में सरकार को यह देखना होगा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की मूल जिम्मेदारी भी पूरी हो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और बसों की वास्तविक उपलब्धता तथा उनके संचालन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

एमएससी केमिस्ट्री चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कांगड़ा की छात्राओं का शानदार प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा घोषित एमएससी केमिस्ट्री चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। छात्राओं की इस उपलब्धि से महाविद्यालय परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण है।

महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में मीनाक्षी देवी ने 8.77 सीजीपीए प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन के माध्यम से यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। वहीं, संयोगिता ने 8.48 सीजीपीए अर्जित कर महाविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त प्रियंका ने 8.39 सीजीपीए के साथ महाविद्यालय स्तर पर तृतीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तीनों छात्राओं की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास और अध्ययन के प्रति समर्पण का परिणाम है। छात्राओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी सफल छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं का यह शानदार प्रदर्शन महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की ऐसी उपलब्धियां अन्य छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्राचार्य ने इस उपलब्धि के लिए छात्राओं के साथ-साथ विभाग के शिक्षकों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ-साथ शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाविद्यालय के शिक्षकों और समस्त स्टाफ ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। छात्राओं की इस सफलता से एमसीएम डी.ए.वी. कॉलेज कांगड़ा ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है।

नवोदय में 9वीं और 11वीं की खाली सीटों के लिए आवेदन 30 तक

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के दौरान नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। ये आवेदन वेबसाइट सीबीएसईआईटीएमएस.एनआईसी.इन/2026 पर किए जा सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान जिला हमीरपुर के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी नवोदय की नौवीं कक्षा की खाली सीटों के लिए और दसवीं में पढ़ रहे विद्यार्थी नवोदय की ग्यारहवीं कक्षा की खाली सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य विक्रम कुमार ने बताया कि अगर किसी विद्यार्थी को आवेदन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वह किसी भी कार्य दिवस में विद्यालय के हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकता है।

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण से सुख-शांति व समृद्धि की कामना की

भारतेन्दु संवाददाता, तियारा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल तियारा परिवार ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। स्कूल परिवार ने भगवान श्रीकृष्ण से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

डीएवी कॉलेज समिति, नई दिल्ली प्रेसिडेंट डॉ. पूनम सूरी, चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल, एआरओ नमित शर्मा एवं मैनेजर विपिन जिष्टू के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल की ओर से जन्माष्टमी पर्व को लेकर शुभकामना संदेश जारी किया गया। प्रधानाचार्य एवं स्कूल के समस्त स्टाफ ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानव समाज को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए संदेश आज भी जीवन में सकारात्मक सोच और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कूल परिवार ने सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से पर्व को प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में खुशहाली आए और समाज में शांति एवं सद्भाव की भावना मजबूत हो।

स्क्रब टाइफस से बचाव को विशेष एहतियात बरतें लोग : सीएमओ

भरतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। मानसून के दौरान स्क्रब टाइफस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर शशि दत्त शर्मा ने कहा कि वर्षा ऋतु और विशेषकर घास कटाई के मौसम में इस रोग के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि स्क्रब टाइफस एक जूनोटिक रोग है, जो ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से झाड़ियों और घास वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रमित माइट्स के काटने से फैलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खतरा अधिक रहता है। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ा दी है तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने लोगों से तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य

◆ **तेज बुखार व शरीर दर्द को न करें नजरअंदाज, तुरंत स्वास्थ्य संस्थान पहुंचें**

संस्थान में चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की उन्होंने कहा कि खेतों और घास वाले क्षेत्रों में काम करते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। घर के आसपास साफ-सफाई रखें और झाड़ियों व खरपतवार को हटाते रहें। घास काटने या घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों से लौटने के बाद स्नान करने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पालतू पशुओं की नियमित सफाई भी जरूरी है। सीएमओ ने लोगों से जमीन पर सोने, हरी घास में बैठने या लेटने तथा कृषि कार्य के दौरान आधी बांह वाले कपड़े पहनने से बचने को कहा। स्वास्थ्य विभाग पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालयों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चला रहा है।

एक ही गांव के दो युवकों की संदिग्ध मौत

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। उपमंडल हरोली के गांव पूबोवाल में बुधवार को एक ही गांव के दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से शोक की लहर दौड़ गई। करीब 30 से 32 वर्ष की उम्र के अमनदीप सिंह और सुखराज की अचानक मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों युवक शादीशुदा थे और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह का शव बुधवार सुबह करीब सात बजे घालूवाल स्थित रेन शेल्टर में मिला। वहीं, सुखराज को सुबह करीब 11 बजे अचेत अवस्था में सिविल अस्पताल हरोली लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के दो युवकों की कुछ घंटों के अंतराल में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों की मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। परिस्थितियां संदिग्ध होने के चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में करवाया जाएगा। हरोली थाना प्रभारी अनूप कुमार ने दोनों मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विजय मेमोरियल स्कूल के आराध्या-तानिश ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे ताइक्वांडो का दम

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंदौरा ने शिक्षा के साथ खेलों के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत करते हुए जिला कांगड़ा का नाम रोशन किया है।

विद्यालय के दो होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी आराध्या और तानिश का चयन 15वीं इंटरनेशनल ओपन फ्रेंडशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 28 और 29 नवंबर को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। दोनों खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रथम ओपन फ्रेंडशिप नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-9बी, चंडीगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजय मेमोरियल स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आराध्या और तानिश ने स्वर्ण, सक्षम, पियूष और जसविंदर ने रजत, जबकि आयुष और आदर्श ने कांस्य पदक जीते। विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे पूरे जिला कांगड़ा के लिए गर्व का विषय बताया। प्राचार्या सोनिया शर्मा और स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर सचिन शर्मा ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उचित मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों को भी समान महत्व दिया जाता है। विद्यालय परिवार ने आराध्या और तानिश को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना की। प्रबंधन ने भविष्य में भी विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही।

AUCTION NOTICE

The following unserviceable Non Ferrous/Gun Metal Copper Scrap, Iron/Steel scrap and Aluminum Scrap will be disposed off "as is where is" basis through Public auction on 09.09.2026 at 11.00 AM, in the premises of Jal Shakti Mechanical Workshop, Baggi, Distt Mandi H.P.

Sr. No.	Description of Items	Qty.	Lot Nos. Wise	Remarks
1.	Non Ferrous/Gun Metal Scrap.	404 Kg.	Lot No.1	Survey report has been approved and sanction to write off has been accorded vide EE-Jal Shakti Division BGI-AB-Survey report 2024-25 20473-75 dated-21.02.2025
1.	Copper/Gun Metal Scrap	100 Kg.	Lot No.2	Survey report has been approved and sanction to write off has been accorded vide EE-Jal Shakti Division BGI-AB-Survey repon/2026-27-11386-88 dated-18.07.2026
1.	Iron/Steel Scrap	173 Kg.	Lot No.3	Survey report has been approved and sanction to write off has been accorded vide EE-Jal Shakti Division BGI-AB-Survey report/2026-27-11383-85 dated-18.07.2026
2.	Copper Gun Metal Scrap	94 Kg.		
3.	Aluminum Scrap	4 kg		

Terms and Conditions: **1.** The auction shall be done on "as is where basis is". **2.** The intending bidders have to deposit EMD of Rs. 3,000/- (Rupees three thousand only) for each item/lot separately ie Rs. 3000/-only by way of cash payment before participating in the auction and which shall be returned back to unsuccessful bidders on the same day after completion of the auction **3.** The EMD of successful bidder will be adjusted in the total amount of bid. **4.** Bidder(s) can inspect the articles/items between 10.00 a.m. to 4.00 p.m. in the above mentioned address from to 05.09.2026 to 08.09. 2026 and on 09.09.2026 upto 11.00 A.M. in regard to the conditions, quality etc of the articles/items and satisfy themselves before bidding by the date and time specified. **5.** Any tax is liable shall be paid by the successful bidder. **6.** Copy of GST Registration certificate & Copy of PAN No. **7.** All articles/items will be sold on "AS IS WHERE IS BASIS" will be deemed to have been on the clean understanding that they have satisfied themselves full in regard to the conditions, quality and quantity of the articles/items proposed to be auctioned. **8.** The successful bidder will be required to make full payment of bid on the same day by 4.00 PM. on 09.09.2026 after the finalization of the bid. **9.** The successful bidder will have to lift the articles/items in his own cost, risk and arrangement within a week after depositing the full amount of payment of the bid otherwise the EMD will be confiscated. **10.** The undersigned reserves the right to postpone the date of opening or accept or reject any or all the bids.

Assistant Engineer
JS Mech.S/Division
Baggi, Distt. Mandi (HP)

बिलासपुर में सड़क हादसे में एक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला पुलिस ने पिछले 24 घंटों में सड़क दुर्घटना, मारपीट और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े पांच अलग-अलग मामलों में बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। शिकायत के आधार पर ट्रक चालक राज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदौली गांव में गोशाला निर्माण को लेकर हुए विवाद में नंदू राम ने तोता राम व अन्य पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। इसी गांव की कृष्णा देवी ने कमलदेव व अन्य पर पशुशाला गिराने, पशुओं को दबाने और मारपीट का आरोप लगाया है। झंडूता पुलिस ने जेएमएफसी के आदेश पर राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 2016-17 और 2021 के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में श्री राम व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, तलाई थाना क्षेत्र में निक्की देवी ने बेटे राज कुमार पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया है। सभी मामलों की जांच जारी है।

प्रदर्शन मांगें नहीं मानी, तो आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी, चौड़ा मैदान में गरजे कर्मचारी

ओपीएस की मांग को लेकर गरजे बिजली बोर्ड के कर्मी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली बोर्ड में समायोजित करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अभियंताओं ने बुधवार को शिमला में विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया।

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व अभियंता संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कर्मचारी और कर्मचारी नेता पहुंचे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की। प्रदर्शन से पहले कर्मचारियों ने रैली निकाली। यह रैली राज्य बिजली बोर्ड के कुमार हाउस स्थित कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद कर्मचारी चौड़ा मैदान में एकत्र हुए। प्रदर्शन में बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारियों के साथ आउटसोर्स कर्मचारी और इंजीनियरिंग विंग से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली उनकी सबसे प्रमुख मांग है। उनका कहना है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।

एचपीएसईबी एंप्लाइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली बोर्ड के करीब 9 हज़ार कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी कोई नई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। उनकी मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का गठन 1971 में हुआ था और 1972 के पेंशन नियमों के तहत कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान था। उनका कहना है कि जब प्रदेश के करीब डेढ़ लाख अन्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया है, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे अलग क्यों रखा गया है। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि सरकार को बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की इस मांग पर जल्द फैसला लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई और कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो कर्मचारी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ने पर हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। यूनियन के संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों की कई मांगें हैं। इनमें नई भर्तियां और दूसरे कर्मचारी मुद्दे शामिल हैं, लेकिन पुरानी पेंशन की मांग सबसे प्रमुख है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले करीब ढाई से साढ़े तीन साल से पुरानी पेंशन से वंचित हैं, जबकि प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि 1974 में राज्यपाल की ओर से पीसीसी रूल्स लागू किए गए थे और उस समय बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी सेवा में थे। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी शिमला पहुंचे हैं और सरकार से विधानसभा सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की मांग कर रहे हैं। हीरालाल वर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो कर्मचारी लंबा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया। उनके मुताबिक एक समय बिजली बोर्ड में करीब 43 हज़ार कर्मचारी थे, जो अब घटकर करीब 13 हजार रह गए हैं। इसके अलावा करीब 3 हजार कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं।

न्यूज शॉर्ट्स

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजी प्रमोद श्रीवास्तव को अतिरिक्त जिम्मेदारी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 1992 बैच की वरिष्ठ आइएएस अधिकारी राजी प्रमोद श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार उन्हें वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजी प्रमोद श्रीवास्तव वर्तमान में विशेष मुख्य सचिव, स्वतंत्रता सेनानी के पद पर तैनात हैं। अब उन्हें विशेष मुख्य सचिव, स्वतंत्रता सेनानी के साथ सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

फर्जी फर्म बनाकर बैंकों से करोड़ों का लिया कर्ज

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। शहर में जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म बनाकर बैंकों और सरकारी विभागों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाजों ने परमजीत कौर के पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर बोगस फर्म बनाई। इसके बाद फर्जी जीएसटी नंबर हासिल कर बैंकों से भारी-भरकम कर्ज लिया गया और जाली आयकर रिटर्न भी दाखिल की जाती रही। मामले का पता चलने पर पीड़िता ने शिकायत दी।

चंडीगढ़: सेक्टर-17 में स्मार्ट पार्किंग का होगा आगाज, शहरभर में हो रही विस्तार की तैयारी

चंडीगढ़ में एप से बुक होगी पार्किंग में जगह, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा नगर निगम

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

शहर की पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम अब स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह परियोजना फिलहाल पूरे शहर में एक साथ लागू नहीं होगी। निगम पहले सेक्टर-17 की सभी पार्किंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्मार्ट पार्किंग समाधान से जोड़ने की योजना बना रहा है। इसके लिए पार्किंग संचालन किसी निजी एजेंसी को सौंपने का प्रस्ताव आगामी सदन की बैठक में रखा जा सकता है। परियोजना के सफल रहने पर सेक्टर-34 समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था में कई आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इससे वाहनों की सुरक्षा के साथ पार्किंग कर्मचारियों की गतिविधियों और शुल्क वसूली पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रस्तावित व्यवस्था में मोबाइल एप के जरिए पार्किंग स्थल बुक करने और पहले से खाली स्थानों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी होगी। इससे वाहन चालकों को पार्किंग तलाशने में लगने वाला समय कम होगा।

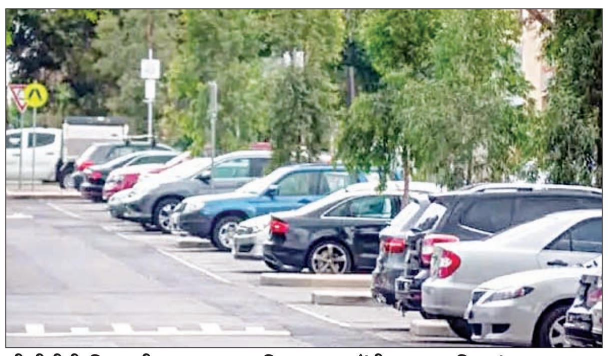

सीसीटीवी निगरानी, समय-आधारित शुल्क होंगी मुख्य सुविधाएं।

नई व्यवस्था में पार्किंग शुल्क को वाहन के पार्क रहने की अवधि के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव भी है। हालांकि चुनावी वर्ष होने के कारण शुल्क बढ़ाने या अधिक समय तक वाहन खड़ा रखने पर ज्यादा शुल्क लेने के प्रस्ताव को लेकर नगर निगम में राजनीतिक सहमति बनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्षदों की ओर से इसका विरोध किए जाने की संभावना है।

निरीक्षण में सामने आई कई कमियां : नगर निगम के अधीन करीब 88 भुगतान वाली पार्किंग हैं। फिलहाल इनका संचालन निगम खुद कर रहा है। हाल के निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों को पार्किंग व्यवस्था में कई खामियां मिली थीं। कई स्थानों पर वाहनों को नियमित रूप से पर्चियां नहीं दी जा रही थीं। इसके अलावा वाहनों की निगरानी, शुल्क वसूली और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायतें सामने आईं।

आठ स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग की योजना

राइट्स की व्यापक आवागमन योजना में शहर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए आठ स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें चार स्थान सेक्टर-17 में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सेक्टर-34, सेक्टर-43 और आइटी पार्क फेज-1 में भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद इनमें से एक-दो स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। नगर निगम की योजना पहले सेक्टर-17 में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था को परखने की है। इसके परिणामों के आधार पर आगे के क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। इससे पार्किंग संचालन में पारदर्शिता, निगरानी और राजस्व वसूली बेहतर होने की उम्मीद है।

एबीवीपी की रणनीति से मिली जीत

रणनीति और एकजुटता के दम पर एबीवीपी ने जीता छात्रसंघ चुनाव

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार मुकाबला केवल छात्र संगठनों के बीच नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी साफ नजर आई। चुनाव को अगले वर्ष होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। करीब पांच लाख युवा मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले छात्र राजनीति के इस चुनाव में एबीवीपी ने रणनीति और संगठनात्मक तैयारी के दम पर बढ़त बनाई। वहीं, एनएसयूआइ आंतरिक गुटबाजी के कारण लगातार तीसरे चुनाव में कमजोर साबित हुई।

सोई का समर्थन बना अहम : एबीवीपी की जीत में चुनाव से ठीक एक दिन पहले शिअद के छात्र संगठन सोई का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समर्थन से एबीवीपी को चुनावी समीकरण मजबूत करने में मदद मिली। इसके अलावा संगठन ने पहले से ही दूसरे छात्र संगठनों से जुड़े प्रभावशाली चेहरों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई।

दो वर्ष पहले पीयू छात्रसंघ चुनाव जीत चुके निर्दलीय उम्मीदवार अनुराग दलाल को भी एबीवीपी ने अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही पिछले वर्ष आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसएपी से अध्यक्ष पद का टिकट मांग चुके चिराग को भी संगठन में शामिल किया गया। इन चेहरों के जुड़ने से एबीवीपी को अलग-अलग छात्र समूहों तक पहुंच बनाने में फायदा मिला।

गुटबाजी से कमजोर हुई एनएसयूआइ

एनएसयूआइ के लिए आंतरिक मतभेद एक बार फिर नुकसानदेह साबित हुए। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर संगठन में एकजुटता दिखाई दी, लेकिन उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर गुटबाजी सामने आई। इसके चलते कार्यकर्ताओं में समन्वय की कमी दिखाई दी।

इंटरनेट मीडिया बना चुनाव प्रचार का अहम हथियार

इस बार चुनाव प्रचार में इंटरनेट मीडिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। छात्र संगठनों ने प्रचार के लिए अलग-अलग टीमें और वार रूम तैयार किए थे। प्रत्याशियों की गतिविधियों को लगातार इंटरनेट मीडिया पर साझा किया गया। प्रचार सामग्री, वीडियो और प्रत्याशियों के कार्यक्रमों को तेजी से छात्रों तक पहुंचाया गया। एबीवीपी ने जहां संगठनात्मक मजबूती और विभिन्न छात्र समूहों को साथ जोड़ने पर जोर दिया, वहीं उसके प्रतिद्वंद्वी संगठन आपसी मतभेद और स्पष्ट रणनीति की कमी से जूझते नजर आए। यही चुनावी समीकरण अंततः एबीवीपी के पक्ष में जाता दिखाई दिया। इसके साथ चुनावी रणनीति में प्रत्यक्ष संपर्क के साथ डिजिटल प्रचार को भी प्राथमिकता दी गई। छात्र संगठनों ने मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए।

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलेगा 36 दिन अपग्रेडेशन काम, 12 ट्रेनें रहेंगी बंद

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को अगले 36 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्टेशन के अपग्रेडेशन कार्य के लिए रेलवे ने 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पावर और ट्रैफिक ब्लॉक को मंजूरी दी है। इस दौरान अलग-अलग चरणों में कुल 12 ट्रेनें रद रहेंगी और इनके 442 फेरे प्रभावित होंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा, जबकि कई के मार्ग और चंडीगढ़ स्टेशन पर प्लेटफार्म बदले जाएंगे।

रेलवे के अनुसार स्टेशन पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्य के लिए तीन चरणों में ब्लॉक लिया जाएगा। पहला चरण 10 से 21 सितंबर, दूसरा 22 सितंबर से तीन अक्टूबर और तीसरा चार से 15 अक्टूबर तक रहेगा। प्रत्येक चरण 12 दिनों का होगा। इस दौरान अलग-अलग रेल लाइनों पर निर्धारित कार्य किए जाएंगे।

रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की ओर से कराए जा रहे कार्य के तहत लाइन नंबर छह, सात, आठ, चार, पांच, एक, दो और तीन पर पावर तथा यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान बैलेंस गर्डर की स्थापना और उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा पैदल पारपथ के गर्डर हटाने का कार्य भी किया जाएगा। अपग्रेडेशन कार्य के कारण अलग-अलग चरणों में 12 ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित होगा। इनके कुल 442 फेरे रद होने से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।

चंडीगढ़ में सोने-चांदी के गिरे भाव, ग्राहकों को राहत

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। सितंबर की शुरुआत सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ हुई है। चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों के दौरान कीमती धातुओं के भाव में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ज्वेलर राजीव सहदेव की ओर से जारी भाव के अनुसार 2 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। एक सितंबर को यही भाव 1,60,000 रुपये था। इससे पहले 26 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1,66,700 रुपये और 24 अगस्त को 1,66,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 24 कैरेट सोने के भाव में 11,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। सोने की अन्य श्रेणियों में भी गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोने का भाव 24 अगस्त को 1,53,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 2 सितंबर को घटकर 1,42,600 रुपये रह गया। इसी तरह 18 कैरेट सोने की कीमत 1,27,200 रुपये से घटकर 1,18,300 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 1,00,400 रुपये से कम होकर 93,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

मुनाफे का झांसा देकर दो महिलाओं से करोड़ों की ठगी

◆ **शेयर बाजार में बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने करोड़ों रुपए ठगे**

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

शेयर बाजार में रोजाना पांच प्रतिशत तक मुनाफे और आईपीओ में 150 प्रतिशत तक रिटर्न का झांसा देकर साइबर ठगों ने चंडीगढ़ की दो महिलाओं से कुल 3,49,13,731 रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने खुद को प्रतिष्ठित निवेश और ट्रेडिंग कंपनियों का अधिकारी बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। साइबर अपराध थाना सेक्टर-17 ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फर्जी पहचान से बनाया भरोसा : ठगों ने व्हाट्सएप समूह और फेसबुक विज्ञापनों के जरिए महिलाओं से संपर्क किया। इसके बाद उन्हें फर्जी ट्रेडिंग खाते खुलवाकर उसमें निवेश पर लगातार मुनाफा दिखाया गया। आरोपितों ने कथित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र भी भेजे, जिससे पीड़ितों को उन पर भरोसा हो गया।

3.30 करोड़ गंवाए : सेक्टर-38 वेस्ट निवासी मृदु मलिक को सात जून को शेयर बाजार से जुड़े एक व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया था। अगस्त के पहले सप्ताह में एक व्यक्ति ने खुद को निवेश कंपनी का अधिकारी बताया और रोजाना पांच प्रतिशत तक मुनाफे का दावा किया। शुरुआत में महिला ने करीब 20 हजार रुपये लगाए और खाते में मुनाफा दिखाई देने लगा।

इसके बाद निवेश बढ़ाकर करीब 20 लाख रुपये किया गया। आरोपितों ने राइट इश्यू और आईपीओ में निवेश के नाम पर महिला से बड़ी रकम जमा करवाई। महिला ने करीब डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये दोनों में लगाए। रकम निकालने की कोशिश करने पर टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर करीब 10 लाख रुपये और जमा करवाए गए। इस तरह महिला से करीब 3.30 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

न्यूज ब्रीफ

मानसून में बढ़ा डेंगू-मलेरिया का खतरा नगर निगम ने जारी की स्वास्थ्य सलाह

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और पानी से होने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने लोगों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी की है। निगम ने घरों और आसपास सफाई रखने तथा पानी जमा न होने देने की अपील की है। कूलर, गमले, टायर, डिब्बे और पानी की टंकियों को नियमित रूप से साफ करने की सलाह दी गई है। नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई रखने तथा कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने को कहा गया है। पीने के लिए साफ और ढके बर्तनों में पानी रखें और जरूरत पड़ने पर पानी उबालकर या क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करें। फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं और खुले व बासी भोजन से बचें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाने की सलाह दी गई है। निगम ने सांपों से सावधान रहने और घास व झाड़ियों में नंगे पैर न जाने को कहा है। सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है। निगम के अनुसार सामूहिक प्रयास और जागरूकता से मानसून में बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है।

सनटेक सिटी मामले में आईएएस अनुराग वर्मा को ईडी का समन

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को दोबारा समन जारी किया है। उन्हें सात सितंबर को जालंधर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। यह कार्रवाई मोहाली की सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। इससे पहले अनुराग वर्मा को 31 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए और दस्तावेज जुटाने के लिए समय मांगा था। मामले में आइएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ से भी दो बार पूछताछ हो चुकी है। ईडी वर्ष 2024 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए प्रशासनिक फैसलों और जमीन मालिकों की सहमति से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पंजाब में बिजली संकट गहराया, पांच थर्मल यूनिट हुए बंद

भारतेंदु संवाददाता, पटियाला। पंजाब में बिजली की मांग बढ़ने के बीच सरकारी थर्मल प्लांटों की उत्पादन क्षमता प्रभावित है। रोपड़, लहरा मोहब्बत और गोइंदवाल साहिब के कुल दस यूनिटों में से पांच बंद हैं। रोपड़ से केवल 200 मेगावाट और लहरा मोहब्बत से 167 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि गोइंदवाल साहिब लगभग 496 मेगावाट उत्पादन कर रहा है। राज्य में निजी थर्मल प्लांटों की स्थिति बेहतर है। राजपुरा से 1329 और तलवंडी साबो से 1676 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। दूसरी ओर बिजली की मांग 16 हजार मेगावाट से अधिक पहुंच गई है। गर्मी और उमस के कारण घरेलू खपत बढ़ी है, जबकि बारिश कम होने से कृषि क्षेत्र में मोटरों का इस्तेमाल बढ़ गया है।

दबुर्जी फ्लाईओवर पर बस-ट्रक की जोरदार टक्कर

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। दबुर्जी फ्लाईओवर पर बुधवार को ट्रक और पंजाब रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें और खरोंचें आईं, जबकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। प्राथमिक उपचार के बाद यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार, ट्रक बठिंडा से अजनाला जा रहा था। वहीं पंजाब रोडवेज की बस तरनतारन के पट्टी से जम्मू की ओर जा रही थी। चालक के मुताबिक फ्लाईओवर की चढ़ाई पर ट्रक अचानक पीछे की ओर आने लगा और उसका पिछला हिस्सा बस के अगले भाग से टकरा गया।

लुधियाना स्कूल में हेड टीचर की हुई अचानक मौत

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। सरकारी प्राथमिक स्कूल हैबोवाल खुर्द के हेड टीचर हरजीत ग्रेवाल की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पानी पीते समय वह अचानक गिर पड़े। अध्यापक उन्हें पहले नजदीकी क्लीनिक और फिर दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरजीत ग्रेवाल सुबह सामान्य रूप से स्कूल पहुंचे थे और प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद कक्षाएं भी ली थीं।

डीए बकाया भुगतान को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारियों में बढ़ा टकराव

डीए भुगतान को लेकर कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के करीब 3.5 लाख कर्मचारियों और लगभग 4 लाख पेंशनरों को पिछले तीन वर्षों से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की लंबित किस्तों का इंतजार है। यह मामला अब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बड़े विवाद में बदल गया है। कर्मचारियों का दावा है कि सरकार पर बकाया डीए और डीआर के भुगतान से करीब 25 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जबकि सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों को पहले ही अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिल रहा है।

कर्मचारी संगठनों के अनुसार पंजाब के सामान्य कर्मचारियों को फिलहाल 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में कार्यरत आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और न्यायिक अधिकारियों को 58 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को भी जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इसी अंतर को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अदालत का रुख किया था।

◆ **लाखों कर्मचारी तीन साल से कर रहे महंगाई भत्ते का इंतजार**

◆ **पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दे रही चुनौती**

8 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को 30 जून तक सभी लंबित डीए और डीआर जारी करने तथा कर्मचारियों को अधिकारियों के समान डीए देने का आदेश दिया था। सरकार और पीएसपीसीएल ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज हो गई।

3 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने 15 दिन के भीतर बकाया भुगतान का निर्देश दिया और 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी। समय पर भुगतान नहीं होने पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का भी प्रावधान किया गया।

राजोआना को हाईकोर्ट से राहत, आंखों के ऑपरेशन को मिली मंजूरी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा का सामना कर रहे बलवंत सिंह राजोआना की आंखों के ऑपरेशन से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है। पटियाला केंद्रीय जेल में बंद राजोआना की आंखों का ऑपरेशन किसी निजी अस्पताल में नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी जांच और संभावित ऑपरेशन पीजीआई चंडीगढ़ में ही किया जाएगा। न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आम लोग भी बेहतर इलाज के लिए पीजीआई को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाने की मांग के पीछे अदालत को कोई ठोस वजह नजर नहीं आई।

जालंधर में बुजुर्ग से लूट की कोशिश, गुरुद्वारे में बची जान

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। शहर के अजीत नगर में देर रात गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के बाहर बुजुर्ग व्यक्ति से लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। दो बाइक सवार युवकों ने बुजुर्ग को रोककर उसके साथ हाथापाई की। आरोप है कि एक युवक के हाथ में तेजधार हथियार था। बुजुर्ग ने सूझबूझ दिखाते हुए गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाकर खुद को बचाया। घटना थाना नंबर-4 के क्षेत्र में डॉ. बीआर अंबेडकर चौक के पास की बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो युवक बाइक पर आते और फिर वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अपनी एक्टिवा पर सामान रखकर उसे लॉक करने के बाद गुरुद्वारा साहिब की ओर जा रहा था। इसी दौरान दोनों युवक उसके पास पहुंचे। एक युवक ने उसे रोककर धक्का-मुक्की शुरू कर दी। खतरा भांपते हुए बुजुर्ग किसी तरह गुरुद्वारा साहिब के भीतर पहुंचा और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर वहां मौजूद सेवादार तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देखकर दोनों युवक बाइक लेकर फरार हो गए।

पंजाब में पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के नियम बदले, आय संग पद भी बनेगा आधार

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रमाणपत्र बनवाने में लोगों को आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके लिए जिलों के अधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

◆ **पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र में आय, नौकरी, पद और संपत्ति की होगी जांच**

मंत्री ने बताया कि अब पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र केवल परिवार की आय के आधार पर जारी नहीं होगा। इसके लिए माता-पिता की सरकारी नौकरी, पद, सामाजिक स्थिति, पिछले तीन वर्षों की आय और परिवार की संपत्ति सहित विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी। आठ लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। शहरी और ग्रामीण संपत्ति की स्थिति को भी पात्रता तय करते समय देखा जाएगा।

सेवा केंद्रों और पटवारियों को नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही सभी सेवा केंद्रों के बाहर सूचना पट लगाए जाएंगे, ताकि आवेदकों को प्रमाणपत्र की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

मंत्री ने कहा कि विवाह के बाद महिला के प्रमाणपत्र की पात्रता उसके ससुराल की स्थिति से नहीं, बल्कि माता-पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होगी। माता-पिता का प्रमाणपत्र नहीं बना होने पर भी बच्चे का प्रमाणपत्र नियमों के अनुसार बनाया जा सकता है।

जमावड़ा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बढ़ती संख्या से यातायात प्रभावित, आम लोगों को परेशानी

मोहाली फेज 11 में लगातार बढ़ रही किसानों की संख्या

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर लगाया गया पक्का मोर्चा बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पंजाब के अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ मोर्चा स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों की बढ़ती संख्या के कारण आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है। फेज 11 चौक के आसपास सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है।

दूसरे दिन बढ़ी भीड़ : मोर्चे के पहले दिन औपचारिक रूप से मंच का संचालन किया गया था। दूसरे दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक किसान नेता मंच से अपनी मांगों और आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर अपनी बात रखेंगे। किसान नेताओं के संबोधन को सुनने के लिए पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान लगातार पहुंच रहे हैं।

मंगलवार देर रात तक ही काफी संख्या में किसान मोर्चा स्थल पर पहुंच चुके थे। इसके कारण निर्धारित स्थान पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ गई थी। बुधवार सुबह भी किसानों का पहुंचना जारी रहा। इससे मोर्चा स्थल के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती गई।

बड़े नेता होंगे शामिल : किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल और हरिंदर सिंह लखोवाल सहित अन्य किसान नेता बुधवार को मंच से किसानों को संबोधित करेंगे। नेताओं की ओर से किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाने के साथ आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।किसानों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वे लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं।

इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर पक्का मोर्चा लगाया गया है। किसानों के अनुसार मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। किसानों के बड़ी संख्या में पहुंचने के कारण फेज 11 चौक के आसपास यातायात प्रभावित हुआ है।

> **जाम** की स्थिति को देखते हुए आम लोगों को फेज 10 और फेज 11 की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है। खासकर सुबह और दोपहर के समय इन रास्तों पर यातायात का दबाव अधिक रहने की संभावना है। किसानों के लगातार पहुंचने के कारण आने वाले समय में भी क्षेत्र में यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस की ओर से वाहनों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बना हुआ है। बुधवार को किसान नेताओं के संबोधन और आंदोलन की अगली रणनीति पर होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं।

भाजपा का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सुनील शर्मा ने साधा तीखा निशाना

विपक्ष के नेता ने उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की दी चुनौती

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लाल चौक स्थित क्लॉक टावर के पास भाजपा नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी कि वह अपने गृह क्षेत्र गांदरबल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दें और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नए सिरे से जनता के बीच जाकर जनादेश मांगें।

सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर के आम और गरीब लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में पानी का संकट बना हुआ है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिटर और कार्यकारी अभियंता तक उपलब्ध नहीं हैं तो मंत्रियों से उम्मीद करना भी मुश्किल है। विपक्ष के नेता ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है तथा गरीब मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी तरह स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग की।

> **भाजपा** नेता ने कहा कि प्रदेश में जनसमस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए शर्मा ने सवाल किया कि क्या जनता ने उन्हें राजकुमार की तरह रहने और गुलमर्ग तथा पहलगाम में स्कींग करने के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है तो उन्हें गांदरबल सीट से इस्तीफा देकर इसी मुद्दे पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। शर्मा ने कहा कि यदि उमर अब्दुल्ला में आत्मसम्मान है तो वह राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएं और अपना समर्थन साबित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का दर्जा बहाल करना भाजपा का मुद्दा है और पार्टी ने जनता से उचित समय पर इसे बहाल करने का वादा किया है।

बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझते लोग

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है और शिकायतों के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी का असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में बंपर भर्ती का ऐलान, चतुर्थ श्रेणी के 2863 पदों पर मौका

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर सामने आया है। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के 2863 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों को सामान्य प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पांच अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीदवार तीन नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में भर्ती से संबंधित पदों की संख्या, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। चतुर्थ श्रेणी के इन पदों पर भर्ती से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी।

खराब मौसम के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जांच के बाद खोला गया बैटरी कार मार्ग

हल्की बारिश के बीच मां वैष्णो देवी यात्रा जारी जयकारे लगाते भवन की ओर बढ़े श्रद्धालु

भारतेंदु संवाददाता, कटड़ा

सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी यात्रा बुधवार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रही। यात्रा के दौरान बीच-बीच में हल्की बारिश होती रही, लेकिन इससे श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। परिवार और मित्रों के साथ पहुंचे श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे। बीती मंगलवार देर रात हुई झमाझम बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई।

बारिश तेज होने पर श्रद्धालुओं को मार्ग में बनाए गए आश्रय स्थलों में रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ा। मौसम सामान्य होने के बाद श्रद्धालुओं ने फिर से यात्रा शुरू की और जयकारों के साथ भवन की ओर बढ़ते रहे। बारिश को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी रखी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मौसम और मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। बैटरी कार मार्ग को भी सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया। आवश्यक जांच के बाद मार्ग को फिर से खोल दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिली। उधर, खराब मौसम का असर हेलीकाप्टर सेवा पर भी देखने को मिला। मौसम की परिस्थितियों के कारण हेलीकाप्टर सेवा दिनभर प्रभावित रही। हालांकि पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं में माता के दर्शन को लेकर उत्साह बना रहा।

कटड़ा से भवन तक पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही। कई श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए छाते और बरसाती का सहारा लेते नजर आए। मौसम सुहावना होने के कारण यात्रा मार्ग पर वातावरण भी भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं का कहना था कि माता के दर्शन की आस्था के आगे मौसम की परेशानी छोटी है। हल्की बारिश के बावजूद वे उत्साह के साथ यात्रा पूरी कर रहे हैं। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं से मौसम को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से यात्रा जारी रखने का संकल्प जताया।

इंस्पेक्टर संजीत शर्मा बने कटड़ा थाना प्रभारी, रंजीत सिंह राव को दी भावभीनी विदाई

भारतेंदु संवाददाता,कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा स्थित पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने नए एसएचओ के रूप में पदभार संभाल लिया। वहीं, निवर्तमान एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव के स्थानांतरण पर थाना परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। डीएसपी कटड़ा भीष्म दुबे सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राव को भावभीनी विदाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान नवनियुक्त एसएचओ संजीत शर्मा का भी स्वागत किया गया। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव ने करीब 10 माह तक थाना प्रभारी के रूप में कटड़ा में सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल में नशे के खिलाफ अभियान, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। नशा मुक्ति अभियान में कटड़ा को दूसरा स्थान भी मिला।

अनंतनाग में चट्टान गिरी, पर्यटकों की गाड़ी चपेट में आने से एक की मौत

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में बुधवार को पहाड़ी से अचानक लुढ़ककर गिरी चट्टान की चपेट में आने से एक पर्यटक की मौत हो गई। हादसा बमजू दरगाह के पास खानबल-पहलगाम मार्ग पर हुआ। एक अधिकारी के अनुसार, पहलगाम से अनंतनाग की ओर जा रही इनोवा कार (जेके 01एटी-8081) पर अचानक पहाड़ी से चट्टान आ गिरी। वाहन में छह पर्यटक सवार थे। हादसे में एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चालक समेत अन्य पर्यटक सुरक्षित रहे। घायल पर्यटक को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ओडिशा के गंजाम निवासी आर. हिमांशु प्रसाद राव के रूप में हुई है।

राजौरी के गाँव में भालू ने महिला पर किया हमला

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के पीरी क्षेत्र के तरकासी गांव में बुधवार को भालू के हमले में 45 वर्षीय महिला घायल हो गई। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के अनुसार, तरकासी गांव निवासी नजीरा बेगम पर उस समय जंगली भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला के शरीर पर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जम्मू में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, 15 हजार लेते जूनियर असिस्टेंट रंगे हाथ गिरफ्तार

विवाह प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को सहायक आयुक्त (सामान्य) कार्यालय में तैनात जूनियर असिस्टेंट को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान अजय कुमार निवासी गंगो चक, गजनसू, जम्मू के रूप में हुई है।

आरोप है कि उसने विवाह प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। मामले की शिकायत एसीबी के पास पहुंचने के बाद अधिकारियों ने इसकी प्रारंभिक जांच की। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपित को पकड़ने की योजना बनाई। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देने के लिए कहा गया। जैसे ही अजय कुमार ने 15 हजार रुपये स्वीकार किए, वहां मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी अधिकारियों ने आरोपित से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके साथ ही उसके ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई भी की गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिश्वत की मांग केवल इसी मामले में की गई थी या पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में पदोन्नति, 11 इंस्पेक्टरों को मिली डीएसपी रैंक

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में 11 इंस्पेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया। ये सभी इंस्पेक्टर सामान्य कैडर से संबंधित हैं। गृह विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी गई है। अधिकारियों को वेतनमान-8 के तहत 47,600 से 1,51,100 रुपये का वेतनमान मिलेगा। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में शेख आजाद, इम्तियाज अहमद, बशीर अहमद, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अलियास मलिक, संजीव कुमार, मोहम्मद फारूक, बहार अहमद, मुश्ताक अहमद, मीर रियाज अहमद और फारूग अहमद शामिल हैं।

जम्मू में 15 दिन चलेगा ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान

दोपहिया वाहन चालकों पर विशेष नजर, नियम तोड़ने वालों के सीधे काटे जाएंगे चालान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू शहर में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात नियमों की अनदेखी को देखते हुए यातायात पुलिस ने वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस की ओर से एक से 15 सितंबर तक विशेष यातायात अभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान शहर की प्रमुख सड़कों और व्यस्त मार्गों पर विशेष नाके लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों पर नजर रखी जाएगी। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, तीन सवारियां बैठाने, तेज गति से वाहन चलाने और लापरवाही बरतने वाले चालकों के भी चालान किए जाएंगे।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग अब भी इसकी अनदेखी करते हैं। इसी तरह वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकता है। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण भी सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है।

विशेष अभियान के दौरान नाबालिगों के वाहन चलाने पर भी पुलिस की नजर रहेगी। नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ भी जुर्माना और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

कश्मीर में पर्यावरण बचाने के लिए इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

पारंपरिक पर्यटन से पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के बीच कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग तेज हो रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों, आर्द्रभूमियों, पहाड़ों, घास के मैदानों, नदियों और ग्रामीण क्षेत्रों को टिकाऊ पर्यटन का आधार बनाया जा सकता है।

इको-टूरिज्म के तहत प्रकृति भ्रमण, वन्यजीव पर्यटन, पक्षी दर्शन, ट्रेकिंग, शिविर, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति से जुड़े अनुभव विकसित किए जा सकते हैं। इससे पर्यटकों को नए अनुभव मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

स्थानीय पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पर्यटन के बजाय सीमित और जिम्मेदार पर्यटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए पर्यटकों की संख्या, निर्माण गतिविधियों और कचरे पर नियंत्रण जरूरी है।

विशेषज्ञों ने प्रकृति मार्ग, वन भ्रमण, पक्षी दर्शन केंद्र, साइकिल मार्ग, शिविर स्थल, गांव आधारित पर्यटन और होमस्टे विकसित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि नई सुविधाएं स्थानीय पर्यावरण की क्षमता का आकलन करने के बाद ही विकसित की जानी चाहिए। स्थानीय युवाओं को प्रकृति मार्गदर्शक, पक्षी दर्शन विशेषज्ञ, ट्रेकिंग प्रशिक्षक और पर्यटन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देने की भी मांग उठी है।

जम्मू-कश्मीर में पथराव और आतंकी भर्ती में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

पथराव और आतंकी भर्ती में कमी से सुरक्षा स्थिति सुधरी

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई का असर आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2025 के बीच पथराव की घटनाओं में 98.6 प्रतिशत की कमी आई है। 2018 में पथराव के 1,767 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 25 रह गई।

आतंकवाद में युवाओं की भर्ती के मामलों में भी करीब 99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2018 में युवाओं की भर्ती के 199 मामले सामने आए थे, जबकि 2025 में यह संख्या केवल दो रह गई। आतंकी घटनाओं में भी बड़ा सुधार हुआ है। 2018 में 228 आतंकी घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 12 रह गईं। इसी तरह मुठभेड़ों की संख्या 189 से घटकर 33 और मारे गए आतंकियों की संख्या 257 से घटकर 34 रह गई।

सुरक्षा बलों के बलिदान के मामलों में भी कमी आई। 2018 में 91 जवान बलिदान हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या 16 रही। नागरिकों की मौत भी 55 से घटकर 28 रह गई।

वहीं आतंकवाद से जुड़े संदिग्धों और सहयोगियों की गिरफ्तारी बढ़ी है। 2018 में 105 गिरफ्तारियां हुई थीं, जबकि 2025 में 143 लोगों को पकड़ा गया। इसे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज होने का संकेत माना जा रहा है।

तय दरों से महंगी ईंटें बेचने पर भट्ठा मालिकों पर सवाल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम में जिला प्रशासन की ओर से ईंटों के दाम निर्धारित किए जाने के बावजूद ईंट-भट्ठा मालिकों पर कथित तौर पर मनमानी कीमत वसूलने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2020 में तय दर के अनुसार तीन हजार ईंटों की कीमत 21 हजार रुपये थी, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क शामिल था। इसके बावजूद कुछ भट्ठा मालिक तीन हजार ईंटों के लिए 26 से 28 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। बारामूला और श्रीनगर समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों ने इस पर चिंता जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि ईंटों की बढ़ती कीमतों से खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए घर बनाना मुश्किल हो रहा है।

जम्मू विश्वविद्यालय में अब एक साथ दो पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे छात्र

माइग्रेशन प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म, छात्रों को मिली राहत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक पाठ्यक्रम करने की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक लचीलापन और विभिन्न विषयों में ज्ञान हासिल करने का अवसर देना है।

समझौते पर जम्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. नीरज शर्मा, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के कुलसचिव डा. अनिल कुमार और क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के कुलसचिव अंकुर महाजन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. उमेश राय और क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति प्रो. केएस चंद्रशेखर मौजूद रहे। कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति प्रो. बीएन त्रिपाठी ने भी इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।

एनएचएआई टोल फर्जीवाड़े में जम्मू समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित फर्जी वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जम्मू समेत देश के कई हिस्सों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता में की गई। जम्मू में ईडी की टीम ने कारोबारी राकेश चौधरी से जुड़े परिसरों में तलाशी ली। सुबह करीब नौ बजे केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ टीम गांधी नगर ग्रीन बेल्ट स्थित उनके आवास पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने परिसर को घेरकर आवाजाही पर रोक लगा दी। इसके अलावा त्रिकुटा नगर स्थित उनके कार्यालय में भी अभिलेखों की जांच किए जाने की सूचना है। ईडी की जांच एनएचएआई के विभिन्न टोल प्लाजा पर कथित फर्जी टोल संग्रह से जुड़ी है। जांच एजेंसी को आशंका है कि अनधिकृत साफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी या अनधिकृत टोल रसीदें तैयार की गईं। आरोप है कि इस प्रक्रिया से एकत्र धनराशि एनएचएआई की आधिकारिक लेखा प्रणाली से बाहर भेजी गई।

आंदोलन — राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक गारंटी और युवाओं के आरक्षण मुद्दे पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

राज्य दर्जे की मांग को लेकर श्रीनगर में एनसी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक गारंटी देने और युवाओं से जुड़े आरक्षण के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च : एनसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया।

केंद्र से वादे पूरे करने की मांग : एनसी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र में भाजपा नेतृत्व को जम्मू-कश्मीर की जनता से किए गए वादों की याद दिलाना है। उन्होंने कहा कि अब इन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। सादिक ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को उन प्रतिबद्धताओं की याद दिलाना चाहती है, जो जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में संसद और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की गई थीं।

युवाओं के आरक्षण पर जोर

एनसी ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं से जुड़े आरक्षण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। सादिक ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं के लिए पदों के युक्तिकरण से जुड़ी प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। उनके अनुसार रोजगार से जुड़े मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

जनादेश के सम्मान की मांग

एनसी नेता ने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा दिए गए जनादेश और उनके अधिकारों की बहाली की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। एनसी का कहना है कि राज्य का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा, युवाओं के आरक्षण और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने इन मांगों को एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रमुखता से रखा है। एनसी ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं और अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान तनवीर सादिक ने आरोप लगाया कि विभिन्न स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड और प्रतिबंधों के कारण एनसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही कार्यकर्ताओं और लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन रास्तों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। सादिक ने दावा किया कि कई कार्यकर्ताओं को मौके तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने प्रदर्शन को सीमित करने के लिए कई मार्गों पर बैरिकेड लगाए थे।

जलवायु परिवर्तन : बढ़ती जीवनयापन लागत का नया आर्थिक संकट

लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय समस्या माना जाता रहा, लेकिन आज यह आम नागरिकों की आय, आजीविका और जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला गंभीर आर्थिक संकट बन चुका है। भारत में बढ़ती गर्मी, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसमी घटनाएं भोजन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की लागत लगातार बढ़ा रही हैं।

जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में दिखाई देता है। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य एवं पेय पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत है। ऐसे में कमजोर मानसून, भीषण गर्मी और फसलों की क्षति के कारण कृषि उत्पादन घटने पर अनाज, सब्जियां, दालें और खाद्य तेल महंगे हो जाते हैं। इससे आम परिवारों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। कृषि क्षेत्र इस संकट का सबसे बड़ा शिकार है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ के कारण उत्पादकता घट रही है तथा किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कृषि संकट का सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। जब उत्पादन कम होता है तो आपूर्ति बाधित होती है, जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है तथा खाद्य मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन खाद्य उपलब्धता के साथ-साथ उसकी वहनीयता को भी चुनौती देता है। इसका प्रभाव केवल खेती तक सीमित नहीं है। आय में कमी और खर्च में वृद्धि के कारण गरीब परिवारों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आवश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। कई बार कर्ज और मजबूरन पलायन जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र भी तेजी से प्रभावित हो रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर अब आवश्यकता बन गए हैं। इससे बिजली की मांग और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर अधिक बिजली बिल के रूप में पड़ता है। निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए इसका अर्थ अन्य आवश्यक खर्चों में कटौती करना होता है। जल संकट भी जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती बन चुका है। अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में गिरावट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि शहरों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है। इससे घरेलू खर्च बढ़ता है और महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

विशाल कल्याण
सहायक प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सोलन

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसके व्यापक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी, वायु प्रदूषण तथा डेंगू, मलेरिया और हीट स्ट्रोक जैसी जलवायु-संवेदनशील बीमारियों के कारण स्वास्थ्य व्यय बढ़ रहा है। बीमारी से कार्य दिवसों की हानि होती है और परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन का बोझ सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं और कमजोर समुदाय सिंचाई, बीमा, आधुनिक तकनीक तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधिक प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से जलवायु परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और गहरा करता है।

यद्यपि सरकार राहत पैकेज, खाद्य प्रबंधन, फसल बीमा और आपदा सहायता जैसी पहलें कर रही है, फिर भी दीर्घकालिक समाधान के लिए जलवायु-लचीली कृषि, जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा जलवायु न्याय आधारित नीतियों में निवेश आवश्यक है। विशेष रूप से छोटे किसानों, महिलाओं और कमजोर समुदायों को विकास योजनाओं के केंद्र में रखना होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कम पानी में अधिक फसल का लक्ष्य, सूक्ष्म सिंचाई से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 1 जुलाई 2015 को 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल' नामक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

इसके अतिरिक्त यह सूक्ष्म सिंचाई के लिए संसाधन सृजन को पूरा करने हेतु सूक्ष्म स्तर पर जल संचयन और जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों (अन्य हस्तक्षेपों) का भी समर्थन करता है। देश में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना है। उचित जल प्रबंधन के माध्यम से फसल उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना भी अहम है। गन्ना, केला, कपास आदि जैसी जल-संवेदनशील/जल-उपभोक्ता फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत आने वाली फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने पर उचित ध्यान दिया जाता है। उर्वरक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का संभावित उपयोग करना होगा। जल की कमी वाले जल संकटग्रस्त और महत्वपूर्ण भूजल वाले क्षेत्रों/जिलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना होगा। ट्यूबवेल/नदी-उठाने वाली सिंचाई परियोजनाओं को सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों से जोड़ना जरूरी है ताकि उत्थापन और दबावयुक्त सिंचाई दोनों के लिए ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा सके। चल रहे कार्यक्रमों के साथ समन्वय और तालमेल स्थापित करना और गतिविधियों की योजना बनाना, विशेष रूप से सृजित जल संसाधनों के संभावित उपयोग, दबावयुक्त सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के एकीकरण आदि के लिए अनिवार्य है।

कृषि एवं बागवानी विकास के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका प्रसार करना भी इस योजना का एक लाभ है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव के लिए कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य न केवल सुनिश्चित सिंचाई के लिए जल संसाधन सृजित करना है, बल्कि 'जल संचय' और 'जल सिंचाई' के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का उपयोग करके सुरक्षात्मक सिंचाई को बढ़ावा देना भी है।

सूक्ष्म सिंचाई इस योजना का अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के चार प्रमुख घटक हैं— त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रति बूंद अधिक फसल हर खेत तक पानी और जलसंभर विकास। यह योजना कृषि में जल संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिनेश दमाथीआ
स्वतंत्र लेखक

'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के तहत सूक्ष्म स्तर के भंडारण ढांचे, सटीक सिंचाई प्रणाली, कुशल जल परिसंचरण, द्वितीयक जल स्रोतों का उपयोग और जल उत्थापन उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही कृषि गतिविधियों के बेहतर समन्वय और प्रबंधन पर भी जोर दिया जाता है, जिससे जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक खेत तक पानी की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हो। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

जेन-जी को चाहिए वास्तविक भागीदारी

भारतीय राजनीति में जेन-जी को लेकर बढ़ती चर्चा को केवल इंटरनेट मीडिया की देन मानना उचित नहीं होगा। यह चर्चा देश के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में हो रहे एक व्यापक बदलाव का संकेत है। भारत की करीब एक चौथाई आबादी इस पीढ़ी से जुड़ी है। इतनी बड़ी जनसंख्या को राजनीति लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि यह मान लेना भी अतिशयोक्ति होगी कि आने वाले हर चुनाव का परिणाम केवल जेन-जी के रुख से तय होगा। भारतीय चुनावों में आज भी स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, सरकारी योजनाएं, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए जेन-जी को किसी जादुई राजनीतिक शक्ति के रूप में देखने के बजाय बदलती राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझना अधिक उचित होगा।

जेन-जी कोई एकरूप राजनीतिक समूह नहीं है। अलग-अलग राज्यों, भाषाओं, सामाजिक वर्गों और आर्थिक परिस्थितियों में पली-बढ़ी इस पीढ़ी की आकांक्षाएं भी अलग हैं। महानगरों में काम करने वाले युवाओं की प्राथमिकताएं छोटे शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से अलग हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की समस्याएं भी शहरी युवाओं से भिन्न हैं। इसलिए इस पूरी पीढ़ी को किसी एक विचारधारा या राजनीतिक दल के समर्थक के रूप में देखना सही नहीं होगा। फिर भी एक चीज इन्हें व्यापक रूप से जोड़ती है और वह है डिजिटल दुनिया से गहरा जुड़ाव।

जेन-जी ऐसी पहली पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन, इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनते हुए देखा है। इनके लिए सूचना प्राप्त करने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बीच बहुत कम अंतर है। कोई घटना कुछ ही मिनटों में देशभर में चर्चा का विषय बन सकती है। इसी कारण युवाओं की छोटी-सी नाराजगी भी व्यापक जनभावना का रूप ले सकती है। राजनीतिक दलों के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। उन्हें अब केवल चुनावी भाषणों के माध्यम से युवाओं तक पहुंचने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं और आकांक्षाओं को समझना होगा।

दुनिया के कई हिस्सों में युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी इसका संकेत देती है कि नई पीढ़ी केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि सम्मान, पारदर्शिता और भविष्य की सुरक्षा भी चाहती है। तेजी से बदलती तकनीक, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। युवाओं के सामने यह सवाल खड़ा है कि आज हासिल की गई शिक्षा आने वाले वर्षों में उनके लिए कितनी उपयोगी होगी। दूसरी ओर भ्रष्टाचार, अवसरों की असमानता और संस्थाओं पर घटता भरोसा भी असंतोष को बढ़ा रहा है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और सीमित रोजगार अवसर जैसी समस्याएं युवाओं की निराशा को और गहरा करती हैं।

शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। युवाओं से कहा जाता है कि वे पढ़ाई करें, कौशल हासिल करें और कठिन मेहनत करें। लेकिन जब वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है या भर्ती लंबे समय तक अटकी रहती है तो निराशा केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं रह जाती। वह व्यवस्था पर अविश्वास में बदलने लगती है। इसलिए राजनीतिक दल यदि जेन-जी को केवल सामाजिक माध्यमों पर आकर्षित करने के लिए छोटे वीडियो, आकर्षक नारे और आधुनिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो यह पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल संवाद जरूरी है, लेकिन वास्तविक समस्याओं का समाधान उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

युवाओं का भरोसा जीतने के लिए तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा—भरोसा, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी। भरोसा तभी पैदा होगा जब परीक्षाओं और भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो। सरकारी घोषणाओं और वास्तविक परिणामों के बीच दूरी कम करनी होगी। आर्थिक अवसर तभी बढ़ेंगे जब शिक्षा को रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए और उद्योग, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा नई तकनीक में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा हों। उद्यमिता को केवल भाषणों और योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय युवाओं को पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक भागीदारी। युवाओं को केवल चुनावी प्रचार में भीड़ या सामाजिक माध्यमों पर सामग्री तैयार करने वाले कार्यकर्ता के रूप में देखना उनकी क्षमता को सीमित करना है। राजनीतिक दलों को युवाओं को संगठन के महत्वपूर्ण पदों, नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक स्थान देना होगा। जिस पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य है, उसे वर्तमान के फैसलों में भी अपनी आवाज रखने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में नेतृत्व को केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना गया है। आचार्य चाणक्य की राजर्षि की अवधारणा इसी विचार को सामने रखती है। राजर्षि वह शासक है जो सत्ता को निजी अधिकार नहीं, बल्कि जनता की सेवा का दायित्व समझता है। वह अनुशासन में रहता है, आलोचना सुनता है और अपने निर्णयों को जनहित से जोड़ता है।

-शिवांश धाकड़

कविता

आओ उखाड़ फेंकें नशे की जड़ को

-भीम बसेड़ू राजपूत, महादेव (मंडी)

नशेड़ी है मर-मर के जीता,
खून कर रहा अपनों का,
रोज जहर है उसको पीता,
बनता दुश्मन सपनों का।
मीठा लगता नशे का जहर,
धीरे-धीरे जीवन खाता,
चित्ता, सिंथेटिक ड्रग्स के दलदल में,
युवा पीढ़ी को फंसाता।
बुरी संगत में पड़कर देखो,
कैसे घर उजड़ जाते हैं,
हंसते-खेलते परिवारों में,
दुख के बादल छा जाते हैं।
मां-बाप की आंखों के आंसू,
बेटे की राह निहारें,
जिससे घर में खुशियां थीं, वही अपनों को मारे।
नशे की खातिर इंसान कभी, अपने रिश्ते भूल जाता है,
दो पल की झूठी खुशी में,
पूरा जीवन हार जाता है।
आओ मिलकर प्रण हम लें,
नशे की जड़ को काटेंगे,
हर बच्चे और युवा को अब,
सही राह पर हम लाएंगे।

टूटते संयुक्त परिवार व बुजुर्ग मां-बाप के प्रति संतानों की ओर से की जा रही उपेक्षा

अगर हम कुछ समय पूर्व जाएं, तो पाते हैं कि पहले संयुक्त परिवारों का चलन था और आपस में मधुरता एवं सामंजस्य का वातावरण विद्यमान रहता था। उस दौरान यदि परिवार का कोई सदस्य कुछ समय के लिए भी इधर-उधर नहीं दिखाई देता था, तो सभी सदस्य चिंतित हो उठते थे। उस समय वृद्ध माता-पिता की देखभाल संतानें अपना केवल नैतिक नहीं बल्कि परम कर्तव्य समझती थीं।

संयुक्त परिवार संस्कार और सामूहिक जीवन की आधारशिला हुआ करता था, जहां परिवार मात्र एक इकाई नहीं बल्कि आपसी सुख-दुख का मजबूत सहारा होता था। उस समय परिवार की यह व्यवस्था सभी सदस्यों के सहयोग, समर्पण और सहभागिता से चलती थी। बुजुर्गों का स्नेह और अनुभव बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक होता था, जिससे उनमें संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता था। आर्थिक दृष्टि से भी संयुक्त परिवार उपयोगी था, क्योंकि अनेक कमाने वाले सदस्यों के कारण जिम्मेदारियां विभाजित रहती थीं और जीवन अपेक्षाकृत सरल होता था। समय के साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। शिक्षा, रोजगार, शहरीकरण और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह ने संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी और पारिवारिक संवाद कमजोर पड़ता गया। आज की युवा पीढ़ी अनेक बार माता-पिता के साथ रहना बोझ या बाधा के रूप में देखने लगी है, जिसके कारण पारिवारिक एकता पर प्रभाव पड़ा है।

इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव वृद्ध माता-पिता पर पड़ा है। जीवनभर जिन संतान के भविष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया, वही वृद्धावस्था में उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में आर्थिक निर्भरता के बावजूद बुजुर्ग मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति समाज के नैतिक ढांचे पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आज वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा और उनके प्रति दुर्व्यवहार के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। इसी कारण सरकारों को उनके संरक्षण हेतु कई कानून बनाने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश सहित अनेक राज्यों तथा केंद्र सरकार ने 'वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कानून' जैसे प्रावधान लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। फिर भी कानूनों का अस्तित्व यह दर्शाता है कि सामाजिक संवेदनशीलता में कमी आई है।

माता-पिता अपने जीवन की समस्त पूंजी बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और भविष्य निर्माण में लगा देते हैं, यह आशा रखते हुए कि वृद्धावस्था में संतान उनका सहारा बनेगी, परंतु आधुनिक समय में बदलते मूल्य और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कई बार यह अपेक्षा

तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

टूट जाती है, जिससे बुजुर्ग अकेलेपन, असुरक्षा और मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। वृद्धावस्था केवल शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और जीवन के गहन सत्य का संगम होती है। बुजुर्ग परिवार की धरोहर होते हैं और उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। उनके बिना परिवार केवल भौतिक इकाई रह जाता है, जिसमें भावनात्मक गहराई और संस्कारों की कमी महसूस होती है।

समाज के लिए यह आवश्यक है कि बुजुर्गों को केवल देखभाल का विषय न मानकर सम्मान और सहभागिता का केंद्र माना जाए। उनके अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, उनसे संवाद बनाए रखना और उन्हें परिवार का सक्रिय हिस्सा बनाए रखना समय की आवश्यकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

महिला कुश्ती की प्रेरणा बनीं साक्षी

साक्षी मलिक भारतीय कुश्ती की ऐसी दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। उनका जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। उनके पिता दिल्ली परिवहन निगम में बस परिचालक और मां स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थीं। साक्षी को कुश्ती की प्रेरणा अपने दादा बदलू राम से मिली, जो स्वयं पहलवान थे। उन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में कुश्ती का प्रशिक्षण शुरू किया। शुरुआती दौर में सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खेल के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा।

साक्षी मलिक
जन्म : 3 सितंबर 1992

साक्षी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी सफलता 2010 में जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में मिली, जहां उन्होंने 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया। 2014 में डेव शुल्ट्ज अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी वर्ष ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई, हालांकि निर्णायक मुकाबले में उन्हें नाइजीरिया की अमिनत अदेनीयी से हार का सामना करना पड़ा।

2015 में दोहा में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में साक्षी ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद उनका सबसे यादगार दौर 2016 में आया। उन्होंने ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में चीन की झांग लान को हराकर रियो ओलंपिक के लिए जगह बनाई। रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने शुरुआती मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज के जरिए वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में किर्गिस्तान की एशियाई चैंपियन ऐसुलू तिनिबेकोवा को 8-5 से हराया। इस मुकाबले में वह एक समय 0-5 से पीछे थीं, लेकिन शानदार वापसी करते हुए उन्होंने जीत दर्ज की।

ग्रामीण विकास की नई तस्वीर, मजबूत पंचायतों से गांवों में बढ़ी विकास और जनभागीदारी

भारत में ग्रामीण विकास देश को विकसित बनाने की रीढ़ है। पिछले 12 वर्ष में ग्रामीण विकास की दिशा में सराहनीय कार्य हुए हैं, जिसके परिणाम अब पूरे देशभर के ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। पंचायती राज संस्थान और स्थानीय निकास के माध्यम से ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रगति देखने को मिली है, जो पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण चरण है। सक्षम, जवाबदेह और वित्तीय रूप से सशक्त पंचायतों के निर्माण के दृष्टि से पंचायती राज मंत्रालय ने कई पहल की हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को गहरा, डिजिटल शासन का विस्तार, स्थानीय योजना को मजबूत, राजकोषीय हस्तांतरण में वृद्धि और देश भर में ग्रामीण लोगों के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है।

इन वर्षों में संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। इस गति के आधार पर, 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए, 16वें वित्त आयोग ने विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 4,35,236 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत किए गए आवंटन की तुलना में लगभग 84 प्रतिशत ज्यादा है। यह बढ़ा हुआ आवंटन पंचायती राज संस्थानों के राजकोषीय सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ज्ञात रहे कि 2018-19 में शुरू किए गए और 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, तीनों स्तरों पर 2.70 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के 4.10 करोड़ पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों (संचयी) का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पूरा हो गया है, जो ग्रामीण शासन के इतिहास में संस्थागत पहुंच की एक अनोखी उपलब्धि है। आरजीएसए महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण, पेसा प्रशिक्षण और शासन कौशल पहलों की एक श्रृंखला के लिए भी मुख्य आधार रहा है। आरजीएसए के तहत, अकेले वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 33.55 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो उन्हें पंचायत के कामकाज, सेवा वितरण और नेतृत्व के ज्ञान से लैस करता है।

पंचायतों के कामकाज में सुधार के लिए, स्थानीय शासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में पर्याप्त निवेश किया गया है। आरजीएसए और संशोधित आरजीएसए के तहत 25,100 से अधिक ग्राम पंचायत भवन और 61,000 से अधिक कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं, जिससे पंचायती राज संस्थानों की भौतिक और डिजिटल दोनों क्षमताओं में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को सहभागी ग्राम नियोजन के प्राथमिक साधन के रूप में संस्थागत किया गया है, जिसमें 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जा रही हैं।

ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीपीडीपी के डिजिटल एकीकरण ने स्थानीय विकास योजना की पारदर्शिता और पहुंच में और सुधार किया है। इस अवधि की सबसे परिवर्तनकारी पहलों में से एक स्वामित्व योजना रही है। 2020 में शुरुआत के बाद से, इस योजना ने बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणों को सक्षम किया है और 10 जून 2026 तक 1.92 लाख गांवों में लगभग 3.18 करोड़ संपत्ति स्वामित्व कार्डों के वितरण की सुविधा प्रदान की है।

ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन के डिजिटल परिवर्तन का भी नेतृत्व किया है, जिसने पंचायतों में योजना, बजट, लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया है। 2.59 लाख से अधिक पंचायतों को ई-पंचायत ईकोसिस्टम में शामिल किया गया है, जबकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण ने वास्तविक समय की वित्तीय निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सक्षम किया है। 10 जून 2026 तक, एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित किया गया है, जिससे पंचायत वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी सुधार हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 15वें वित्त आयोग (2020-26) के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.82 लाख करोड़ रुपए का अनुदान मिला, जो कुल आवंटन का 94.98 प्रतिशत है। यह स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

डॉ. नितिका शर्मा
भोरंज, जिला हमीरपुर

पंचायत उन्नति सूचकांक आधारित 'सभासार' जैसे डिजिटल नवाचारों ने ग्राम स्तर पर पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है। वहीं पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिली है।

महिला नेतृत्व और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई पहलें की गई हैं। इससे पंचायतें अब विकास, सेवा वितरण और लोकतांत्रिक भागीदारी का मजबूत आधार बन चुकी हैं। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

ट्रेन की चपेट में आने से दो रेलवे कर्मियों की मौत

एजेंसी, मीरजापुर

चुनार कोतवाली क्षेत्र के पिरल्लीपुर गांव के पास मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से डीएफसीसी रेलवे के ठेकेदार के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतकों की पहचान पिरल्लीपुर गांव निवासी रामशरण राजभर (35) और इंदरपुर कुसुम्ही निवासी रणजीत कुमार (24) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों कर्मचारी रात में रेलवे ट्रैक की निगरानी और पेट्रोलिंग के लिए ड्यूटी पर थे। मंगलवार रात करीब 11 बजे दोनों पिरल्लीपुर गांव के पास ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से गुजर रही अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही कजरहट चौकी प्रभारी सदानंद सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण करने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लिया। मृतकों के स्वजन को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस हादसे के कारणों और उस समय वहां से गुजरने वाली ट्रेनों की जानकारी जुटा रही है। डीएफसीसी रेलवे के ठेकेदार के अधीन कार्यरत दोनों कर्मचारियों की मौत की सूचना से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अज्ञात ट्रेन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और रेलवे से मिली जानकारी के आधार पर हादसे में शामिल ट्रेन का पता लगाने में जुटी है।

न्यूज ब्रीफ

तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने गनमैन को मारी टक्कर, मौत

एजेंसी, अमेठी। रामगंज थाना क्षेत्र के रामगंज कस्बे में बुधवार सुबह तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार की टक्कर से ड्यूटी से घर लौट रहे गनमैन की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के कोहंडौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी मोहन लाल मौर्य (55) के रूप में हुई है। वह सुल्तानपुर स्थित श्रीराम फाइनेंस कंपनी में गनमैन के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटते समय रामगंज बाजार में अनियंत्रित कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मोहन लाल को स्थानीय लोगों ने सीएचसी रामगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए गौरीगंज भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक रामराज कुशवाहा ने बताया कि फरार कार चालक की तलाश की जा रही है।

यूपी के रायबरेली में लगातार बारिश के बीच मकान ढहा, वृद्ध की मौत

एजेंसी, रायबरेली। जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच चंदापुर थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव में मंगलवार रात कच्ची दीवार ढहने से 85 वर्षीय वृद्ध रघुनाथ की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार भोजन के बाद वह घर में सो रहे थे। रात करीब एक बजे अचानक दीवार गिरने से वह मलबे में दब गए। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह राजस्व और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पूर्वी-पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी वर्षा

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दो से छह सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। तीन से छह सितंबर के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बौछारों के साथ भारी वर्षा की संभावना है। बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर, इटावा, आगरा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। प्रयागराज, कौशांबी, वाराणसी, मिर्जापुर समेत अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।

घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

एजेंसी, इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र के परमधाम गांव में घर से करीब 60 फीट दूर चारपाई पर सो रहे 60 वर्षीय सिद्ध स्वरूप की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह पुत्र अनिल कुमार ने पिता को चारपाई पर लहूलुहान मृत अवस्था में देखा। चारपाई के पास फावड़ा भी पड़ा मिला। परिजनों के अनुसार उनकी किसी से रंजिश नहीं थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अवनीश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।

राम मंदिर ट्रस्ट में तीन सदस्यों की नियुक्ति से खाली पद हुए पूरे

एजेंसी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाली पड़े तीन सदस्य पदों पर बुधवार को नियुक्तियां की गईं। मणिराम दास जी की छावनी में आयोजित ट्रस्ट की बैठक में तीनों पदों को भरने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट की बैठक के दौरान अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरि, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और महंत दिनेन्द्र दास समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नियुक्त किए गए तीन सदस्यों में अयोध्या के अलावा दिल्ली और शिकोहाबाद से सदस्य शामिल हैं। बैठक को देखते हुए मणिराम दास जी की छावनी और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। नवनियुक्त सदस्यों से राम मंदिर से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग की अपेक्षा की गई है। बैठक के दौरान परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की।

तकनीक, नवाचार और निवेश के जरिए कानपुर को नई पहचान दिलाने की तैयारी

कानपुर बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र

एजेंसी, कानपुर

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर (यूपीडीआइसी) में कानपुर की भूमिका और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण मंथन हुआ। बिठूर स्थित होटल इंटर्ननिटी में आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की ओर से 'स्ट्रैटेजिक उत्तर प्रदेश' क्षेत्रीय रक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कानपुर को रक्षा उत्पादन, तकनीक और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सांसद रमेश अवस्थी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया।

कार्यशाला में स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शोध एवं विकास संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने रक्षा क्षेत्र में कानपुर की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और स्थानीय उद्यमों की संभावनाओं पर विस्तार से विचार रखा। साथ ही यूपीडीआइसी के माध्यम से जिले में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि डिफेंस कारिडोर का लाभ केवल बड़े निवेशकों और प्रमुख कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कानपुर के स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई को भी रक्षा उपकरणों और उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना जरूरी है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे तथा उन्हें रक्षा क्षेत्र के लिए उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। कार्यशाला में रक्षा उत्पादन के साथ तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

विशेषज्ञों ने कहा कि बदलते समय में रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और स्थानीय स्तर पर विकसित समाधानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कानपुर के औद्योगिक आधार का उपयोग कर नए उत्पाद और तकनीकी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। कानपुर पहले से ही विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में डिफेंस कारिडोर के विस्तार से यहां मौजूद उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ने की व्यापक संभावनाएं हैं।

स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ कुशल और तकनीकी रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कार्यशाला में प्रशासन, उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय पर भी बल दिया गया। प्रतिभागियों ने माना कि निवेश आकर्षित करने के साथ उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं, तकनीकी सहयोग और बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है।

जनता के संघर्ष और सपनों का जीवंत दस्तावेज है संविधान : डॉ . अरविंद

एजेंसी, वाराणसी। भारतीय संविधान केवल कुछ विद्वानों द्वारा लिखी गई किताब नहीं, बल्कि देश की जनता की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों का जीवंत दस्तावेज है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आम जनता की सक्रिय भागीदारी रही। देश के विभिन्न हिस्सों से मिले सुझावों, पत्रों, ज्ञापनों और जनआंदोलनों ने संविधान को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान किया।

यह बात यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूके के लेक्चरर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो एवं एसोसिएट फेलो डॉ. अरविंद कुमार ने कही। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार को सामाजिक विज्ञान संकाय के स्मार्ट क्लास में 'भारतीय संविधान के निर्माण में जनभागीदारी को समझना' विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि संविधान को केवल संविधान सभा की बहसों तक सीमित करके देखना इसके व्यापक जनसरोकारों को नजरअंदाज करना होगा।

संविधान सभा की लगभग दो वर्ष 11 माह 18 दिन चली विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों के हजारों पत्रों, ज्ञापनों और सुझावों ने संविधान के स्वरूप को प्रभावित किया। जनता की अपेक्षाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की मांगों ने मौलिक अधिकारों तथा नीति-निर्देशक तत्वों के निर्माण को दिशा दी। उन्होंने युवाओं से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की भावना व्यवहार में उतारना ही संविधान के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता है।

24 दिन से धरने पर किसान, राकेश टिकैत से समाधान की उम्मीद

एजेंसी, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद तहसील प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना बुधवार को 24वें दिन भी जारी रहा। लंबे समय से धरने पर बैठे किसान अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष समस्याएं रखने के बावजूद अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

बुधवार को किसानों ने धरना स्थल पर स्वयं साफ-सफाई अभियान चलाया। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी चंद्रेश ने बताया कि गुरुवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सादाबाद तहसील परिसर में पहुंचेंगे। उनके आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर धरना स्थल तथा आसपास के परिसर की सफाई की गई, ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जा सके।

किसानों ने बताया कि राकेश टिकैत के सामने क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याओं और लंबित मांगों को रखा जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी समस्याओं को सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाएंगे तथा मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाएंगे। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है।

जन्माष्टमी पर काशी-मथुरा के बीच फिर मजबूत हुआ आध्यात्मिक संबंध

एजेंसी, वाराणसी

◆ **इस** अवसर पर दोनों धार्मिक केंद्रों से जुड़े संतों और श्रद्धालुओं ने इस पहल को सनातन संस्कृति की एकता और परंपराओं के संरक्षण का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। दोनों धामों के बीच यह आध्यात्मिक संवाद भविष्य में भी निरंतर जारी रखने पर जोर दिया गया।

सनातन संस्कृति के दो प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र काशी और मथुरा के बीच श्रद्धा, समर्पण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की पावन परंपरा को इस वर्ष भी आगे बढ़ाया गया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान को श्रद्धापूर्वक प्रेषित की गई। इस पहल के माध्यम से दोनों धार्मिक केंद्रों के बीच स्थापित आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूती मिली है।

श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर से भेजी गई भेंट सामग्री को श्रीकृष्ण जन्मस्थान न्यास को सौंपने के लिए प्रेषित किया गया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर काशी से मथुरा भेजी गई इस भेंट को श्रद्धालुओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल बताया।

काशी और मथुरा दोनों ही सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं। एक ओर काशी भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के रूप में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह परंपरा वर्ष 2024 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुरू की गई थी। उस समय श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री विश्वेश्वर की ओर से श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में विराजमान श्री लड्डू गोपाल के लिए उपहार सामग्री भेजी गई थी। इसके बाद इस पहल को धार्मिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की निरंतर परंपरा के रूप में आगे बढ़ाया गया। इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर भेंट भेजकर इस परंपरा को कायम रखा गया। इसके अलावा रंगभरी एकादशी के अवसर पर भी काशी और मथुरा के बीच परस्पर भेंट तथा श्रद्धा-संदेशों का आदान-प्रदान किया गया था।

इससे दोनों धार्मिक केंद्रों के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव को नई मजबूती मिली। धार्मिक आयोजनों के माध्यम से काशी और मथुरा के बीच स्थापित यह संबंध केवल भेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति, परंपराओं और साझा आध्यात्मिक विरासत के आदान-प्रदान का प्रतीक भी बन रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम से भेजी गई विशेष भेंट के माध्यम से भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण की नगरी के बीच श्रद्धा का यह सेतु और मजबूत हुआ है।

वाराणसी में गंगा खतरे के निशान की ओर, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता

एजेंसी, वाराणसी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 10 बजे केंद्रीय जल आयोग के राजघाट गेज पर जलस्तर 70.32 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 70.260 मीटर से ऊपर है। गंगा का पानी सभी 84 घाटों को पार कर आसपास के मंदिरों, गलियों और सड़कों तक पहुंच गया है। अस्सीघाट से नगवां मोड़ की सड़क तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर वरुणा नदी पर भी पड़ा है। पलट प्रवाह के कारण सलारपुर, पुराना पुल, पुलकोहना, हुकुलगंज, बघवानाला और ढेलवरिया समेत कई निचले क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया है। कई परिवार सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंच गए हैं।

जिला प्रशासन ने 13 राहत शिविर सक्रिय किए हैं, जहां 219 परिवारों के 935 लोग रह रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव के लिए 32 नावें लगाई गई हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, जल पुलिस और अन्य विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। गंगा में नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की है।

बारिश का कहर: कच्चे मकान गिरने से दो वृद्ध महिलाओं की मौत

एजेंसी, फरीदाबाद। सेक्टर-49 स्थित अचीवर्स सोसाइटी के करीब 500 परिवार पिछले दो दशकों से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। सोसाइटी में सार्वजनिक जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत अब हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने फरीदाबाद नगर निगम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अधिकारियों से यह बताने को कहा गया है कि सोसाइटी में इतने लंबे समय से सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति क्यों नहीं हो सकी और समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। आयोग ने निवासियों को तत्काल राहत देने के लिए सोसाइटी में पानी के टैंकर भेजने के निर्देश भी दिए हैं। लंबे समय से जलापूर्ति की सुविधा नहीं मिलने के कारण यहां रहने वाले लोगों को पीने और घरेलू जरूरतों के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि गर्मी और अन्य मौसम में पानी की कमी के कारण परेशानी और बढ़ जाती है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। आयोग ने संबंधित विभागों को समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाने को कहा है। अब अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। आयोग ने अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने और सोसाइटी में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

◆ **जीडीए की मंजूरी से लंबित भवन मानचित्रों का होगा निस्तारण।**

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया। लखनऊ के केकेसी स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क किनारे बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

पुलिस ने बाद में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बसों में बैठाकर धरना स्थल ईको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकें। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। उनका आरोप है कि भर्ती का परिणाम आने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ व्यापक स्तर पर अन्याय हुआ और कई अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए।

इसके बाद लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया के बीच 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मामला वहां लंबित है। इस प्रकरण पर आठ सितंबर को सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने भर्ती में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, लेकिन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली।

साझेदारी — उत्तर प्रदेश और जर्मनी के बीच निवेश व औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में जर्मनी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश और जर्मनी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, नवाचार, कौशल विकास और औद्योगिक सहयोग के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए किन क्षेत्रों में साथ मिलकर काम किया जा सकता है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हों और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। उन्होंने जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताया।

बैठक में नवाचार और तकनीकी सहयोग को लेकर भी विचार साझा किए गए। जर्मनी की औद्योगिक विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध निवेश की संभावनाओं को जोड़कर नए क्षेत्रों में साझेदारी विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कौशल विकास के क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने और निवेश के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया।

जर्मन निवेश से यूपी में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

बैठक में दोनों पक्षों ने औद्योगिक क्षेत्र में संभावित संयुक्त परियोजनाओं को लेकर भी विचार साझा किए। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अवसरों में रुचि दिखाई। इस दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान तथा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

प्रयागराज से चलने वाली विशेष ट्रेनों में बढ़ीं अतिरिक्त बर्थ, यात्रियों को राहत

एजेंसी, प्रयागराज

◆ **रेलवे ने यात्रियों को दी राहत, प्रयागराज की दो विशेष ट्रेनों में बढ़ाया स्लीपर कोच।**

यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध कराने और प्रतीक्षासूची कम करने के लिए रेलवे ने प्रयागराज से चलने वाली दो विशेष ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बुधवार को बताया कि इससे यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी।

गाड़ी संख्या 04113 प्रयागराज-एसएसएस हुब्बल्ली विशेष ट्रेन में पांच सितंबर से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इसके बाद ट्रेन में कोचों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04114 एसएसएस हुब्बल्ली-प्रयागराज विशेष ट्रेन में यह बदलाव आठ सितंबर से लागू होगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 04119 सूबेदारगंज-वलसाड विशेष ट्रेन में भी पांच सितंबर से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। इससे ट्रेन में कोचों की संख्या 19 से बढ़कर 20 हो जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04120 वलसाड-सूबेदारगंज विशेष ट्रेन में अतिरिक्त कोच छह सितंबर से लगाया जाएगा।

रेलवे के अनुसार, विशेष ट्रेनों में कोच बढ़ाने का उद्देश्य यात्रियों को अधिक बर्थ उपलब्ध कराना और प्रतीक्षासूची को कम करना है। बढ़ती यात्री संख्या के बीच इस फैसले से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, परिचालन संबंधी कारणों से गाड़ी संख्या 04159 प्रयागराज-विशाखापट्टनम साप्ताहिक विशेष ट्रेन के चार सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाले फेरे निरस्त रहेंगे। वापसी में गाड़ी संख्या 04160 विशाखापट्टनम-प्रयागराज के पांच सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार के फेरे भी रद्द किए गए हैं।

हरियाणा में शामलात जमीन घोटाले पर बड़ा एक्शन 112 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

सात सरकारी कर्मचारियों समेत 112 आरोपियों पर शामलात भूमि घोटाले में कार्रवाई हुई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद ने पलवल जिले के फास्टक् नगर में शामलात देह की भूमि की कथित अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने जांच पूरी करने के बाद सात तत्कालीन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत कुल 112 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान यानी आरोपपत्र पेश किया है।

आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से शामलात भूमि को नियमों के विपरीत बेचने और खरीदने का रास्ता साफ किया गया, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। ब्यूरो की ओर से यह आरोपपत्र पलवल की अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

मामले में तत्कालीन तहसीलदार होडल नरेश जोवल, मनबीर सिंह और ओम प्रकाश गोदारा को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क भगवान सिंह और भूप सिंह, तत्कालीन पटवारी ताराचंद तथा तत्कालीन गिरदावर वीरेंद्र सिंह भी आरोपियों में शामिल हैं।

105 ग्रामीण, विक्रेता और खरीदार भी आरोपी: मामले में सरकारी कर्मचारियों के अलावा 105 ग्रामवासी, विक्रेता और खरीदारों को भी आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो के अनुसार शामलात भूमि की खरीद-फरोख्त में नियमों की अनदेखी और कथित मिलीभगत के माध्यम से सरकारी भूमि के स्वरूप को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों और भूमि से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इसके आधार पर आरोपियों की भूमिका निर्धारित करते हुए अदालत में चालान पेश किया गया है।

कई गंभीर धाराओं में मामला: आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी, 409, 467, 468 और 471 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित 13(2) तथा पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट, 1961 की धारा 13-ए के तहत भी कार्रवाई की गई है। इन धाराओं में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी पद का दुरुपयोग और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद शामलात भूमि से जुड़े मामलों में सरकारी स्तर पर निगरानी और सख्त होने की उम्मीद है। शामलात देह की जमीन का उपयोग आमतौर पर गांव के सामुदायिक हितों से जुड़ा होता है।

बरवाला औद्योगिक क्षेत्र में आइसीएल के पीसीबी प्लांट में लगी भयंकर आग

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

जिले के बरवाला स्थित अलीपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को आइसीएल कंपनी के पीसीबी प्लांट नंबर एक और दो में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में दोनों प्लांट आग की चपेट में आ गए। प्लांट में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए पंचकूला के अलावा आसपास के शहरों से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। चार शहरों की फायर ब्रिगेड टीमों ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग स्थानों से आग पर पानी डालना शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी विकराल थी कि प्लांट से काफी ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। टीमों ने पहले आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोकने का प्रयास किया और इसके बाद प्रभावित क्षेत्र में पानी की बौछार की।

कई दमकल गाड़ियों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें घटना स्थल पर मौजूद रहीं। अधिकारियों ने प्लांट के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और आग से प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण किया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग के कारणों और नुकसान का आकलन जारी है। दमकल विभाग ने प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।

चिंटेल्स पैराडिसो के नए फ्लैटों का रास्ता खुला, 48 महीने में पूरा होगा पुनर्निर्माण

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान फ्लैट खरीदारों और चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड के बीच पिछले करीब साढ़े चार साल से चल रहे विवाद का समाधान हो गया। इसके साथ ही परियोजना के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, मौजूदा परियोजना में 532 फ्लैट हैं, जबकि पुनर्निर्माण के बाद नई परियोजना में करीब 800 फ्लैट बनाए जाने की योजना है। निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च या अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। नई परियोजना के निर्माण को करीब 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान फ्लैट मालिकों को निर्धारित शर्तों के अनुसार शिफ्टिंग खर्च और किराये की सुविधा दिए जाने की बात सामने आई है। इससे लंबे समय से अपने घरों को लेकर असमंजस में रह रहे निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

चिंटेल्स पैराडिसो में वर्ष 2022 में एक टावर के हिस्से में गंभीर हादसा होने के बाद परियोजना की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद फ्लैट खरीदारों और बिल्डर के बीच विवाद बढ़ गया था। मामला विभिन्न स्तरों से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब अदालत में समाधान के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। फ्लैट मालिकों को उम्मीद है कि नई परियोजना सुरक्षित मानकों के अनुरूप तैयार होगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान मिल सकेगा।

नकली एशियन पेंट कारोबार का भंडाफोड़, 233 बाल्टियां बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

डबुआ कालोनी में नकली पेंट की सप्लाई की शिकायतों के बाद क्राइम ब्रांच एनआईटी ने बुधवार को दो दुकानों पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने दोनों स्थानों से एशियन पेंट्स के नाम और पैकिंग वाली 79 भरी हुई तथा 154 खाली बाल्टियां बरामद की हैं। इसके अलावा ढक्कन, लॉक और हैंडल भी मिले हैं। पुलिस ने सामान कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि डबुआ कालोनी की कुछ दुकानों पर एशियन पेंट्स के नाम और पैकिंग का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें ग्राहकों को असली कंपनी का पेंट बताकर बेचने की आशंका थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच एनआईटी की टीम ने ए-ब्लॉक में मकान नंबर 843 के पास स्थित एक दुकान पर तलाशी ली।

डबुआ में नकली पेंट का शक, पुलिस ने दो दुकानों से सामान किया जब्त।

दुकान पर मौजूद बबलू ने पुलिस को बताया कि दुकान प्रदीप की है और वह पारिवारिक काम से आगरा गया हुआ है। तलाशी के दौरान अलग-अलग उत्पादों के नाम वाली 79 भरी बाल्टियां मिलीं। पुलिस ने जांच के लिए पेंट के नमूने भी सुरक्षित किए। इसके बाद टीम डबुआ-भाखरी रोड स्थित गांव भाखरी की दूसरी दुकान पर पहुंची।

रेलवे ट्रैक पर फंसी कार आरपीएफ ने हटाकर सुरक्षित कराया इंजन का रास्ता

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। शहर में रेलवे फाटक बंद होने के दौरान एक हुंडई कार रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। अचानक कार के ट्रैक पर अटक जाने से फाटक के दोनों ओर खड़े वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कार चालक जल्दबाजी में रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान फाटक बंद हो गया और कार रेलवे लाइनों के बीच फंस गई। चालक ने वाहन को वहां से निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। स्थिति को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार को ट्रैक से दूर हटाया, जिसके बाद रेलवे इंजन को सुरक्षित तरीके से क्रॉसिंग से गुजारा गया। समय रहते कार हटाए जाने से बड़ा हादसा टल गया।

हथनीकुंड बैराज में ट्रेनिंग के दौरान पलटी मोटर बोट, दो कमांडो अब भी लापता

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

हथनीकुंड बैराज में मंगलवार शाम प्रशिक्षण के दौरान मोटर बोट पलटने के बाद लापता हुए दो कमांडो की तलाश बुधवार सुबह तक जारी रही। हादसे को करीब 14 घंटे बीत जाने के बावजूद दोनों कमांडो का कोई सुराग नहीं मिल सका है। उनकी तलाश के लिए सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और उत्तर प्रदेश से पहुंची पीएसी की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।

मंगलवार शाम प्रशिक्षण के दौरान कमांडो मोटर बोट के जरिये बैराज क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मोटर बोट पलट गई। हादसे के बाद कुछ जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो कमांडो पानी में लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने अभियान शुरू किया।

बचाव दल मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी गई।

पूरी रात हेलिकॉप्टर से निगरानी: लापता कमांडो की तलाश के लिए रातभर अभियान चलाया गया। हेलिकॉप्टर के माध्यम से पश्चिमी यमुना नहर और हथनीकुंड बैराज क्षेत्र की निगरानी की गई। बचाव दलों ने बैराज के गेट के आसपास, पानी के तेज बहाव वाले हिस्सों और नहर के किनारों पर भी खोजबीन की। अंधेरा होने के बावजूद बचाव दलों ने अभियान जारी रखा। बुधवार सुबह भी तलाशी अभियान में तेजी लाई गई। पानी के बहाव और बैराज की संरचना को देखते हुए बचाव दल बेहद सावधानी से अभियान चला रहे हैं। सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पानी में संभावित स्थानों पर तलाश कर रही हैं।

कई एजेंसियां जुटीं: हादसे के बाद दो कमांडो के लापता होने से प्रशासन में भी चिंता बढ़ गई है। तलाश अभियान में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश से आई पीएसी की टीमें शामिल हैं। सभी संभावित स्थानों पर एक साथ खोज की जा रही है। हेलिकॉप्टर से ऊपर से निगरानी कर बचाव दलों को संदिग्ध स्थानों की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन की ओर से अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है।

न्यूज ब्रीफ

विधानसभा सत्र के बाद भड़के भूपेंद्र हुड्डा बोले- सदन में परोसा गया झूठ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र के हंगामेदार समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में कई मुद्दों पर सच्चाई के बजाय झूठ परोसा गया। उन्होंने सरकार के रवैये को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। हुड्डा ने कहा कि अपने करीब 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में उन्होंने विधानसभा के भीतर ऐसा अलोकतांत्रिक रवैया कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर सरकार ने उचित जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी सरकार से जवाब मांगती रहेगी।

शिवा बिल्डटेक पर ईडी का शिकंजा, गुरुग्राम में कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी शिवा बिल्डटेक के गुरुग्राम स्थित कई ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। कार्रवाई का नेतृत्व करीब पांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें कंपनी से जुड़े परिसरों के साथ दोनों निदेशकों के आवास पर भी पहुंची हैं। तलाशी के दौरान अधिकारियों की ओर से कंपनी के दस्तावेज, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। ईडी की टीम सुबह से ही संबंधित परिसरों में मौजूद है और जांच जारी है। हालांकि, तलाशी किस मामले से जुड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

आरटीआई जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर तत्कालीन राज्य जन सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार सतीश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने मामले में विभाग को कड़ी फटकार भी लगाई। मामला गुरुग्राम के डीएलएफ निवासी हरिंदर धींगड़ा की ओर से 7 नवंबर 2022 को दाखिल किए गए आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। आवेदन में कुछ प्रशासनिक जानकारियां मांगी गई थीं। नियमानुसार जानकारी 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना जरूरी था, लेकिन तत्कालीन अधिकारी निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दे सके। सुनवाई के दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने जानकारी की उपलब्धता साबित करने के लिए चैटजीपीटी और गूगल सर्च का सहारा लिया, लेकिन आयोग के समक्ष यह प्रयास प्रभावी नहीं रहा।

फरीदाबाद की 500 परिवारों वाली सोसाइटी को 20 साल से पानी नहीं, आयोग सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-49 स्थित अवीर्स सोसाइटी के करीब 500 परिवार पिछले दो दशक से पेयजल संकट झेल रहे हैं। सार्वजनिक जलापूर्ति नहीं मिलने की शिकायत पर हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने नगर निगम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण से जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही सोसाइटी के निवासियों को तत्काल राहत देने के लिए पानी के टैंकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से पानी की समस्या के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने अधिकारियों से समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मामले में आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी।

28वें दिन भी सफाईकर्मियों की हड़ताल, कहीं हाथापाई तो कहीं सरकारी जीप पर हमला

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 28वें दिन भी जारी है। मंगलवार को हड़ताल के 27वें दिन प्रदेश के कई जिलों में वैकल्पिक सफाई व्यवस्था को लेकर सफाईकर्मियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कैथल, जींद और हिसार में विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ गया। वहीं, फतेहाबाद में पुलिस सुरक्षा के बीच कूड़ा उठाने का काम कराया गया।

हरियाणा में सफाईकर्मियों की हड़ताल उग्र, कई जिलों में टकराव से प्रशासन की बढ़ी चिंता।

कैथल जिले के सीवन में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर लौट रहे नगरपालिका अधिकारियों की सरकारी जीप पर सफाई कर्मचारियों और उनके स्वजन द्वारा कथित तौर पर कस्सी से हमला किया गया। हमले में जीप का पिछला शीशा टूट गया। वाहन में सवार कनिष्ठ अभियंता और लिपिक बाल-बाल बच गए। घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई। उधर, जींद में चार दिन बाद कूड़ा उठाने के लिए पहुंचे ठेकेदार के कर्मचारियों को हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।

इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। हिसार में भी कचरा उठाने के दौरान सफाईकर्मियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इस दौरान पांच पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कूड़ा उठाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। फतेहाबाद में प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाकर कूड़ा उठवाया। हड़ताल लंबी खिंचने के कारण कई शहरों और कस्बों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए आंदोलन के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आम लोगों की सुविधाओं को प्रभावित करना उचित नहीं है। प्रशासन ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

15 सितंबर से धान खरीद शुरू करने की मांग, फतेहाबाद में किसानों का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति और हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों, खेत मजदूरों और पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान प्रतिनिधियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सात सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो प्रदेशभर में किसानों और मजदूरों को लामबंद कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

ज्ञापन में किसानों ने हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में परमल धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की प्रमुख मांग उठाई। उनका कहना है कि समय पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों ने धान में 20 प्रतिशत तक नमी स्वीकार करने और पूरी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना अनुचित कटौती खरीद सुनिश्चित करने की मांग की।

फतेहाबाद में किसानों का प्रदर्शन, धान खरीद जल्द शुरू करने की मांग।

इसके साथ ही नरमा और कपास की सरकारी खरीद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एमएसपी पर समय से शुरू करने की मांग की गई। किसान प्रतिनिधियों ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि लंबित भुगतान तुरंत ब्याज सहित जारी किया जाए। भविष्य में भुगतान में देरी होने पर किसानों को ब्याज देने का स्थायी प्रावधान बनाया जाए। साथ ही गन्ने के लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की गई।

पशुपालकों के हितों को लेकर भी किसानों ने आवाज उठाई। दुग्ध क्षेत्र में मिलावट पर रोक लगाने के साथ वीटा सहित अन्य दुग्ध संस्थानों की खरीद व्यवस्था और वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदर्शन में जिला प्रधान ओम प्रकाश हसंगा समेत अनेक किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों ने सरकार से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

कैथल के डेरे में साधु की हत्या, शरीर पर मिले चोट के निशान

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। हरियाणा के कैथल जिले के गांव बाबा लदाना स्थित बाबा राजपुरी डेरे में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है। डेरे के विश्राम गृह में साधु का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान थे और बाल भी उखड़े हुए पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अनुयायी मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। अनुयायियों ने डेरे के मुख्य महंत दूज पुरी पर साधु को जंजीरों से बांधकर पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिगरेट उठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद साधु के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पिटाई के दौरान साधु की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद डेरे में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट ने पूर्व सेवा को पेंशन योग्य माना, कर्मचारियों को राहत

2006 से पहले की पार्ट टाइम, एडहॉक, अस्थायी और अनुबंधित सेवा को पेंशन योग्य सेवा माना गया

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 46 याचिकाओं का निपटारा करते हुए कर्मचारियों से जुड़े मामलों को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर फैसला सुनाया। इनमें तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एक श्रेणी के कर्मचारियों की मांग को अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट के फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष राहत मिली है, जिन्होंने 1 जनवरी 2006 से पहले पार्ट टाइम, एडहॉक, अस्थायी या अनुबंध के आधार पर सेवा की थी और बाद में नियमित नियुक्ति प्राप्त की। अदालत ने ऐसी पूर्व सेवा को पेंशन के लिए योग्य सेवा मानने का रास्ता साफ किया है। इससे संबंधित कर्मचारियों की पेंशन गणना में उनकी पूर्व सेवा को शामिल किया जा सकेगा।

पुरानी पेंशन से संबंधित कर्मचारियों की ओर से दाखिल 46 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत ने मामलों की प्रकृति के आधार पर उन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया।

इनमें तीन श्रेणियों के कर्मचारियों के पक्ष में राहत दी गई, जबकि एक श्रेणी की मुख्य मांग को खारिज कर दिया गया। कर्मचारियों की ओर से 28 अक्टूबर 2005 की निर्धारित कटऑफ तारीख को बदलकर 18 अगस्त 2008 करने की मांग भी उठाई गई थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

यानी संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कटऑफ तारीख में बदलाव नहीं किया गया। फैसले का अहम पहलू उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने नियमित होने से पहले विभिन्न अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत काम किया था। 1 जनवरी 2006 से पहले पार्ट टाइम, एडहॉक, अस्थायी या अनुबंध के आधार पर की गई सेवा और उसके बाद नियमित नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों की इस पूर्व सेवा को पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाएगा। इससे ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ की गणना में फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन और प्रभावित कर्मचारी अपनी पूर्व सेवा को पेंशन में शामिल करने की मांग करते रहे हैं।

हालांकि अदालत ने सभी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया। 28 अक्टूबर 2005 की कटऑफ तारीख को 18 अगस्त 2008 तक बढ़ाने की मांग खारिज होने से इस श्रेणी के कर्मचारियों को राहत नहीं मिल सकी। अदालत के इस निर्णय से पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामलों में कटऑफ तारीख की भूमिका भी स्पष्ट हुई है। हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा के उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया या सेवा की शुरुआत अलग-अलग समय और अलग-अलग आधार पर हुई थी।

फतेहाबाद में स्वाइन फ्लू की दस्तक, गोरखपुर में मिला पहला मामला; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

फतेहाबाद जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। गांव गोरखपुर निवासी एक महिला की एच1-एन1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और संक्रमित महिला के परिजनों तथा उसके संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग शुरू कर दी।

स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर उनकी लगातार निगरानी शुरू की है। टीम ने परिवार और आसपास के लोगों से खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी ली। एहतियात के तौर पर संपर्क में आए लोगों को जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर समय पर उपचार शुरू किया जा सके। जिला महामारी अधिकारी डॉ. विष्णु मित्तल ने बताया कि एच1-एन1 का मामला सामने आने के बाद जिले के सभी नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में विशेष फ्लू कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। यहां फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर जांच और पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर और आपातकालीन सुविधाओं को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

फतेहाबाद में एच1-एन1 जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए अग्रोहा या करनाल भेजे जाएंगे। विभाग के पास नमूने लेने की किट और आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉ. मित्तल के अनुसार, अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के होते हैं और सामान्य उपचार से मरीज ठीक हो जाते हैं। हालांकि बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को संक्रमण से विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, अत्यधिक थकान या सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है।

दिल्ली बसों में सुरक्षा होगी और कड़ी पर्दे-काले शीशों पर रोक का आदेश

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही चलती बस में 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक बसों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बसों में यात्रियों, खासकर महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आठ नए आदेश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत बसों की खिड़कियों पर ऐसे पर्दे लगाने पर रोक लगाई गई है, जिनसे अंदर का दृश्य बाहर से दिखाई न दे।

इसके अलावा बसों में काले या अत्यधिक गहरे शीशों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य बस के अंदर होने वाली गतिविधियों पर निगरानी को आसान बनाना है। निर्देशों में बसों के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति और आपातकालीन व्यवस्था की नियमित जांच पर भी जोर दिया गया है। बस संचालकों और कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बसों में तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है और सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दिल्ली में 1008 व्यंजनों का भोग, नोएडा में 251+ पकवान; जन्माष्टमी पर खास तैयारी

इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी, दिल्ली में मयूर थीम से सजेगा परिसर

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कृष्ण भक्तों के लिए इस्कॉन मंदिरों में इस बार विशेष और भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य उत्सव को भक्ति, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाने की तैयारी है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इस बार खास **मयूर थीम** तैयार की गई है। मंदिर परिसर को मोर के पंखों और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है।

जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण को 1008 तरह के व्यंजनों का भोग लगाने की तैयारी है। भक्तों के लिए विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के समय विशेष आरती और पूजा होगी। नोएडा स्थित इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। यहां भगवान कृष्ण को 251 से अधिक प्रकार के पकवानों का महाभोग अर्पित किया जाएगा। मंदिर परिसर में विशेष सजावट के साथ भक्तों के लिए भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है।

दिल्ली-एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी इस्कॉन और दूसरे कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में झांकियां, फूलों की सजावट और रोशनी की विशेष

व्यवस्था की जा रही है। भक्तों के लिए भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। दिनभर भजन, कीर्तन, पूजा और भगवान कृष्ण की आराधना होगी। शाम के समय मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।

रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और आरती की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में जन्माष्टमी के इन आयोजनों को लेकर भक्तों में खास उत्साह है।

ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटरों की जांच तेज, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जिले में 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इन संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में कई कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। विभाग की जांच के दौरान ऐसे संस्थानों की पहचान की गई, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजकर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत की जा रही है। नियमों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को संचालन से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके अलावा संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और अन्य निर्धारित मानकों का भी पालन करना होता है। विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद संबंधित कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि केवल नोटिस जारी करना ही अंतिम कार्रवाई नहीं होगी। यदि संचालक नियमों का पालन नहीं करते और पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उनके संस्थानों को सील किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें निर्धारित नियमों के दायरे में लाना है।

गाजियाबाद में जमीन खरीदने का सुनहरा मौका, 7 सितंबर को होगी भूखंडों की नीलामी

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बड़ा मौका दिया है। प्राधिकरण ने इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी समेत शहर के प्रमुख रिहायशी क्षेत्रों में 60 से अधिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की है। इच्छुक आवेदक इन भूखंडों के लिए 2 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। जीडीए की इस नीलामी में शहर की कई प्रमुख आवासीय योजनाओं और क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल की गई हैं।

इनमें इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, कोयल एन्क्लेव, कर्पूरीपुरम और ब्रिज विहार जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से नीलामी के लिए अलग-अलग श्रेणियों और आकार के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक खरीदार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जीडीए की योजना का उद्देश्य उपलब्ध संपत्तियों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना होगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है।

पंजीकरण की अंतिम तारीख 2 सितंबर है, इसलिए इच्छुक लोगों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। नीलामी 7 सितंबर को होगी, जिसमें पात्र आवेदक भाग ले सकेंगे। नीलामी में शामिल भूखंडों की कीमत, क्षेत्रफल, आरक्षित मूल्य और अन्य शर्तों की जानकारी जीडीए द्वारा जारी विवरण में उपलब्ध कराई जाएगी। खरीदारों को आवेदन करने से पहले संबंधित संपत्ति और नीलामी की शर्तों की पूरी जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।

नमो भारत की टीम ने जीते यात्रियों के दिल, 500+ लोगों का सामान लौटाया

एजेंसी, नई दिल्ली

नमो भारत केवल तेज और सुविधाजनक सफर का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यात्रियों की मदद और सुरक्षा को लेकर भी लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की टीम ने पिछले एक साल के दौरान 500 से अधिक यात्रियों का खोया या छूटा हुआ सामान सुरक्षित तरीके से उनके मालिकों तक पहुंचाया। इसके अलावा कर्मचारियों ने कई ऐसे यात्रियों की भी मदद की, जो सफर के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए थे। टीम की तत्परता से कई लोगों को उनके परिजनों से दोबारा मिलाया गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी व्यवस्था यात्रियों को प्राथमिकता देने वाली सोच के तहत काम करती है। नमो भारत के स्टेशनों और ट्रेनों में तैनात कर्मचारी यात्रियों की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देते हैं। किसी यात्री का बैग, मोबाइल, दस्तावेज या अन्य सामान

नमो भारत की टीम बनी यात्रियों का सहारा

छूट जाने पर उसे सुरक्षित रखने और पहचान की पुष्टि के बाद संबंधित व्यक्ति को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। खोया सामान मिलने पर यात्री सबसे पहले स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों या सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें सामान से जुड़ी जरूरी जानकारी, जैसे बैग का रंग, आकार, पहचान चिन्ह, उसमें मौजूद वस्तुओं और यात्रा से संबंधित विवरण बताना चाहिए। यदि सामान ट्रेन में छूटा है तो यात्रा का समय और संबंधित स्टेशन की जानकारी भी देना उपयोगी होता है। इससे कर्मचारियों को सामान की पहचान और तलाश करने में आसानी होती है।

नमो भारत की टीम केवल सामान मिलने की शिकायतों पर ही काम नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को अन्य सहायता भी उपलब्ध कराती है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और ऐसे यात्रियों पर ध्यान दिया जाता है, जो किसी कारण से अपने साथ आए लोगों से अलग हो जाते हैं।

30 सितंबर से बदलेंगे नियम, बिल्डरों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी रेरा ने परियोजनाओं की प्रगति और उससे जुड़ी जानकारी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रमोटरों की ओर से दी जाने वाली परियोजना संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ाना और घर खरीदारों को सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही से सभी प्रमोटरों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट यानी क्यूपीआर के साथ आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जमा करने होंगे।

इन प्रमाणपत्रों के जमा होने के बाद ही प्रमोटर क्यूपीआर को पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। अब तक की व्यवस्था में प्रमोटर स्वयं परियोजना की प्रगति से संबंधित आंकड़े दर्ज करते थे और संबंधित पेशेवरों के प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कर देते थे। इससे परियोजना की वास्तविक प्रगति और उपलब्ध कराई गई जानकारी के बीच अंतर की संभावना बनी रहती थी।

नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया गया है। रेरा 2.0 पोर्टल पर लागू नई व्यवस्था के अनुसार अब परियोजना से जुड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने-अपने डिजिटल प्रमाणपत्र सीधे पोर्टल पर जमा करेंगे। इसके बाद इन्हीं प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

इससे प्रमोटरों की ओर से दर्ज की जाने वाली जानकारी पर संबंधित पेशेवरों का सत्यापन भी सुनिश्चित होगा। यूपी रेरा ने इस नई सुविधा को मौजूदा पोर्टल पर सक्रिय कर दिया है। प्रमोटरों को प्रक्रिया समझने और तकनीकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए सहायता की व्यवस्था भी की जा रही है।

मेरठ में नकली रीपैकिंग रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाएं बरामद

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर करीब एक करोड़ रुपये कीमत की एक्सपायर्ड दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में चार सगे भाइयों असलम, सद्दाम, अकरम और अशरफ को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चारों भाई एक्सपायर्ड दवाइयों और सौंदर्य उत्पादों को नए रैपर और लेबल लगाकर दोबारा पैक करते थे और फिर उन्हें बाजार में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दवा कंपनियों के डिपो से एक्सपायर्ड दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदकर मेरठ स्थित गोदाम में लाते थे। यहां स्कैनर और अन्य मशीनों की मदद से नकली लेबल तैयार किए जाते थे। इसके बाद उत्पादों की रीपैकिंग कर उन्हें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के बाजारों में सप्लाई किया जाता था।

आगरा में महावीर नाले पर बनी सात अवैध और जर्जर दुकानें ध्वस्त

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा के सुभाष बाजार क्षेत्र में महावीर नाले पर बनी अवैध और जर्जर दुकानों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को नगर निगम की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल और पोकलेन-जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सात दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बताया गया कि महावीर नाले पर लंबे समय से कई दुकानें अवैध तरीके से बनी हुई थीं। इनमें कुछ दुकानें काफी जर्जर हालत में थीं, जिससे आसपास आने-जाने वाले लोगों और दुकानदारों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था।

नगर निगम की ओर से दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर सुरक्षा संबंधी चेतावनी दी गई थी। इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में 8 जुलाई को हुई एक दर्दनाक घटना भी रही। महावीर नाले पर बनी एक जर्जर दुकान अचानक गिर गई थी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्र में स्थित अन्य जर्जर और असुरक्षित निर्माणों को लेकर गंभीरता दिखाई और संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए। नगर निगम की टीम ने बुधवार को पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया।

मशीनों की मदद से चिन्हित दुकानों को एक-एक कर गिराया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। नाले पर बने अवैध निर्माणों के कारण नाले की सफाई और जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।

फर्जी डीड दिखाकर लिया करोड़ों का लोन, पांच आरोपी पुलिस के रडार पर

दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों का बड़ा खेल, 1.06 करोड़ के कर्ज घोटाले का खुलासा

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक के लोन घोटाले का मामला सामने आया है। मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (ष्ठष्ठ) के फर्जी कन्वेयंस डीड यानी स्वामित्व दस्तावेज तैयार कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से 1.06 करोड़ रुपये से अधिक का लोन हासिल करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर ष्ठष्ठ से संबंधित संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें असली बताकर वित्तीय संस्था के सामने पेश किया। इन दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की वैधता और स्वामित्व का भरोसा दिलाकर लोन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद कंपनी से बड़ी रकम लोन के रूप में प्राप्त कर ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ, जब लोन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान संबंधित संपत्ति के कागजात पर संदेह पैदा हुआ। सत्यापन में कथित तौर पर सामने आया कि पेश की गई कन्वेयंस डीड वास्तविक नहीं थी। इसके बाद वित्तीय कंपनी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान पांच लोगों की कथित भूमिका सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर कैसे किया गया और लोन की रकम हासिल करने के लिए आरोपियों ने किस तरह की योजना बनाई।

जांच एजेंसियां आरोपियों के बीच संबंध, बैंकिंग लेनदेन और लोन की रकम के इस्तेमाल की भी पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस कथित धोखाधड़ी में कोई अन्य व्यक्ति या संस्था शामिल थी या नहीं। अधिकारियों के मुताबिक,

नकली डीड दिखाकर करोड़ों का कर्ज लिया

दस्तावेजों की सत्यता की जांच और संबंधित रिकॉर्ड का मिलान मामले की जांच का अहम हिस्सा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। यह मामला सामने आने के बाद फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय संस्थानों से बड़े लोन हासिल करने वाले गिरोहों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है।

मामले में पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने से लेकर लोन की रकम हासिल करने तक की पूरी कड़ी खंगाल रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों के बैंक खातों, संपत्ति रिकॉर्ड और आपसी संपर्कों की जांच कर रही हैं। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में किसी संगठित गिरोह की भूमिका भी हो सकती है। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और लेनदेन की भी जांच कर रही है। साथ ही फर्जी डीड तैयार करने वाले लोगों की तलाश जारी है। जांच में अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

रेवाड़ी में प्लेटफॉर्म-5 पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, सांस लेने तक में हुई दिक्कत

एजेंसी, नई दिल्ली

रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्लेटफार्म नंबर-4 और 5 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा होने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। त्योहारों के चलते पहले से ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक थी। इसी बीच प्लेटफार्म नंबर-2 पर आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर-5 पर डायवर्ट किए जाने की सूचना से स्थिति और गंभीर हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस और आला हजरत एक्सप्रेस के यात्रियों के एक साथ प्लेटफार्म नंबर-5 पर पहुंचने से वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई यात्रियों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्लेटफार्म पर यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक प्लेटफार्म बदलने की वजह से बड़ी संख्या में यात्री सामान लेकर प्लेटफार्म नंबर-5 की ओर दौड़ पड़े। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी हुई।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा एयरपोर्ट पर बनेगा जीटीसी, एक ही जगह मिलेंगे मेट्रो से पॉड टैक्सी तक विकल्प

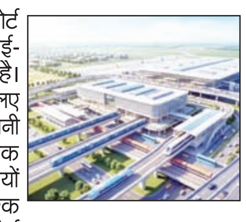

एजेंसी, नई दिल्ली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भविष्य में सड़क, मेट्रो, नमो भारत और हाई-स्पीड रेल से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर यानी जीटीसी विकसित किया जा रहा है। यह एक मल्टी-मॉडल परिवहन केंद्र होगा, जहां यात्रियों को अलग-अलग परिवहन साधनों की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। जीटीसी के जरिए एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को मेट्रो, बस, नमो भारत, हाई-स्पीड रेल और पॉड टैक्सी जैसे विकल्प उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आसानी से एक परिवहन माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना और यात्रा का समय कम करना है। केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां एयरपोर्ट को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन के एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने पर काम कर रही हैं। इससे जेवर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और भविष्य में बढ़ने वाले यात्रियों की आवाजाही को भी सुगम बनाया जा सकेगा।

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मौतों का आंकड़ा 14 पहुंचा

एजेंसी, दिल्ली। प्रयागराज-कौशांबी सीमा से सटे चिल्ला शहबाजी गांव में सोमवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बुधवार सुबह 16 वर्षीय उर्वशी ने स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुई थी। घटना के दिन सोमवार को 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को दो और घायलों ने दम तोड़ दिया था। बुधवार को उर्वशी की मौत के बाद हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 14 पहुंच गई। हादसे में घायल तीन लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। हादसे के बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों के परिजन भी मलबे में दबे अपने जरूरी और कीमती सामान की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और अवैध पटाखा फैक्ट्री से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

आगरा में आज भारी बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

एजेंसी, दिल्ली। आगरा में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और बादल छाने के साथ हवा चलने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। आगरा भी बारिश की चेतावनी वाले जिलों में शामिल है। बारिश के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम सुहावना रहने के साथ कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं।

फरीदाबाद में नकली एशियन पेंट्स का भंडाफोड़, 233 बाल्टियां बरामद

एजेंसी, दिल्ली। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में नकली एशियन पेंट्स की बिक्री और सप्लाई का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने एक दुकान से एशियन पेंट्स के नाम पर भरी हुई 79 बाल्टियां बरामद कीं। वहीं, दूसरी दुकान से 154 खाली बाल्टियां और उनके ढक्कन मिले। पुलिस के अनुसार, बरामद सामान का इस्तेमाल कथित तौर पर नकली पेंट तैयार कर उसे नामी ब्रांड के नाम से बाजार में बेचने और सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में नकली उत्पादों की बिक्री को लेकर हड़कंप मच गया। पुलिस अब बरामद पेंट और पैकिंग सामग्री की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नकली पेंट कहां तैयार किया जाता था और इसे किन-किन इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने लोगों से पेंट खरीदते समय पैकिंग, लेबल और विक्रेता की विश्वसनीयता जांचने की अपील की है।

सोनीपत में प्रेम विवाह करने वाले दंपती की संदिग्ध मौत, पति फंदे से मिला

एजेंसी, नई दिल्ली। सोनीपत में दो साल पहले प्रेम विवाह करने वाले ऋतिक और सिमरन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव उनके घर से बरामद हुए। जानकारी के अनुसार, ऋतिक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि सिमरन का शव बेड के पास फर्श पर पड़ा था। उसके गले में भी फंदा लगा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस दोनों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ऋतिक और सिमरन ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह किया था और दोनों साथ रह रहे थे। अचानक दोनों के शव मिलने से परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करेगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

स्वाइन फ्लू की रफ्तार तेज, दिल्ली में अब तक 3218 संक्रमण

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक राजधानी में स्वाइन फ्लू के 3218 मामले सामने आ चुके हैं। यह वर्ष 2019 के बाद दिल्ली में दर्ज हुआ संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगस्त के दूसरे पखवाड़े में संक्रमण की रफ्तार और तेज हुई। अकेले 31 अगस्त को 164 नए मामले सामने आए। लगातार बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

न्यूज ब्रीफ

हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में विवाद के दौरान चली गोली, आरोपी फरार

अनिल थपलियाल। हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में मंगलवार को दो कर्मचारियों के बीच विवाद के दौरान कथित तौर पर फायरिंग हो गई। गोली कार्यालय में रखी एक अलमारी में जा लगी। गोली चलने की आवाज से परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आरोपी कर्मचारी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस फायरिंग की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त बने दीपेंद्र चौधरी

अनिल थपलियाल। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में दीपेंद्र चौधरी को उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पारदर्शिता, निष्पक्षता और निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। चौधरी ने भी समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई।

एंडोकॉन 2026 में ग्राफिक एरा अस्पताल की तकनीक को प्रथम पुरस्कार

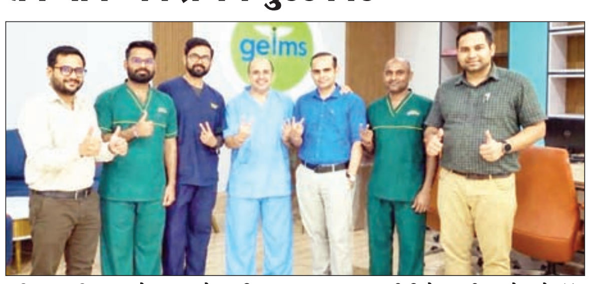

अनिल थपलियाल। देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल की विशेषज्ञ टीम को एंडोकॉन 2026 में अभिनव उपचार तकनीक के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। डॉक्टरों ने एक बुजुर्ग महिला की आहार नली में हुए जटिल छेद को बिना बड़ी सर्जरी के सफलतापूर्वक बंद किया। इस छेद के कारण आहार नली से छाती और फेफड़ों की ओर असामान्य रास्ता बन गया था, जिससे मरीज को खाने और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। विशेषज्ञों ने आमतौर पर ह्रदय के छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एएसडी क्लोजर उपकरण का अभिनव उपयोग किया। इस उपचार को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित चिकित्सा कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया, जहां विशेषज्ञों ने इसे देश का सर्वश्रेष्ठ केस मानते हुए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान ग्राफिक एरा अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा तकनीक और जटिल मामलों के अभिनव उपचार की विशेषज्ञता को राष्ट्रीय पहचान देता है।

भारतीय राजनयिकों ने हाउस ऑफ हिमालयाज़ आउटलेट का किया दौरा

अनिल थपलियाल। देहरादून स्थित हाउस ऑफ हिमालयाज के फ्लैगशिप आउटलेट का वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में जाम्बिया में उच्चायुक्त आलोक रंजन झा, लिथुआनिया में राजदूत देवेश उत्तम और जमैका में उच्चायुक्त मयंक जोशी शामिल रहे। यह दौरा विदेश मंत्रालय के मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हुआ। राजनयिकों ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, उत्कृष्ट गुणवत्ता, डिजाइन और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के विशेष उपहार हैम्पर तैयार कराने में रुचि दिखाई। यह पहल उत्तराखंड के स्थानीय शिल्प, ग्रामीण उद्यमिता और प्राकृतिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उत्तराखंड के 15 सदस्यीय मीडिया दल ने आईसीएमआर-एनआईएन का किया दौरा

अनिल थपलियाल। हैदराबाद प्रेस दौरे के दूसरे दिन उत्तराखंड के 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान का दौरा किया। संस्थान की निदेशक डॉ. भारती कुलकर्णी ने खाद्य संरचना, पोषक तत्वों की आवश्यकता और स्वस्थ आहार संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों में कम उम्र से ही स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और कोदा जैसे स्थानीय मोटे अनाजों के पोषक तत्वों पर शोध जारी है। रागी के सेवन से एनीमिया में कमी पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, अधिक वजन और मोटापे को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां बताया। मीडिया प्रतिनिधियों ने संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कर खाद्य विश्लेषण और लिपिड रसायन विज्ञान में चल रहे अनुसंधान कार्यों की जानकारी ली। तकनीकी सत्र में मीडिया की भूमिका और प्रमाण आधारित पोषण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने सालार जंग संग्रहालय का दौरा कर हैदराबाद की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और संग्रहालय में संरक्षित महत्वपूर्ण संग्रहों की जानकारी प्राप्त की।

उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

रोपवे परियोजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, नियम और विनियम जल्द जारी करने के दिए निर्देश

अनिल थपलियाल

देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी पर्यटन और यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

रोपवे नियमावली जल्द जारी होगी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश।

बैठक में मुख्य सचिव ने ब्रिडकुल को प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और नियमन के लिए रोपवे रेग्यूलेशन और रूल्स जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं से जुड़े लंबित प्रक्रियात्मक, भूमि संबंधी और आपसी समन्वय के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

मुख्य सचिव ने सभी रोपवे परियोजनाओं में पार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रोपवे के निर्माण के साथ यात्रियों और पर्यटकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा विकसित करना आवश्यक है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित एजेंसियों को आगामी कार्यवाही में तेजी लाने को कहा। जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए गए। इससे भूमि, निर्माण और अन्य प्रशासनिक मामलों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।

नैनीताल की रोपवे परियोजनाओं में तालमेल पर जोर

नैनीताल क्षेत्र की महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। रानीबाग-ज्योलीकोट-हनुमानगढ़ी-कैंचीधाम और रानीबाग-भीमताल-भवाली परियोजनाओं में एनएचएलएमएल और यूकेएमआरसी के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने को कहा गया।

धार्मिक स्थलों तक आसान होगी पहुंच

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में रोपवे को सुगम और सुरक्षित परिवहन के साथ पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के साथ इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव विनीत कुमार, एनएचएलएमएल और यूकेएमआरसी के अधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।

मसूरी की धरती ने देखा उत्तराखंड आंदोलन का संघर्ष और बलिदान : धामी

मसूरी गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने किया नमन

अनिल थपलियाल

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी के शहीद स्थल झूलाघर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान के कारण ही अलग उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हो सका। उन्होंने कहा कि मसूरी की धरती राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की गवाह रही है। वर्ष 1994 में खटीमा गोलीकांड के विरोध में यहां हजारों आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान प्रत्येक उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में हमेशा अमर रहेगा। नई पीढ़ी को राज्य निर्माण के संघर्ष और आंदोलनकारियों के योगदान से परिचित कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।

◆ शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान हर उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में रहेगा अमर: धामी

धामी ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके दायरे में चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी शामिल किया गया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन सात हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन 5500 रुपये प्रतिमाह की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के साथ विकास को गति देने के लिए काम कर रही है।

देहरादून की नहरों पर मंडरा रहा खतरा

चंद्रबनी में नहर में डूबा 11 वर्षीय सम्राट

एसडीआरएफ के रेस्क्यू के बाद मिला शव

विकास बलोनी

देहरादून। देहरादून के चंद्रबनी स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया परिसर में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गोपी जीवी के 11 वर्षीय बेटे सम्राट की पास की नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि सम्राट घर के बाहर खेल रहा था, इसी दौरान वह अचानक नहर में जा गिरा। लगातार बारिश के कारण नहर का जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ था और पानी का बहाव बेहद तेज था। देखते ही देखते मासूम तेज धारा की चपेट में आकर बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। काफी तलाश के बाद बच्चे को बोड़ीवाला क्षेत्र से बरामद किया गया।

◆ वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट परिसर में खेल रहा था मासूम, अचानक नहर में गिरने से गई जान

इस हादसे ने बरसात के दौरान खुले नालों, नहरों और जलधाराओं के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बारिश के दौरान जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ने से ऐसी जगहें बेहद खतरनाक हो जाती हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी, नहर और बरसाती नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की जाती रही है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और क्षेत्र में भी शोक की लहर है। यह हादसा अभिभावकों और स्थानीय प्रशासन के लिए बरसात के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी है।

टनकपुर में खेल महाकुंभ का भव्य आगाज, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

मुख्यमंत्री धामी ने मशाल सौंपकर किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ

अनिल थपलियाल

चंपावत में टनकपुर के स्व. कैलाश चंद्र गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ-2026 और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी गहना महर को मशाल सौंपकर खेलों का औपचारिक आगाज किया। खिलाड़ियों ने योगासन और पारंपरिक खेल मुर्गा झपट की प्रस्तुति दी तथा खेल भावना की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को मजबूत खेलभूमि के रूप में विकसित करने और युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को एक लाख रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ओवरऑल चैंपियन टीम को मुख्यमंत्री ट्रॉफी के साथ पांच लाख रुपये मिलेंगे। इस बार आधुनिक खेलों के साथ मुर्गा झपट, पिट्ठू, मल्लखम्ब, कंचा और रस्साकस्सी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिताएं चार चरणों में होंगी। न्याय पंचायत स्तर पर एक से 10 सितंबर, विधानसभा स्तर पर 11 से 20 सितंबर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर 21 से 30 सितंबर और राज्य स्तर पर 10 से 30 अक्टूबर तक मुकाबले होंगे। महिला और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी विशेष स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।

गरमपानी-खैरना में शिप्रा नदी उफनी, पहाड़ियों से पत्थर गिरने से बढ़ा खतरा

उत्तराखंड में बारिश से उफान पर शिप्रा नदी

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नैनीताल जिले के कैंची धाम, रातीघाट और गरमपानी-खैरना क्षेत्र में शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। मंगलवार को नदी का बहाव कई गुना तेज होने से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। नदी के रौद्र रूप को देखकर स्थानीय लोगों को वर्ष 2021 की भीषण आपदा की याद आ गई। कई लोग अपने घरों की छतों से नदी के बहाव पर नजर रखते रहे। तेज बहाव के बीच बोल्डरों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों से टकराने की आवाज ने भी लोगों की चिंता बढ़ाई।

उत्तराखंड

कैंची धाम में उफान पर आई शिप्रा नदी

शिप्रा के तेज बहाव से याद आई वर्ष 2021 की आपदा।

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी। श्री कैंची धाम तहसील के तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी ने रातीघाट पहुंचकर नदी के नजदीक रह रहे एक परिवार को दूसरे सुरक्षित भवन में स्थानांतरित कराया। वहीं गरमपानी-खैरना बाजार क्षेत्र में मुनादी कराकर पहले से चिह्नित दस परिवारों को जीआइसी खैरना में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचने के निर्देश दिए गए। स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

हालांकि शिप्रा नदी का बहाव काफी तेज रहा लेकिन आश्रम परिसर के आसपास किए गए मजबूत बाढ़ सुरक्षा कार्यों के कारण किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। नदी के किनारे रखी निर्माण सामग्री जरूर तेज बहाव में बह गई। इसके अलावा गरमपानी स्थित देवी मंदिर और खैरना बाजार क्षेत्र में पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण भी खतरा बढ़ गया। कुछ लोग पत्थरों की चपेट में आने से बाल-बाल बचे।

बुधवार को बारिश की तीव्रता कम होने के बाद नदी का जलस्तर भी घटने लगा। इससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। प्रशासन लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी तथा बरसाती नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की गई है।

डीएवी कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन

अनिल थपलियाल। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में व्यवस्थाओं में सुधार और कॉलेज को उत्तराखंड सरकार के अधीन लाने की मांग को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्र-छात्राओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज परिसर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मुख्य मार्ग तक पहुंच गया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर पुतला रखकर विरोध जताया, जिससे कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। छात्र नेताओं का आरोप है कि कॉलेज की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था अभी भी कानपुर स्थित डीएवी प्रबंधन के अधीन है। उन्होंने इसे छात्रों के हितों के खिलाफ बताया। एबीवीपी ने मूलभूत सुविधाओं, शैक्षणिक सुधार और पारदर्शी प्रशासन की मांग उठाई। छात्र नेता रोहित सिंह ने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

इस्कॉन देहरादून में भव्य वातावरण में मनाई जाएगी जन्माष्टमी

अनिल थपलियाल। देहरादून के मोथरोवाला स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भव्य आध्यात्मिक वातावरण में मनाई जाएगी। मंदिर विशेष रूप से सजाया जाएगा और राधा बांके बिहारी जी के फूल बंगला दर्शन आकर्षण रहेंगे। दिनभर पूजा, जप, श्रीमद्भागवत कथा, भक्ति गीत, नृत्य और कृष्ण लीलाओं पर आधारित झांकियां होंगी। रात में भगवान श्रीकृष्ण को 1008 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे। मध्यरात्रि में विशेष जन्म महाआरती होगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। यातायात सुविधा के लिए पांच स्थानों पर पार्किंग और निशुल्क ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध रहेगी।

पंखुड़ी पाठक ने प्रीतम सिंह से की मुलाकात कांग्रेस के मीडिया अभियान पर हुई चर्चा

अनिल थपलियाल

देहरादून। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी का मीडिया अभियान तेज होने लगा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड की मीडिया प्रभारी नियुक्त की गई पंखुड़ी पाठक ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के मीडिया और संचार अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पंखुड़ी पाठक ने प्रीतम सिंह से चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन भी लिया।

इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के दोनों सहप्रभारियों सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव से भी मुलाकात की। बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, चुनावी रणनीति और पार्टी के जनसरोकारों को मीडिया के माध्यम से प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया गया। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के दौरान संगठन और संचार तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

यात्रा पहले चरण में 67 हजार श्रद्धालुओं ने लिया था हेली सेवा का लाभ

केदारनाथ हेली सेवा 15 सितंबर से होगी शुरू

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा 15 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए पहली टिकट बुकिंग खिड़की सात सितंबर से खोलने की तैयारी है। इससे यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने में सुविधा मिलेगी।

दूसरे चरण में टिकट बुकिंग की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसके तहत टिकट एक साथ लंबे समय के लिए जारी करने के बजाय 15-15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा संचालकों के साथ आवश्यक बैठकें पूरी कर ली हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और मौसम विभाग के साथ भी लगातार समन्वय किया जा रहा है।

प्राधिकरण के अनुसार हेली सेवा का संचालन मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से निर्धारित अनुमति भी आवश्यक होगी। खराब मौसम या अन्य सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में उड़ानों को रोकने या उनमें बदलाव करने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले मौसम और उड़ान संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं से हेली टिकट केवल अधिकृत माध्यमों से ही बुक करने की अपील की है। केदारनाथ शटल सेवा के लिए निर्धारित अधिकृत वेबसाइट का उपयोग करने को कहा गया है। साथ ही बद्रीनाथ शटल सेवा के लिए भी निर्धारित माध्यम से ही टिकट लेने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं को अनधिकृत एजेंटों और बिचौलियों से टिकट खरीदने से बचने को कहा गया है, ताकि ठगी और कालाबाजारी से बचा जा सके।

विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खोलेगा आईएचएम-आईआईएम का सहयोग

अनिल थपलियाल

देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और आईआईएम सिरमौर के बीच आतिथ्य एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, कार्यकारी विकास, संकाय विकास, विद्यार्थी इमर्शन, अनुसंधान तथा ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करेंगे। आईएचएम देहरादून के विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रबंधन पद्धतियों पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी विकसित किया जाएगा। इसमें नेतृत्व, विपणन, वित्त, उद्यमिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक विषय शामिल होंगे।

आईएचएम में आतिथ्य उद्यमिता विकास के लिए संयुक्त इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। केंद्र के माध्यम से इच्छुक विद्यार्थियों और उद्यमियों को व्यवसाय योजना, बाजार विश्लेषण, प्रशिक्षण तथा उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। आईआईएम सिरमौर के निदेशक प्रो. प्रफुल्ला वाई. अग्निहोत्री ने कहा कि सेवा क्षेत्र की बदलती जरूरतों को देखते हुए आधुनिक प्रबंधन क्षमताओं के साथ आतिथ्य कौशल को जोड़ना जरूरी है। आईएचएम देहरादून के प्रधानाचार्य डॉ. शिव मोहन ने विश्वास जताया कि यह साझेदारी विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा करेगी।

न्यूज ब्रीफ

ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (जॉब ट्रेनी) के 236 पदों को पोस्ट कोड-26008 के अंतर्गत भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (जॉब ट्रेनी) के 236 पदों के लिए 202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 184 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण 160 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है जोकि 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसका शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी सूचना दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड कॉपी और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

रेडियोग्राफर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) के 58 पदों को पोस्ट कोड-26009 के अंतर्गत भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) के 58 पदों के लिए 337 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 302 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण 105 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है जोकि 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसका शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी सूचना दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड कॉपी और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

शिवरात्रि मेला में देवी-देवता के बैठने को बनेंगे विशेष स्थान : विधायक

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। वल्लभ राजकीय डिग्री कॉलेज, मंडी में मौजूदा परिसर के विकास (लैंडस्केपिंग, रैंप और बायो इंजीनियरिंग कार्यों के साथ-साथ वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट) के कार्यों का शिलान्यास किया गया है, जिस के तहत अब महाविद्यालय के दोनों भवनों के मध्य बचे हुए खाली स्थान को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि उक्त स्थान का उपयोग विद्यार्थियों के बैठने और अन्य गतिविधियों के उपयोग में लाया जा सके। विधायक ने लोक निर्माण विभाग को इसका प्रारूप तैयार करती बार विशेष तौर निर्देश दिए गए थे कि इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाए, ताकि शिवरात्रि मेले के दौरान देवी-देवताओं को एक सुंदर,साफ और सुव्यवस्थित स्थान विराजने के लिए उपलब्ध हो। इस कार्य के लिए स्वयं विधायक के अथक प्रयासों से सरकार द्वारा 6,54,93,000/- रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 1,00,00,000 रुपए की व्यय स्वीकृति प्रदान की गई। जल्द ही इस कार्य की टेंडर प्रकिया शुरू की जाएगी। उन्होंने जल्द ही इसके कार्य शुरू होने की पुष्टि की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि आगामी शिवरात्रि तक ये कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

भारी बारिश से बिलासपुर में करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान, राहत कार्य तेज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिले में गत दिवस हुई भारी वर्षा से विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डीसी राहुल कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक करीब 2.70 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 31 लाख और विद्युत विभाग को लगभग 63 लाख रुपए की क्षति हुई है। बारिश से 11 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं, जबकि छह सड़क मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गए थे। इनमें गंगलोह-मलरौन, ढोलरा चकनाड़-गाह, स्वारघाट-मंझेड-मतनोह समेत अन्य मार्ग शामिल हैं। प्रशासन के प्रयासों से सभी मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी वर्षा से सात रिहायशी भवन और तीन गौशालाएं भी प्रभावित हुई हैं। एक कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार फौरी राहत और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

शाहपुर के रैत ब्लॉक के निर्वाचित बीडीसी सदस्यों की शपथ में देरी पर भाजयुमो ने उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत ब्लॉक में निर्वाचित पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्यों की शपथ में हो रही देरी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सवाल उठाते हुए प्रशासन से जल्द शपथ करवाने की मांग की है। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 79 के तहत पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान तथा आगे की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान है। ऐसे में शपथ में देरी का कारण प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि 'आखिर शपथ में देरी की वजह क्या है? कहीं किसी राजनीतिक दबाव या राजनीतिक स्वार्थ के कारण तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित तो नहीं किया जा रहा' यदि कोई कानूनी, प्रशासनिक या तकनीकी कारण है तो उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीडीसी सदस्य जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं विकास कार्यों को पंचायत समिति के माध्यम से उठाने की जिम्मेदारी मिली है। जनता के मत से चुने गए प्रतिनिधियों को समय पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलना चाहिए।

प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित, 150 सड़कें बंद

बारिश ने बिगाड़ी बिजली-पानी की व्यवस्था, 374 ट्रांसफार्मर और 40 पेयजल योजनाएं प्रभावित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक व्यापक बारिश हुई। कई जगह नदी-नाले उफान पर हैं और भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह तक प्रदेश में 150 सड़कें अवरुद्ध, 374 बिजली ट्रांसफार्मर बंद और 40 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं। मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 78 सड़कें बंद हैं।

बारिश का असर सड़क यातायात, बिजली और पेयजल आपूर्ति पर साफ दिखाई दे रहा है। मंडी में 78 सड़कें बंद हैं। शिमला जिले में 30, कुल्लू में 12, चंबा में आठ, कांगड़ा में सात, सिरमौर में छह, ऊना और सोलन में चार-चार तथा लाहौल-स्पीति में एक सड़क अवरुद्ध है। बिजली आपूर्ति की स्थिति भी कई इलाकों में प्रभावित हुई है। शिमला जिले के रामपुर और चौपाल में 84, कुल्लू के आनी और निरमंड में 81, चंबा में 35, किन्नौर के निचार में 34 और सिरमौर के नाहन में 10 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। पेयजल योजनाओं में हमीरपुर की 23 और शिमला जिले की 17 योजनाएं प्रभावित हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 से 8 सितंबर के बीच किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि इन दिनों भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 और 5 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 6 से 8 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। यानी चेतावनी नहीं है, पर मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद भी नहीं है। बारिश का असर कालका-शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर भी पड़ा है। सोलन जिले में एक पुल के नीचे से मिट्टी धंसने के बाद इस रेल मार्ग पर सेवा पिछले तीन दिन से बंद है। रेलवे ने 13 सितंबर तक इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। बुधवार को भी इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं हुई।

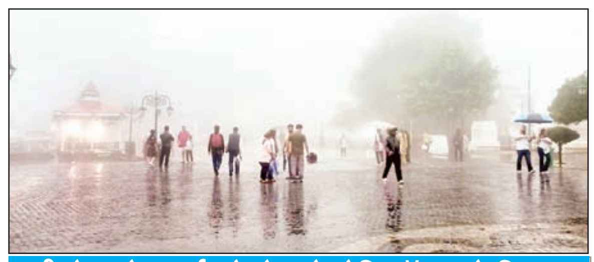

नदी में फंसे बुजुर्ग को सेना के हेलिकॉप्टर से निकाला

सिरमौर जिले के नाहन विकास खंड की बर्मा पापड़ी पंचायत में मंगलवार शाम रूण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक बुजुर्ग कई घंटों तक तेज बहाव के बीच फंसा रहा। जमीन के रास्ते उस तक पहुंचना मुश्किल होने के बाद वायुसेना के हेलिकॉप्टर की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय स्तर पर उसकी पहचान बनवारी दास के रूप में बताई गई है। रेस्क्यू अभियान के दौरान बुजुर्ग को बचाने के लिए नदी में उतरा एक अन्य व्यक्ति भी तेज बहाव में फंस गया। उसके बचाव के लिए भी प्रशासन की रेस्क्यू टीम और वायुसेना के हेलिकॉप्टर को लगाया गया। मौके पर एसडीएम नाहन राजीव संख्यान सहित प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौजूद रहीं। तेज बहाव और कम रोशनी के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें आईं।

रामपुर में अस्थायी पुल बहा

शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 15/20 क्षेत्र में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। गानवी खड्ड पर बनाया गया अस्थाई पुल तेज बहाव में बह गया। इससे गानवी, कूट और क्याओ पंचायतों का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। जघोरी पंचायत में भी यातायात प्रभावित हुआ। कूट खड्ड में पानी बढ़ने से सुर गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल भी बह गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में भी भारी बारिश के बाद पालीगाड़-कोट के नजदीक और फेडल नाला सड़क के पास कई जगह भूस्खलन हुआ। इससे नेशनल हाईवे-305 बंद हो गया। सड़क बहाली के लिए मशीनरी मौके पर भेजी गई है। हाईवे बंद होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।

30 तक बनवाएं हिमकेयर कार्ड

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर परिवार को पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। हिमकेयर के तहत स्मार्ट कार्ड लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफे या आवेदक स्वयं www.hpsbys.in वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, लिखित वचनपत्र और श्रेणी प्रमाणपत्र अपलोड करने के साथ निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर ने बताया कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आधार पर प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया कि अब नए कार्ड का पंजीकरण वर्ष में केवल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में ही किया जाएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक नए कार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा कार्ड का नवीनीकरण भी 30 सितंबर, 2026 तक करवाया जा सकता है। इन कार्डों की वैधता एक वर्ष के लिए होगी।

दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर उठाई आवाज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर अधिवक्ता लग्नेश कुमार, अध्यक्ष 'सामर्थ्य हमारी पहचान' तथा जिला दिव्यांग कल्याण संघ के प्रधान विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता की।

उन्होंने प्रदेश सरकार से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने और राज्य दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की। अधिवक्ता लग्नेश कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक स्टेट दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 79 के तहत राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बोर्ड की कमेटी में अनुभवी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही कमेटी में कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधित्व दिव्यांगजनों का होना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याओं और अधिकारों को प्रभावी तरीके से उठा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्यांगजनों से संबंधित बैठकों और निर्णयों में कई बार भेदभाव देखने को मिलता है। बिलासपुर में दुकानों के आवंटन का मामला उठाते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी और नगर परिषद की करीब 277 दुकानें हैं, लेकिन इनमें से केवल एक दुकान दिव्यांग व्यक्ति को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि डीसी बिलासपुर की ओर से पहले निर्देश दिए गए थे कि कुल दुकानों में से कम से कम पांच प्रतिशत दुकानें दिव्यांगजनों को आवंटित की जाएं। इसके बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। लग्नेश कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार विभाग ही यदि उनकी समस्याओं की अनदेखी करेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से राज्य दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड गठित करने, बिलासपुर में पांच प्रतिशत दुकानें दिव्यांगजनों को आवंटित करने और अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में उचित अवसर और प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए।

एनआईटी हमीरपुर में 9 से 11 अक्टूबर तक होगा शिक्षा महाकुंभ-2026

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में 9 से 11 अक्टूबर 2026 तक शिक्षा महाकुंभ-2026 का आयोजन किया जाएगा। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की इकाई डीएचई, एनआईटी हमीरपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और आईआईटी मंडी के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले आयोजन का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विद्या भारती हिमाचल के पदाधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई विधायकों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन का मुख्य विषय 'शिक्षा, प्रकृति और प्रगति-विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए शिक्षा' रखा गया है। महाकुंभ में देशभर से कुलपति, निदेशक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे।

आईएचएम हमीरपुर के विद्यार्थी प्रियांशु को प्रतिष्ठित एफएचआरएआई उत्कृष्टता पुरस्कार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (आईएचएम) हमीरपुर में बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के 2023-26 के विद्यार्थी प्रियांशु शर्मा को संस्थान के शैक्षणिक टॉपर के रूप में प्रतिष्ठित एफएचआरएआई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

21 से 23 अगस्त तक ताज गंगेज, वाराणसी में आयोजित एफएचआरएआई के 56वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान प्रियांशु शर्मा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रियांशु शर्मा ने अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन, निरंतर मेहनत और समर्पण के आधार पर संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर यह सम्मान हासिल किया है। प्रियांशु शर्मा ने इसके लिए अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा आईएचएम हमीरपुर के समस्त स्टाफ के मार्गदर्शन, सहयोग एवं निरंतर प्रोत्साहन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान में प्राप्त शैक्षणिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उनके व्यक्तित्व और पेशेवर क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमीरपुर के एडीसी एवं आईएचएम हमीरपुर के कार्यकारी प्रधानाचार्य अभिषेक कुमार गर्ग और संस्थान के समस्त अधिकारियों, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने प्रियांशु शर्मा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

घुमारवीं पुलिस की बड़ी कामयाबी, चोरी की बाइक समेत दो आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को चंडीगढ़ के पास बलौंगी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य वाहन चोरी की वारदातों में उनकी संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को थाना घुमारवीं में मोटरसाइकिल नंबर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान कर उनका पीछा किया। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 1 सितंबर 2026 को बलौंगी, चंडीगढ़ के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन शर्मा (20) पुत्र बाबू राम, निवासी गांव भराड़ी, डाकघर कोठी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर तथा सुखजिंदर सिंह (34) पुत्र हरजिंदर सिंह, निवासी गांव खराल खुर्द, डाकघर जोड़ा, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

झंडूता में मारपीट के दो मामले दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता क्षेत्र में मारपीट व विवाद के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पहले मामले में गांव कोठी, डाकघर कोसरियां निवासी रोशन लाल ने अपने भाई मनसा राम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने रास्ता रोककर उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया तथा गाली-गलौच के साथ जान से मारने की धमकी दी। दूसरे मामले में बागडू, भड़ोलीखुर्द निवासी बुजुर्ग निक्की देवी ने अपने बेटे राज कुमार उर्फ राजू के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज करने की शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामलों की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नौकरियां देने के बजाय प्रदेशवासियों को जुए की लत लगवाना चाह रही है सुक्खू सरकार : जयराम

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक धरने पर बैठे और सरकार के फैसले का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी शुरू करने का फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।

जयराम ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहां के लोग इस तरह की प्रवृत्तियों से दूर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार नए-नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया है कि लॉटरी से किसी तरह की आदत नहीं लगेगी और यह केवल भाग्य का खेल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था पर जोर देना चाहिए, जिसमें लोगों को उनकी मेहनत का फल मिले। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों का पैसा एक लॉटरी को केवल भाग्य का खेल बताना समझ से परे है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल पहले ही नशे की समस्या से जूझ रहा है। चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में लॉटरी शुरू होने से लोगों में एक और तरह की लत बढ़ने का खतरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी लॉटरी का दौर रहा है और इसके कारण कई परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा था। उनके अनुसार, कई लोगों ने लॉटरी के चक्कर में अपनी जमीन और घर तक बेच दिए थे, जबकि कुछ लोग कर्ज में डूब गए थे। उन्होंने कहा कि 1999 के बाद हिमाचल इस समस्या से बाहर निकला था और अब सरकार को दोबारा उसी दिशा में नहीं जाना चाहिए। जयराम ने कहा कि व्यक्ति के भाग्य के नाम पर चल जाए, ऐसी व्यवस्था प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार के भांग की खेती को वैध करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने भांग की खेती को वैध करने की बात तो कही है, लेकिन इससे होने वाली आय को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गठित समिति का काम अध्ययन और दौरा करना था। उनके अनुसार समिति ने भांग की खेती को वैध करने की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभी तक सदन में भी इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई है।

शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ 8 सितंबर को एबीवीपी की विशाल रैली

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों और झूठी गारंटियों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। परिषद की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि 8 सितंबर को मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में 3000 से 4000 कार्यकर्ताओं की विशाल रैली निकाली जाएगी।

नैंसी अटल ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार फीस वृद्धि, छात्र संघ चुनाव बहाली और बदहाल शिक्षा व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विद्यार्थियों और युवाओं को सत्र से काफी उम्मीदें थीं, पर सरकार गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले डेढ़ महीने से प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में आंदोलन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ करीब 20 दिनों तक भूख हड़ताल चली, जिसके बाद सरकार को फीस में मामूली कटौती करनी पड़ी, लेकिन वृद्धि पूरी तरह वापस नहीं ली गई। आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन परिषद पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों की हालत पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि एसपीयू मंडी का दायरा लगातार घटाया जा रहा है, नौणी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में लंबे समय से स्थायी कुलपति नहीं है और प्रशासनिक अव्यवस्था चरम पर है। यदि कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आए तो उनके कार्यालय पर ताला लगाकर एक चाबी मुख्यमंत्री और दूसरी राज्यपाल को भेजी जाएगी। एचपीटीयू में भी स्थायी कुलपति, डीन और नियमित स्टाफ का अभाव है। उन्होंने मांग की है कि एचपीटीयू को सेल्फ फाइनेंस से हटाकर एडेड संस्थान बनाया जाए और सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। 8 सितंबर की रैली शिक्षा, फीस वृद्धि, रोजगार, कानून-व्यवस्था, नशा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।

समीक्षा बिलासपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर मंथन

सड़क हादसों पर डीसी सख्त, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनएचएआई सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जिले में कुल 92 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं थीं, जबकि 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 73 सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। वर्ष 2026 में दर्ज दुर्घटनाओं में फोरलेन क्षेत्र में 24, घुमारवीं क्षेत्र में 15 तथा सदर क्षेत्र में 12 दुर्घटनाएं सामने आई हैं। डीसी राहुल कुमार ने एनएचएआई, संबंधित उपमंडल अधिकारियों तथा पुलिस विभाग को जिले में विशेष रूप से फोरलेन पर मुख्य ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किए जाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।

उन्होंने परिवहन विभाग को जिले में अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और आम लोगों को यातायात नियमों तथा सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि फोरलेन क्षेत्र में पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर इस वर्ष अब तक ओवर स्पीड के 63,265 चालान किए गए हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट 13,206, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल के 1,215, बिना सीट बेल्ट 682, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 730 तथा शराब पीकर वाहन चलाने के 179 चालान किए गए हैं। डीसी ने पुलिस विभाग को शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने तथा ओवर स्पीड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के साथ-साथ लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जानी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक पुलिस विभाग द्वारा कुल 90,232 चालान किए गए, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त आरटीओ बिलासपुर द्वारा अब तक 2,255 चालान किए गए हैं न इनमें ओवरलोडिंग, वाहन फिटनेस सहित विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं। बैठक में सड़क दुर्घटना की स्थिति में एंबुलेंस की उपलब्धता, उपयुक्त तैनाती, रिस्पांस टाइम तथा अस्पताल तक पहुंचने और मरीज के हैंडओवर टाइम को लेकर भी चर्चा की गई। डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि दुर्घटना के बाद घायलों को कम से कम समय में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

बिलासपुर में 'मिशन दृष्टि' की शुरुआत, 3 से 8 साल के बच्चों की होगी नेत्र स्क्रीनिंग

◆ **स्क्रीनिंग से उपचार और फॉलो-अप तक पूरी प्रक्रिया की होगी निगरानी**

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिले में 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की पहल 'मिशन दृष्टि बिलासपुर' के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

समिति की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बिलासपुर करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को उपाध्यक्ष तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में जिला कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, डाइट के प्रधानाचार्य-सह-परियोजना निदेशक, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर और एम्स बिलासपुर के नेत्र विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और संबंधित विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से लक्षित आयु वर्ग के बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिशन दृष्टि बिलासपुर के तहत बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं पर एक वर्ष का अध्ययन भी किया जाएगा। स्क्रीनिंग के दौरान एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जिले में बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में बच्चों के नेत्र स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिशन का विधिवत शुभारंभ 1 सितंबर से किया गया है। इसके तहत जिले के प्राथमिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग की जाएगी।

डायना की खूबसूरती के आगे एक्ट्रेस भी फेल

आर्मेनिया। डायना खुबेसेरियन आर्मेनिया की अंतरराष्ट्रीय धाविका हैं, जो मुख्य रूप से स्प्रिंट स्पर्धाओं में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने एथलेटिक्स में अपनी तेज गति और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन से पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आर्मेनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया की राह में बढ़ी चुनौतियां

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले व्यस्त शेड्यूल बना चुनौती

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल होती जा रही है। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर मौजूद टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल है। नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय खिलाड़ियों को रेड-बॉल क्रिकेट की पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा है।

टीम मैनेजमेंट और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के सामने घरेलू क्रिकेट, इंडिया-ए के मुकाबलों और इंटरनेशनल सीरीज के बीच खिलाड़ियों के वर्कलोड और तैयारियों का संतुलन बनाने की चुनौती है।

ईरानी कप और इंडिया-ए मैचों का शेड्यूल टकराया

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए को 22-25 सितंबर और 29 सितंबर-2 अक्तूबर तक दो 4-दिवसीय रेड-बॉल मैच खेलने हैं। वहीं, 1-5 अक्तूबर तक श्रीनगर में ईरानी कप होगा। दोनों टूर्नामेंट के शेड्यूल में क्लैश से टेस्ट दावेदारों को लेकर चयनकर्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। इंडिया-ए में ज्यादा टेस्ट खिलाड़ियों को उतारने पर ईरानी कप की रेस्ट ऑफ इंडिया टीम कमजोर हो सकती है, जबकि खिलाड़ियों को ईरानी कप में भेजने पर उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी का मौका कम मिलेगा।

न्यूजीलैंड दौरे से पहले भी टाइमलाइन टाइट

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्तूबर से 5 मैचों की टी-20 सीरीज के साथ शुरू होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर से इंडिया-ए के तीन 4-दिवसीय मैच होंगे, जिनका शेड्यूल 5 मैचों की वनडे सीरीज से ओवरलैप करेगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिरी वनडे और पहले टेस्ट के बीच सिर्फ 4 दिन का अंतर है। ऐसे में टेस्ट खिलाड़ियों को रेड-बॉल क्रिकेट की पर्याप्त तैयारी का समय मिलना मुश्किल है।

वनडे व टेस्ट के बीच संतुलन की चुनौती

अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों में मुख्य वनडे खिलाड़ियों को ज्यादा मैच खिलाना चाहता है। वहीं, डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस के लिए आगामी टेस्ट सीरीज भी बेहद अहम हैं। इसी वजह से मुख्य टेस्ट खिलाड़ियों को तीसरे वनडे के बाद रिलीज करने की योजना है, ताकि वे टेस्ट की तैयारी कर सकें। कुछ खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से पहले इंडिया-ए के रेड-बॉल मैचों में भी मौका दिया जा सकता है।

जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खिसके

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताजा टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने पिछले हफ्ते बुमराह को पीछे छोड़कर नंबर-1 स्थान हासिल किया था और 872 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर कायम हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी 861 पॉइंट के साथ दूसरे और बुमराह 853 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ऋषभ पंत सातवें और शुभमन गिल नौवें नंबर पर हैं। गिल को दो स्थान का नुकसान हुआ है।

ओली रॉबिन्सन टॉप-5 में पहुंचे

इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन ने 6 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-5 में जगह बनाई है। पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 8 विकेट लेने के बाद उन्हें लगातार दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। इस शानदार प्रदर्शन के बाद रॉबिन्सन 831 रेटिंग पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वे जुलाई 2023 के बाद पहली बार टॉप-5 में लौटे हैं।

टॉप-10 के बाहर भी तेज गेंदबाजों की छलांग

श्रीलंका के असिथा फर्नांडो 4 स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के जोश टंग 4 पायदान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 13वें और पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास 10 स्थान की छलांग के साथ संयुक्त रूप से 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

टेस्ट बल्लेबाजी में ब्रुक नंबर-1

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रुक नंबर-1 पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे और जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस 2 स्थान की बढ़त के साथ टॉप-10 में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के सऊद शकील 15 पायदान चढ़कर 18वें, श्रीलंका के सोनल दिनूषा 29 स्थान की छलांग के साथ 25वें और भारत के देवदत्त पडिक्कल 5 पायदान ऊपर चढ़कर 54वें नंबर पर हैं।

स्पोर्ट्स विंडो

इमाम उल हक की चोट की होगी जांच, आकिब जावेद ने उठाए सवाल

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक की पिंडली की चोट अब जांच के दायरे में आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद ने उनकी चोट की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। इमाम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे। पाकिस्तान को इस मुकाबले में 194 रन से हार का सामना करना पड़ा। आकिब जावेद ने जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद इमाम का दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं करना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि चोट लगना खेल का हिस्सा है, लेकिन इस मामले की परिस्थितियां अलग हैं और इसकी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान ने टीम में बड़े बदलाव किए हैं। सात खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया है, जिनमें इमाम उल हक भी शामिल हैं। इसके अलावा गेंदबाजी कोच उमर गुल और मुख्य कोच सरफराज अहमद को भी पद से हटा दिया गया है।

जन्मदिन पर मोनफिल्स की जीत

एजेंसी, न्यूयॉर्क। फ्रांस के गेल मोनफिल्स ने अपने 40वें जन्मदिन को यादगार बनाते हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। मोनफिल्स ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए एडोल्फो डेनियल वैलेजो को 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 से हराया। इस जीत के साथ मोनफिल्स यूएस ओपन में मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जिमी कॉनर्स का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा, जिन्होंने दो सितंबर 1992 को 40 वर्ष की उम्र में जैमे ओन्सिन्स को हराया था। लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का आभार जताते हुए मोनफिल्स ने कहा कि अपने 40वें जन्मदिन पर खेलना उनके लिए बेहद खास था और प्रशंसकों ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। मोनफिल्स इस साल के अंत में संन्यास लेने की योजना बना रहे हैं। वह यूएस ओपन को भी यादगार बनाना चाहते हैं। वह 2016 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। इस बार उन्होंने पत्नी एलिना स्वितोलिना के साथ मिश्रित युगल में भी हिस्सा लिया और सेमीफाइनल तक पहुंचे।

इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में प्रणय ने अंतिम-16 में बनाई जगह

एजेंसी, जकार्ता। शीर्ष वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय ने बुधवार को एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के अंतिम-16 में जगह बना ली। विश्व के 39वें नंबर के प्रणय ने चीनी ताइपे के लियाओ झुओ-फू को एक घंटे चार मिनट चले मुकाबले में 18-21, 21-15, 21-19 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद प्रणय ने दूसरे गेम में बेहतर खेल दिखाया और मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ लेकिन प्रणय ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। प्रणय को शुरुआती दौर में बाई मिली थी। वह आखिरी बार जुलाई के अंत में ताइपे ओपन में खेले थे, जहां उन्हें अंतिम-16 में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। अंतिम-16 में प्रणय का सामना चीन के शुआन चेन झू से होगा। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अस्मिता चालीहा ने थाईलैंड की पोर्नपिचा चोइकीवोंग को 21-17, 23-21 से हराकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त अनमोल खड़ब ने हांगकांग की लियांग का विंग को 21-17, 21-9 से हराया।

चांदी 2 दिन में 9000, सोना 4500 सस्ता

एजेंसी, मुंबई। सोने-चांदी के दाम में आज यानी 2 सितंबर को फिर गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,855 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए हो गई है। एक किलो चांदी की कीमत आज 2,059 रुपए गिरकर 2.28 लाख रुपए पर आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 2 दिन में ही चांदी करीब 9,000 और सोना 4,500 रुपए सस्ता हो चुका है। कल सोना 2,652 रुपए और चांदी 6,780 रुपए सस्ती हुई थी। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के चलते सोने की कीमत पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत में तेजी के कारण भी सोने और चांदी में गिरावट आई है।

इंग्लैंड दौरे के लिए श्रीलंका की वनडे टीम में शनाका की वापसी

एजेंसी, कोलंबो

श्रीलंका ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी वनडे टीम में पूर्व कप्तान दासुन शनाका को वापस बुलाया है। शनाका जनवरी 2024 के बाद पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट में खेलते नजर आ सकते हैं। उनके अलावा लेग स्पिनर सचिंदु कोलंबगे को भी टीम में शामिल किया गया है।

शनाका और कोलंबगे की वापसी के साथ मिलान रत्नायके और प्रमोद मदुशन को टीम से बाहर कर दिया गया है। श्रीलंका ने जून में वेस्टइंडीज के खिलाफ बारिश से प्रभावित तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-0 से जीती थी। शनाका की वापसी से श्रीलंका के मध्यक्रम को अनुभव मिलेगा। श्रीलंका की नजर अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप में जगह बनाने पर है। शनाका ने अब तक 71 वनडे खेले हैं और इनमें से 43 में श्रीलंका की कप्तानी की है। हालांकि, इस प्रारूप में उनका बल्लेबाजी औसत 22.39 रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए श्रीलंका ने पूर्व कप्तान चरिथ असलंका को भी टीम में वापस बुलाया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम से बाहर रहे असलंका ने लंका प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद वापसी की है। असलंका ने लंका प्रीमियर लीग में 38.50 की औसत व 153.38 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए। उन्होंने चैंपियन गॉल ग्लैडिएटर्स के लिए चार अर्धशतक लगाए। पूरे इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि कुसल मेंडिस कप्तान बने रहेंगे।

इंग्लैंड दौरा 15 से शुरू

श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा 15 सितंबर से शुरू होगा। तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज साउथम्पटन, कार्डिफ और मैनचेस्टर में खेली जाएगी। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज चेस्टर-ले-स्ट्रीट, लीड्स और द ओवल में होगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा।

टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बीसीसीआई की समीक्षा बैठक आज

हेड कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और लक्ष्मण मुंबई बुलाए, 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर होगी चर्चा

एजेंसी, नई दिल्ली

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने समीक्षा बैठक बुलाई है। हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण वीरवार बैठक में शामिल होंगे। यह मीटिंग मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में होगी।

इसमें विदेशी दौरों पर टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खिलाड़ियों की इंजरी, आईपीएल के वर्कलोड और टीम मैनेजमेंट, सीओई और चयन समिति के बीच कम्यूनिकेशन भी बैठक के अहम मुद्दे होंगे।

भारत को जून में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से हार मिली थी। टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह भारत की करीब 3 साल में 16 सीरीज के बाद पहली टी-20 सीरीज हार थी। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भारत 0-4 से हार गया। नॉटिंघम में टीम को 125 रन से हार मिली थी। वनडे सीरीज में भारत ने पहला मैच जीता, लेकिन सीरीज 1-2 से गंवा दी। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने इन नतीजों के बाद टीम के प्रदर्शन की समीक्षा की बात कही थी। अब यह बैठक बुलाई गई है।

चयन समिति को समय पर नहीं मिली थी बुमराह की फिटनेस की जानकारी

बैठक में खिलाड़ियों की इंजरी और सीओई की भूमिका पर भी चर्चा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों, सीओई और सिलेक्शन कमेटी के बीच कम्यूनिकेशन को लेकर सवाल उठे हैं। एक मामले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के फिट नहीं होने की जानकारी चयन समिति को समय पर नहीं मिली थी। वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने और साई सुदर्शन की रिकवरी में उम्मीद से ज्यादा समय लगने पर भी चर्चा होगी।

हार्दिक की फिटनेस भी अहम

बैठक में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस और रिकवरी पर भी चर्चा होगी। चयन समिति 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में देखना चाहती है। फिलहाल हार्दिक वनडे में 5 से 6 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लंबे समय तक बनाए रखने की योजना पर चर्चा करेंगे।

4 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 9 को

आईपीएल के वर्कलोड का खिलाड़ियों की फिटनेस पर असर भी बैठक का अहम मुद्दा होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20आई सीरीज के लिए चुने गए जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, नीतिश रेड्डी और हर्षित राणा की उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर है। चारों खिलाड़ियों का 9 सितंबर को फिटनेस टेस्ट होगा। न्यूजीलैंड दौरे को देखते हुए बीसीसीआई तेज गेंदबाजों के पूल को फिट रखने और खिलाड़ियों के बीच इंजरी की समस्या कम करने के तरीकों पर भी चर्चा करेगा।

फार्मा और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार सुगमता और निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में दोनों देशों के वाणिज्य, उद्योग, सीमा शुल्क, नियामक संस्थाओं और राजनयिक मिशनों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा आंकड़ों के साझा उपयोग में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और कृषि क्षेत्र में नियामक सहयोग बढ़ाने पर विचार किया गया। अफगान व्यापारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने, बैंकिंग एवं वित्तीय सहयोग मजबूत करने और व्यापार संपर्क बेहतर करने के मुद्दे भी बैठक में प्रमुखता से उठे।

क्रेडिट कार्ड बंद कराने में देरी हुई तो मिलेगा मुआवजा

एजेंसी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्ड बंद करने की प्रक्रिया को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। नियमों के मुताबिक यदि ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने का अनुरोध करता है और खाते में कोई बकाया राशि नहीं है तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था को सात कार्य दिवसों के भीतर कार्ड बंद करना होगा। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर बैंक को ग्राहक को प्रत्येक दिन 500 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना पड़ सकता है। यह व्यवस्था उन ग्राहकों के लिए राहत वाली है जिन्हें कार्ड बंद कराने के लिए लंबे समय तक बैंक से संपर्क करना पड़ता है। कई बार बैंक ग्राहक को कार्ड बंद करने से रोकने के लिए दूसरे ऑफर देते हैं या प्रक्रिया में देरी करते हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक अपने अनुरोध का रिकॉर्ड और बैंक से मिली जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कार्ड खाते में बकाया राशि होने पर यह प्रावधान सीधे लागू नहीं होता। इसलिए कार्ड बंद कराने से पहले सभी देनदारियों का भुगतान करना बेहतर है। इसके बाद बैंक से कार्ड बंद करने का अनुरोध दर्ज कराकर उसकी पुष्टि लेना चाहिए। तय समय में कार्ड बंद नहीं होने पर ग्राहक बैंक के शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आरबीआई के संबंधित शिकायत तंत्र में शिकायत दर्ज करा सकता है।

शेयर बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स 373 अंक टूटकर 76570 पर बंद

एजेंसी, मुंबई

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों पर दबाव रहा। कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 373.93 अंक यानी 0.49 प्रतिशत गिरकर 76,570.35 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 141.35 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,914.45 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा। कुल 1827 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जबकि 2323 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 191 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्षेत्रवार कारोबार की बात करें तो ऑटो और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में कमजोरी रही। दूसरी ओर ऊर्जा क्षेत्र के कुछ शेयरों में तेजी देखने को मिली। विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने भी घरेलू बाजार की धारणा प्रभावित की। इस बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर रहा और 94.97 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों की नजर अब वैश्विक बाजारों की दिशा, कच्चे तेल की कीमतों और आगामी आर्थिक संकेतकों पर बनी हुई है।

इस बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर रहा और 94.97 के स्तर पर बंद हुआ।

विश्व बैंक से 1.5 अरब डॉलर की सहायता, भारत ने जताया आभार

एजेंसी, नई दिल्ली

वाशिंगटन में जी-20 बैठकों से इतर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत और विश्व बैंक के संबंधों को केवल वित्तीय सहायता और ऋण तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान शहरी विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने, नगर निकायों के बांड बाजार को मजबूत करने और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। भारत ने विश्व बैंक की ओर से 1.5 अरब डॉलर के विकास नीति वित्तपोषण को तेजी से मंजूरी देने के लिए आभार भी जताया।

नई साझेदारी के तहत कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से जुड़ा ज्ञान केंद्र स्थापित करने पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र विकसित करने और भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश के दौरान राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा देने के उपायों पर भी सहमति बनी।

सुभाष चंद्रा मामले में पांच सदस्यीय पीठ करेगी नए सिरे से सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में एस्सल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 25 अगस्त के अपने पूर्व फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि पिछले आदेश में स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाया था। ऐसे में मामले की सुनवाई अब नए सिरे से की जाएगी। ऋणदाताओं की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद अधिकरण ने सुभाष चंद्रा को अपनी किसी भी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने या हस्तांतरित करने से रोक दिया है। यह कदम ऋणदाताओं और गारंटरों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। मामले में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले केवल 6.5 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान प्रस्ताव को लेकर विवाद है। प्रारंभिक पीठ में मतभेद के बाद मामले को पांच सदस्यीय पीठ के पास भेजा गया था।

अल्ट्राटेक सीमेंट दिसंबर तक लॉजिस्टिक्स बेड़े में जोड़ेगी 600 से ज्यादा ईवी ट्रक

एजेंसी, नई दिल्ली

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट अपने लॉजिस्टिक्स बेड़े को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने दिसंबर 2026 तक अपने परिवहन बेड़े में 600 से अधिक इलेक्ट्रिक ट्रकों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए कंपनी ने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा समझौते किए हैं। इनमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आईपीएलटेक, एनर्जी इन मोशन और सैनी सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

इन इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक क्लिंकर और अन्य सामग्री की ढुलाई में किया जाएगा। कंपनी के अनुसार गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में हर साल लगभग 50 लाख टन सामग्री की ढुलाई इन वाहनों के जरिए की जाएगी। अल्ट्राटेक का मानना है कि इलेक्ट्रिक ट्रकों के बढ़ते इस्तेमाल से परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

अल्ट्राटेक का हरित परिवहन अभियान तेज

कंपनी के मुताबिक 600 से अधिक इलेक्ट्रिक ट्रकों का बेड़ा पूरी तरह संचालित होने पर हर साल 1.17 लाख टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही सालाना करीब 3.9 करोड़ लीटर डीजल की खपत भी कम होगी। कंपनी ने बताया कि वह अपने संयंत्रों के साथ-साथ पूरी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक टिकाऊ बनाने पर ध्यान दे रही है। अल्ट्राटेक ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में सीएनजी ट्रकों का इस्तेमाल शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपने लॉजिस्टिक्स बेड़े में शामिल किया गया। वर्तमान में कंपनी के पर्यावरण अनुकूल बेड़े में 850 से अधिक ट्रक हैं, जिनमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक दोनों वाहन शामिल हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाना उसकी हरित पहल और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अल्ट्राटेक बिक्री मात्रा और उत्पादन क्षमता के आधार पर चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में शामिल है।